सत्यमेव जयते

असंशोधित

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

20 मार्च, 2023

सप्तदश विधान-सभा — सोमवार, तिथि 20 मार्च, 2023 ई0

अष्टम सत्र — 29 फाल्गुन, 1944(शक)

(कार्यवाही प्रारम्भ होने का समय -11.00 बजे पूर्वा0)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारम्भ की जाती है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : अब प्रश्नोत्तर काल होगा ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, तुषार का अपहरण कर हत्या कर दी गई है, बिल्डर से 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई और कई अपहरण हुए हैं । महोदय, सरकार को इस पर जवाब देना चाहिए । अध्यक्ष महोदय, अपहरण उद्योग फिर से लौट गया है, रंगदारी का उद्योग फिर से लौट गया है । महोदय, पूरे बिहार में भय का वातावरण बन रहा है और मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की भी भारी क्षति हुई है उसका भी सर्वेक्षण कराकर सरकार मुआवजा दे । अध्यक्ष महोदय, इन दोनों विषयों पर सरकार को जवाब देना चाहिए ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, आपने सूचना दे दी है, अब आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, सरकार...

अध्यक्ष : अब अल्पसूचित प्रश्न लिये जायेंगे ।

नेता प्रतिपक्ष, आप अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार को निर्देश मिले...

अध्यक्ष : अल्पसूचित प्रश्न । माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी ।

(व्यवधान जारी)

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-61 (श्री संजय सरावगी, क्षेत्र संख्या-83, दरभंगा)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : 1. वस्तुस्थिति यह है कि विभागीय अधिसूचना ज्ञापांक-4111, दिनांक-28.05.2013 के द्वारा पूर्व से पिछड़े वर्ग की महिलाओं के लिए प्रावधानित 3 प्रतिशत आरक्षण को अक्षुण्ण रखते हुए शेष आरक्षित एवं

गैर आरक्षित वर्गों के 97 प्रतिशत पदों के 35 प्रतिशत पद प्रत्येक आरक्षण कोटि में अलग-अलग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है ।

इसके फलस्वरूप जिला पुलिस तथा सैन्य पुलिस की बहाली की प्रक्रिया में 37 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, जिससे महिलाओं की संख्या एवं उनके प्रतिशत में लगातार वृद्धि हो रही है ।

2. वस्तुस्थिति यह है कि जिस पुलिस केन्द्र, बैरक, थाना एवं ओ0पी0 में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग शौचालय नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग शौचालय का निर्माण कराया गया है । अबतक कुल-51 पुलिस लाइन/बटालियन में 20 सीटेड तथा कुल 763 थानों/ओ0पी0 में से 107 थानों/ओ0पी0 में 5 सीटेड एवं 656 थाना/ओ0पी0 में 2 सीटेड शौचालय का निर्माण पूर्ण हो चुका है । साथ ही, पुलिस केन्द्र/बटालियन एवं थाना/ओ0पी0 के नए बनने वाले भवन में महिला पुलिस कर्मियों के लिए अलग शौचालय का प्रावधान किया गया है ।

बिहार पुलिस में उपयोग हेतु अस्थाई शौचालय की आवश्यकता/आपूर्ति के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा मोबाइल ट्वायलेट के संबंध में निर्गत स्पेसिफिकेशन की छायाप्रति पुलिस मुख्यालय के पत्रांक-64/आधु0, दिनांक-24.01.2022 द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, बिहार, पटना सहित सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक/समादेष्टा, बिहार को उपलब्ध करायी गयी है ।

3. उपर्युक्त कंडिका-'2' में स्थिति स्पष्ट की गई है ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष...

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, जनक सिंह जी आप बैठ जाइये । नेता प्रतिपक्ष ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है और सरकार उसको सुन ली है, सदन सुन लिया है, अब आप प्रश्नकाल होने दीजिए ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, हमारे नेता प्रतिपक्ष बोल रहे हैं, उसके बाद मैं अपना प्रश्न पूछूंगा ।

अध्यक्ष : अब आपलोगों को बैठ जाना चाहिए, आपके नेता प्रतिपक्ष ने सूचना दे दी है और सूचना को सदन ने सुन लिया है । श्री संजय सरावगी जी, आप अपना प्रश्न पूछें ।

(व्यवधान जारी)

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछता हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

माननीय सदस्य, जनक सिंह जी आप बैठें । संजय सरावगी जी, आप अपना प्रश्न पूछें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, मैंने अपना प्रश्न पूछ लिया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री संजय सरावगी जी आप अपना पूरक प्रश्न पूछें । आपलोग अपना स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

माननीय सदस्य, संजय सरावगी जी आप अपना प्रश्न पूछेंगे या नहीं पूछेंगे ?

श्री संजय सरावगी : महोदय, मैं अपना प्रश्न पूछूंगा, जरा हाउस ऑर्डर में आ जाय ।

(इस अवसर पर विपक्ष के कई माननीय सदस्यगण वेल में आ गए ।)

अध्यक्ष : इनलोगों को मैं कह रहा हूं कि आपलोग अपने स्थान पर जाकर, स्थान ग्रहण करें ।

(व्यवधान जारी)

अब तारांकित प्रश्न लिये जायेंगे । माननीय सदस्य, श्री गोपाल रविदास ।

(व्यवधान जारी)

आपने सूचना दे दी है, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । सरकार एक मिनट में कहां से जवाब दे देगी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2094 (श्री गोपाल रविदास, क्षेत्र संख्या-188, फुलवारी(अ0जा0))

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री (लिखित उत्तर) : उद्योग विभाग द्वारा कोई भी इकाई नहीं लगायी जाती है । यदि कोई उद्यमी मसूर प्रोसेसिंग आधारित प्लान्ट लगाना चाहते हैं तो उन्हें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत सुविधाएं एवं अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है । अति लघु उद्योग इकाइयों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत क्रेडिट लिंक पूंजीगत अनुदान प्रदान की जाती है ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक प्रश्न है कि पटना, नालन्दा, जहानाबाद सहित जो मध्य बिहार के इलाके हैं, जहां पर मसूर के बड़े पैमाने पर पैदावार होते हैं लेकिन एक भी सरकारी स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट का निर्माण नहीं किया गया है । हम मंत्री जी से जानना चाहते हैं और उत्तर जो आया है कि सरकारी स्तर पर प्रोसेसिंग यूनिट खोलने का कोई विचार नहीं है तो हम जानना चाहते हैं कि सरकारी

स्तर पर मसूर का प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं खोला जा सकता है । क्या मंत्री जी, इसको स्पष्ट करना चाहेंगे ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, उद्योग विभाग ।

माननीय सदस्य, आपलोग अपना स्थान ग्रहण करें । आपलोग यह मामला दूसरे आवर में उठाइयेगा ।

(व्यवधान जारी)

आपलोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, पूरी तरह से यह स्पष्ट जवाब दिया गया है कि उद्योग विभाग द्वारा कोई भी इकाई नहीं लगायी जाती है । यदि कोई उद्यमी मसूर प्रोसेसिंग आधारित प्लान्ट लगाना चाहते हैं तो उन्हें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत सुविधाएं एवं अनुदान उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अति लघु उद्योग इकाइयों को प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत क्रेडिट लिंक पूंजीगत अनुदान प्रदान की जाती है । बिहार सरकार लगभग, जो पहले था उससे अभी तक 24 करोड़ 3 लाख 1 हजार 934 रुपये दे चुकी है तो कोई भी वहां अगर उद्यमी बनना चाहता है तो सरकार उसे प्रमोट करती है, सरकार उद्योग खुद नहीं लगाती है । इसलिए मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि कोई भी अगर वहां पर करना चाह रहा है तो हमलोग 35 परसेंट तक सब्सिडी, बैंक से उसका ये और निश्चित तौर पर 1 करोड़ तक का पूंजीगत व्यय हमलोग कराने का प्रयास करेंगे इसलिए मेरा माननीय सदस्य से आग्रह है कि आप उस ढंग के किसी उद्यमी को खोजें जिस उद्यमी को पूरी तरह ऐसे उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित करें ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष : आपलोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए, अभी तारांकित प्रश्न हो रहा है इसको होने दीजिए ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : मैंने कहा है कि आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, मेरा कहना है कि सरकार निजी तौर पर उद्यमियों को प्रोत्साहित करके पैसा देकर यूनिट खड़ा करवाना चाहती है । लेकिन मेरा कहना है कि सरकार स्वयं सरकारी नीति के अनुसार अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं बनाना चाहती है, क्या मंत्री जी स्पष्ट बताना चाहेंगे ।

(इस अवसर पर वेल में आये हुए माननीय सदस्यगण अपनी-अपनी सीट पर वापस चले गए)

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, हमलोग सारा प्रोत्साहन नीति देते हैं ताकि एक नहीं सैकड़ों, एक जिला में अभी तक 500 उद्योग स्थापित हो चुके हैं लेकिन मेरा मानना है कि 2016 प्रोत्साहन नीति के तहत उनकी मदद की जाती है । माननीय सदस्य से मेरा आग्रह है कि कोई ऐसा उद्योग खोलने के लिए आप उद्यमी को लायें, हमलोग उसे पूरी तरह जो भी मसूर दाल प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने के लिए प्रयास करेंगे ।

श्री गोपाल रविदास : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो...

अध्यक्ष : आपका पूरक प्रश्न हो गया, अब दूसरे माननीय सदस्य को पूछने दीजिए ।

श्री गोपाल रविदास : महोदय, हमें स्पष्ट उत्तर नहीं मिल रहा है । मेरा कहना है कि सरकार अपने से क्यों नहीं खोलना चाहती है, जो प्रोत्साहित करके निजी उद्यमियों को देना चाहती है । सरकार अपनी सरकारी प्रोसेसिंग यूनिट क्यों नहीं बैठाना चाहती है, हम यह जानना चाहते हैं मंत्री जी से ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, सरकार अपने आप में इस तरह का उद्योग नहीं खोलती है, लेकिन प्रोत्साहन नीति के तहत सैकड़ों उद्योग खुल रहे हैं, मेरा आग्रह है कि 1 करोड़ तक के लिए पूंजीगत व्यय कराकर जिसमें 35 प्रतिशत उन्हें हर तरह का लाभ भी मिलेगा और पांच तरह का हम उन्हें फायदा दे रहे हैं, शुल्क पूंजीकरण, प्रतिपूर्ति स्टाम्प, भूमि समर्पण शुल्क, ब्याज अनुदान, कर के संबंधित अनुदान ताकि पांच साल तक के लिए यह जो टैक्स हॉलिडे मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो चाहेंगे, वे लोग फैक्ट्री स्टैब्लिस करेंगे लेकिन सरकार अपने कोई फैक्ट्री नहीं खोलती है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी प्रश्न है, इसको करवा दीजिए ।

अध्यक्ष : आपने यह प्रश्न नहीं पूछा, अब हम तारांकित प्रश्न में चले गये हैं । अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, हाउस ऑर्डर में नहीं था ।

अध्यक्ष : हम तो हाउस को ऑर्डर में लाना चाहते थे, लेकिन ऑर्डर में नहीं आ सका ।

श्री श्रवण कुमार, मंत्री : अध्यक्ष महोदय,...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव खड़े हो गये हैं ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, अल्पसूचित प्रश्न का डेढ़ बजे तक का समय है ।

अध्यक्ष : नहीं, समय जितना है, उतना समय जरूर दिया जाता । लेकिन आपसे तीन बार पूछा गया, लेकिन आप अपना सप्लीमेंट्री प्रश्न नहीं पूछ सके ।

माननीय सदस्य, श्री मनोज कुमार यादव अपना पूरक प्रश्न पूछें ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2095 (श्री मनोज कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-16, कल्याणपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : आंशिक स्वीकारात्मक ।

अहिरौलिया कबीर पंथी मठ (अहिरौलिया) की जमीन के चहारदीवारी का निर्माण नहीं हुआ है एवं किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है।

गृह विभाग (विशेष शाखा) के संकल्प ज्ञापांक-8778, दिनांक-19.09.2016 के तहत राज्य अन्तर्गत उन्हीं मंदिरों की चहारदीवारी का निर्माण किया जाता है, जो बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित हो । प्रश्नगत मठ बिहार राज्य धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित है ।

मंदिर चहारदीवारी निर्माण हेतु धार्मिक न्यास पर्षद से निबंधित मंदिरों की जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा प्राथमिकता सूची तैयार की जाती है ।

वर्तमान में उक्त मठ प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

श्री मनोज कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं पूरक प्रश्न पूछ रहा हूं कि सरकार का जवाब आया है कि कबीर पंथी मठ है, वह धार्मिक न्यास पर्षद में निबंधित है लेकिन जिला की प्राथमिकता सूची में नहीं है । अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से आग्रह है कि जिला से सूची मंगाकर जल्द-से-जल्द कबीर पंथी मठ की चहारदीवारी करा दी जाय और कब तक हो जायेगी, हम यही जानना चाह रहे हैं । जिला से सूची कब आयेगी जब निबंधित है तो जिला से सूची मंगाकर माननीय मंत्री जी कब तक करा देंगे ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए, माननीय मंत्री जी जवाब दे रहे हैं।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि माननीय सदस्य ने ठीक से उत्तर को पढ़ा नहीं है । स्पष्ट उत्तर है कि अतिक्रमण नहीं है, लेकिन सवाल है कि धार्मिक न्यास पर्षद से बिना निबंधित हुए सरकार कोई चहारदीवारी नहीं बनाती है । माननीय सदस्य से अनुरोध है कि धार्मिक न्यास पर्षद में इसको करवा लें, उसके बाद ही इस पर विचार किया जायेगा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2096 (श्री विजय कुमार खेमका, क्षेत्र संख्या-62, पूर्णियां)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री विजय कुमार खेमका जी ने माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी को अथॉराइज किया है । इसलिए माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी प्रश्न पूछें ।

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

टर्न-2/यानपति/20.03.2023

तारांकित प्रश्न सं0-2097 (श्री संदीप सौरभ, क्षेत्र सं0-190 पालीगंज)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: उत्तर स्वीकारात्मक है । सैनिक कल्याण निदेशालय, बिहार, पटना के पत्रांक-1244, दिनांक-10.06.2022 द्वारा नायक शहीद रामानुज कुमार के निकटतम आश्रित माता श्रीमती लीला देवी को अनुग्रह अनुदान भुगतान करने हेतु 11,00,000/- रु0 का आवंटल जिला पदाधिकारी, पटना को दिया जा चुका है । नजारत उपसमाहर्ता, पटना के पत्रांक-661, दिनांक-16.03.2023 द्वारा सूचित किया गया है कि दिनांक- 14.03.2023 को नायक शहीद रामानुज कुमार के निकटतम आश्रित माता श्रीमती लीला देवी को 11,00,000/- रु0 अनुग्रह अनुदान राशि का भुगतान किया जा चुका है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री संदीप सौरभ । संदीप जी, आप पूरक पूछें ।

श्री संदीप सौरभ: अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक सवाल है कि पटना जिला के पालीगंज प्रखंड में परियों गांव के निवासी थे श्री रामानुज यादव और 27 मई, 2022 को जम्मू कश्मीर में उनकी शहादत हो गई । उनको सरकार ने बैटल कैजुअलिटी सर्टिफिकेट भी दिया तो सवाल डालने के बाद हालांकि उनके परिवार को मुआवजा मिला है लेकिन मेरा सरकार से यह सवाल है, चूंकि उस परिवार के एक व्यक्ति थे जिनकी शहादत हो गई तो उनके बड़े भाई हैं, बेरोजगार हैं, 33 साल की उम्र उनकी है तो क्या सरकार उनको नौकरी देने का कोई विचार रखती है, बिहार सरकार ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, उनको अनुदान दे दिया गया है, नौकरी देने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसपर कोई विचार नहीं है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव ।

श्री संदीप सौरभ: अध्यक्ष महोदय......

अध्यक्ष: अनुदान दे दिया गया है ।

श्री संदीप सौरभ: एक बात और कहनी है, कई सारे राज्यों में इसका प्रावधान है, किसी की शहादत हुई तो उसके परिवार से मिलने के बाद अगर वहां के मुख्यमंत्री चाहते हैं तो उनके परिवार के किसी एक सदस्य को......

अध्यक्षः अनुदान से संबंधित आपका प्रश्न है, अनुदान दे दिया गया है इसलिए स्थान ग्रहण करें ।

श्री संदीप सौरभः महोदय, अगर सरकार उसको दे देती है तो बाकी राज्यों में हो रहा है तो यहां क्यों नहीं हो सकता है ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मुकेश कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न सं0- 2098 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र सं0-27 बाजपट्टी)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्रीः अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला अन्तर्गत प्रखंड- बोखड़ा के ग्राम- हरिनगर में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबन्दी हो चुकी है।

ग्राम-धनकौल (मौजा-धनकौल, थाना-213 के अन्तर्गत खेसरा-1147) गैर मजरूआ सर्वसाधारण आम कब्रिस्तान है । उक्त कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

श्री मुकेश कुमार यादवः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है सिर्फ आग्रह है इनसे कि जो प्राथमिकता सूची में है वहां चाहेंगे मंत्रीजी से आग्रह करेंगे जल्द से जल्द कब्रिस्तान की घेराबंदी हो जाय ।

अध्यक्षः माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी है, प्राथमिकता सूची वह तय करती है तो उसको प्राथमिकता सूची में बारी-बारी से जहां, असल में देखिए कब्रिस्तान घेराबंदी का मुख्य मकसद है महोदय कि आपस में विवाद नहीं हो ऐसा नहीं है कि हंड्रेड परसेंट को हो जहां विवाद होता है हिन्दू-मुस्लिम में उसको प्राथमिकता के आधार पर निर्धारित करता है कलक्टर, एस0पी0 की अध्यक्षता में कमेटी है । इसीलिए सूची भी वही बनाते हैं और तैयार करते हैं ।

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री मनोहर प्रसाद सिंह ।

तारांकित प्रश्न सं0-2099 (श्री मनोहर प्रसाद सिंह, क्षेत्र सं0-67 मनिहारी (अ0ज0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री सूर्यकान्त पासवान ।

तारांकित प्रश्न सं0-2100 (श्री सूर्यकान्त पासवान, क्षेत्र सं0-147 बखरी (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्षः माननीय सदस्य श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता ।

तारांकित प्रश्न सं0-2101 (श्री लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, क्षेत्र सं0-20 चिरैया)

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

तारांकित प्रश्न सं0-2102 (श्री अजय कुमार सिंह, क्षेत्र सं0-166 जमालपुर)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री अजय कुमार सिंह । पूरक पूछें ।

श्री अजय कुमार सिंह: जवाब नहीं आया है लेकिन इसका पूरक ही पूछ लेता हूं क्या माननीय मंत्री जी को पता है कि इस राज्य में गजेटियर को अंग्रेजी में पढ़कर......

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री: महोदय, इनका प्रश्न राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित किया गया है ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका प्रश्न राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में स्थानांतरित है । माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ।

तारांकित प्रश्न सं0-2103 (श्री मनोज मंजिल, क्षेत्र सं0-195 अगिआँव (अ0जा0))

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलांतर्गत प्रखंड चरपोखरी के मौजा ठेंघवा थाना नंबर-300, खाता-89, खेसरा-523 बिहार सरकार अनावाद किस्म पुरानी प्रति रकवा 40 डिस्मिल के अंश भाग में अवस्थित कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है ।

मौजा भलुआना (प्रेम अकौढ़ा), थाना-307 खाता-35 खेसरा-5 किस्म कब्रिस्तान रकवा 1.49ए0 में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी वर्ष- 2009-10 में की गई है ।

ग्राम-ठेंघवा एवं भलुआना के ग्रामीणों में सौहार्द एवं आपसी भाईचारा का वातावरण है तथा विधि-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर, अनिवार्यता के आधार पर नहीं संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी कमबद्ध से घेराबंदी किए जाने की नीति है ।

अध्यक्ष: पूरक पूछें ।

श्री मनोज मंजिल: महोदय, इसमें जवाब आता है कब्रिस्तान की घेरेबंदी पर जो हम सवाल करते हैं तो जवाब आता है कि वह संवेदनशील नहीं है, वहां माहौल ठीक है इसलिए प्राथमिकता के आधार पर, अब बताइये हमारे विधान सभा क्षेत्र में परिरया हो, काहुक, ठेंघवा, सांघी, 30 से ज्यादा कब्रिस्तान है जिसकी घेरेबंदी नहीं हुई है और कब्रिस्तान की घेरेबंदी हुई भी थी तो 10 साल हो गया है, वह ढह गया है, दीवालें गिर गई हैं ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिए ।

श्री मनोज मंजिल: हम कहना चाहते हैं कि जो कब्रिस्तान का सवाल हमने उठाया है भलुआना का, ठेंघवा का, सरकार उसको कबतक घेरेबंदी कराने का विचार रखती है ?

अध्यक्ष: माननीय मंत्री ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, उत्तर स्पष्ट है, इसमें कोई सप्लीमेंट्री की गुंजाइश ही नहीं, उत्तर तो स्पष्ट दिया हुआ है ।

(व्यवधान)

श्री मनोज मंजिल: महोदय, अभी मेरा है तो फिर आप खड़े हो गए, रुक जाइये ।

अध्यक्ष: अच्छा आप पूछिए ।

श्री मनोज मंजिल: मंत्री महोदय ने क्या कहा कुछ सुनाई ही नहीं दिया, बहुत धीरे बोलते हैं न । महोदय, बहुत धीरे बोलते हैं मंत्री जी इसलिए क्या उन्होंने कहा स्पष्ट नहीं हो पाया।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जरा एक बार उनको और बतला दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: महोदय, मैं पढ़कर सुना देता हूं ।

अध्यक्ष: हां वही सुना दीजिए ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: उनको मिला हुआ है उत्तर लगता है पढ़े नहीं । वस्तुस्थिति यह है कि भोजपुर जिलांतर्गत प्रखंड चरपोखरी के मौजा ठेंघवा थाना नंबर-300, खाता-89, खेसरा-523 बिहार सरकार अनावाद किस्म पुरानी प्रति रकवा 40 डिस्मिल के अंश भाग में अवस्थित कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिक सूची में शामिल नहीं है ।

मौजा भलुआना (प्रेम अकौढ़ा), थाना-307 खाता-35 खेसरा-5 किस्म कब्रिस्तान रकवा 1.49ए0 में अवस्थित कब्रिस्तान की घेराबंदी वर्ष- 2009-10 में की गई है ।

ग्राम-ठेंघवा एवं भलुआना के ग्रामीणों में सौहार्द एवं आपसी भाईचारा का वातावरण है तथा विधि-व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर, अनिवार्यता के आधार पर नहीं संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध से घेराबंदी किए जाने की नीति है ।

अध्यक्ष: आपका जवाब मिल गया ।

श्री मनोज मंजिल: महोदय, वह दीवार गिर गया है इसीलिए सेंसिटिव हो गया है । वहां पर लड़ाई-झगड़ा की नौबत है इसलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह जो ठेंघवा, बलुआना का जो कब्रिस्तान है उसकी घेराबंदी अविलंब करावे ।

अध्यक्ष: सरकार ने बहुत सही तरीके से आपके प्रश्न का जवाब दिया है । बचौल जी आप बोलिये ।

(व्यवधान)

आप जरा एक मिनट, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल': अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्र निवेदन है आपसे कि बिहार में गरीब, पिछड़ा, दलित को आवासीय भूमि नहीं है और एक तरफ सरकारी जमीन हजारों एकड़ कब्रिस्तान के रूप में घेरवा दिया गया है, क्या यह बात सही है ?

अध्यक्ष: स्थान ग्रहण कीजिए, इस प्रश्न से संबंधित नहीं है । माननीय महबूब साहब, आप पूछ लीजिए ।

श्री महबूब आलम: अध्यक्ष महोदय, कब्रिस्तान घेराबंदी के मुद्दा को, हर वक्त यह मुद्दा आता है महोदय तो सरकार टालती रहती है, महोदय, यह सुरक्षा समिति का जो......

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप सुनें ।

श्री हरीभूषण ठाकुर 'बचोल': सरकारी जमीन हजारों एकड़......

श्री महबूब आलम: बोलने दीजिए ।

अध्यक्ष: बचोल जी आप बोल दिए हैं ।

श्री महबूब आलम: संवेदनशीलता की जो मानकता है महोदय, कौन कब्रिस्तान घेरने के लिए संवेदनशीलता की जरूरत है इसकी मानकता कौन तैयार करेंगे, विधायकों की इसमें कोई भूमिका होगी या नहीं । सिर्फ डी0एम0 और एस0पी0 करेंगे अपने ए0सी0 कमरे में बैठकर के और सब विधायक झेलेंगे इसको । विधायक को संवेदनशीलता का मानक तैयार करने का अधिकार दिया जाय महोदय ।

अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: क्या-क्या प्रश्न करते हैं महोदय संवेदनशीलता......

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप शांति बनाइये न, आप सुनिए सरकार का जवाब ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: संवेदनशीलता का अर्थ ही होता है कि विवाद की संभावना है, कभी विवाद हुआ है या होनेवाला है और विधायक फंड से भी तो कब्रिस्तान की घेराबंदी होती है लेकिन संवेदनशीलता के आधार पर होती है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप शांति बनाए रखें । सुनिए सरकार का जवाब ।

(व्यवधान)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य क्या चाहते हैं मेरी समझ में नहीं आ रहा है । मंदिर-मस्जिद दोनों की घेराबंदी है लेकिन संवेदनशीलता के आधार पर, जहां शांति व्यवस्था है वहां घेराबंदी की कोई जरूरत नहीं है, यही सरकार का सिद्धांत है ।

श्री महबूब आलम: संवेदनशीलता का क्या अर्थ है यह तय होना चाहिए न, संवेदनशीलता से एक मतलब है महोदय किसी कब्रिस्तान के अतिक्रमण का भी सवाल है, किसी कब्रिस्तान की बेहुरमती का भी सवाल है महोदय, तो अतिक्रमण और बेहुरमती का सवाल जो संवेदनशील सवाल है और इन सवालों पर सामाजिक जो है व्यवधान भी उत्पन्न होता है महोदय और तनाव भी पैदा होता है तो इस सवाल में विधायकों की भूमिका भी होगी या नहीं......

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए । माननीय मंत्री जी के द्वारा प्रश्न का जवाब दे दिया गया है । श्री सूर्यकान्त पासवान ।

तारांकित प्रश्न सं0-2104 (श्री सूर्यकान्त पासवान, क्षेत्र सं0-147 बखरी (अ0जा0))

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह । अजय बाबू प्राधिकृत हैं । अजय बाबू प्रश्न पूछें ।

तारांकित प्रश्न सं0-2105 (श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह, क्षेत्र सं0-193 बड़हरा)

(लिखित उत्तर)

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री: अध्यक्ष महोदय, बिहार राज्य निर्यात निगम परिसमापन की प्रक्रिया में है । निगम को पुनर्जीवित कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

श्री अजय कुमार सिंह: क्या मंत्री जी बताएंगे कि परिसमापन की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकने के बाद भी पुल निर्माण निगम को पुनर्जीवित किया गया तो निर्यात निगम को पुनर्जीवित करने का विचार क्यों नहीं रखती है सरकार ? दूसरा पूरक है मंत्री जी बताएंगे कि राज्य में विगत 15 वर्षों में कितने निगम बोर्ड सृजित किए गए हैं ?

टर्न-3/अंजली/20.03.2023

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर था, बिहार राज्य निर्यात निगम परिसमापन की प्रक्रिया में है । निगम को पुनर्जीवित कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कोर्ट में भी यह मामला वर्ष 2003 से ही चल रहा है और वर्ष-2003 के 29.01.2015 को पटना उच्च न्यायालय द्वारा बिहार राज्य निर्यात निगम को परिसमाप्ति करने का आदेश पारित करते हुए शासकीय समापन पटना उच्च न्यायालय, मौर्या लोक कॉम्पलेक्स, पटना को अपने अधीन लेने का आदेश दिया

गया है । उक्त आदेश के आलोक में बिहार राज्य निर्यात निगम की परिसंपत्ति को शासकीय समापन को सौंप दिया गया है । बिहार राज्य निगम के कुल 51 कर्मी कार्यरत थे जिनका बकाया वेतन आदि लगभग 68 करोड़ था । वर्तमान में इनका मामला शासकीय समापन के अधीन है

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सरकार के द्वारा आपके प्रश्न का भरपूर उत्तर दे दिया गया है ।

श्री नंद किशोर यादव : महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, वह विवाद जो कोर्ट में था उस कॉरपोरेशन का समापन हुआ कि नहीं हुआ, इस पर नहीं था । वह विवाद था कोर्ट में कर्मचारियों के वेतन भुगतान का, उनके बकाये के भुगतान का यह सारा विषय था । माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है, तो आप लगातार कह रहे हैं कि उद्योगों में वृद्धि हो रही है । हम बड़े पैमाने पर नये उद्योग लगा रहे हैं और जब उद्योगों में वृद्धि हो रही है, हमारे यहां लीची है, आम है सब के एक्सपोर्ट की भी संभावना है महोदय । बहुत सारे उत्पाद राज्य में ऐसे हैं, अब मखाना भी हो गया है, कई उत्पाद ऐसे हैं जिनका एक्सपोर्ट हो सकता है तो उसके काम के सुलभ संचालन के लिए जो एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बना था, उसमें किसी कारण से बंद हो गया, निर्यात की संभावना नहीं रही होगी, जो भी कारण रहा होगा विवाद का, लेकिन अब जब आप कह रहे हैं कि उद्योग में प्रगति हुई है और कई यहां के उत्पाद विदेश जा सकते हैं तो आप फिर एक्सपोर्ट कॉरपोरेश्न के ऊपर यूज करने का विचार क्यों नहीं रखते हैं, यह बताएं ?

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, बात सही है कि हरेक जिलों से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने का सरकार सोच रही है लेकिन यह वर्ष 2003 से ही मामला चल रहा है, न्यायालय में लंबित है, अगर तुरंत कुछ निर्णय आ जाता है तो...

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या माननीय न्यायालय में लंबित है ?

श्री समीर कुमार महासेठ, मंत्री : जी, मामला न्यायालय में लंबित है ।

अध्यक्ष : तो इस पर चर्चा नहीं होगी । आप स्थान ग्रहण कीजिए । श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह ।

(व्यवधान)

हो गया है नंद किशोर बाबू आपने पूछ दिया । अब मैं आगे बढ़ गया हूं और मामला न्यायालय में लंबित है इसलिए इस पर चर्चा नहीं होगी, सरकार जवाब दे रही है । सरकार के जवाब पर मैं कह रहा हूं कि यह मामला न्यायालय में लंबित है और जो न्यायालय में लंबित है, सदन में उस पर चर्चा नहीं हो सकती है ।

माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कीजिए, और भी सदस्यों का प्रश्न है । माननीय सदस्य, डब्लू सिंह जी ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2106 (श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह, क्षेत्र संख्या-221, नवीनगर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, 1. उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्त्ती) नियमावली, 1954 के नियम-8 में भारतीय प्रशासनिक सेवा (बिहार संवर्ग) के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरीय दायित्व के पदों का 33 1/3 प्रतिशत राज्य असैनिक सेवा से प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति (भा0प्र0से0) हेतु निर्धारित है । उक्त प्रतिशत के अनुसार परिगणित पदों का 15 प्रतिशत (भिन्नांक छोड़कर) गैर राज्य असैनिक सेवा से चयन द्वारा नियुक्त करने का प्रावधान है ।

2. उत्तर अस्वीकारात्मक है । राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति में आरक्षण का मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के समक्ष विचाराधीन है तथा राज्य सरकार द्वारा दाखिल सिविल अपील संख्या-4880/2017, राज्य सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं अन्य माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सिविल अपील संख्या-629/2022, जरनैल सिंह केस के साथ सम्बद्ध रहने एवं इस वाद में दिनांक-15.04.2019 को माननीय न्यायालय द्वारा Status Quo (यथास्थिति) आदेश पारित किये जाने के कारण राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति अवरुद्ध है ।

उपर्युक्त वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-31.01.2023 को पारित आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा तत्परतापूर्वक राज्याधीन सेवाओं में प्रोन्नति के पदों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधित्व संबंधी मात्रात्मक आंकड़े एकत्र किये गए हैं, इन्हें आदेशानुसार समेकित कर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रखा जाना है । इस वाद की अगली सुनवाई की तिथि दिनांक- 17.07.2023 से आरंभ होने वाले सप्ताह में निर्धारित है ।

माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के आदेशानुसार राज्य सरकार द्वारा अग्रेतर कार्रवाई की जा सकेगी ।

3. कंडिका-1 एवं 2 के उत्तर में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री विजय कुमार सिंह उर्फ डब्लू सिंह : महोदय, मुझे इसका जवाब मिल गया है । इसमें पूरक पूछने लायक बचा ही नहीं है क्योंकि यह भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है ।

अध्यक्ष : तो आप स्थान आराम से ग्रहण कर लीजिए । माननीय सदस्य, श्री मुकेश कुमार यादव ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2107 (श्री मुकेश कुमार यादव, क्षेत्र संख्या-27, बाजपट्टी)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि सीतामढ़ी जिला अंतर्गत प्रखंड-बोखड़ा के मौजा-झिटकी थाना नंबर-223 के अंतर्गत कोई कब्रिस्तान की भूमि नहीं है । जबकि ग्राम झिटकी के लोग मौजा-भाउर, थाना नंबर-222, खाता नंबर-824, खेसरा-4248, रकवा-3 एकड़-10 डी0 में अवस्थित कब्रिस्तान का प्रयोग करते हैं, जिसकी घेराबंदी हो चुकी है ।

मौजा-बड़ी धर्मपुर थाना नंबर-221 के अंतर्गत खेसरा-11723 बिहार सरकार किस्म कब्रिस्तान जिला स्तर पर तैयार प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं है ।

कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से संवेदनशीलता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है और उसी क्रमबद्ध ढंग से घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी का जवाब आया है, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं कि संवेदनशील कब्रिस्तानों की सूची बनाने में क्या सरकार संबंधित क्षेत्र के माननीय विधायक को भी उसमें शामिल करना चाहती है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, नियम में ऐसी व्यवस्था नहीं है लेकिन अगर माननीय सदस्य चाहें तो कलेक्टर...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाए रखिए न, सुनिये । सरकार के जवाब को सुनिये और आपको पूरक पूछना होगा तो इजाजत लीजिए, इजाजत मिलेगी, आप पूरक पूछियेगा ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, लेकिन अगर वह संवेदनशील इलाका है, माननीय विधायक कलेक्टर के यहां पेटीशन दें, कमेटी उस पर विचार करेगी ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि जिस क्षेत्र में माननीय विधायक जहां-जहां घूमते हैं वहां कलेक्टर...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये न, उतना क्यों घूम के पूछ रहे हैं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : महोदय, पूरक ही पूछ रहे हैं । सरकार उस कमेटी में माननीय विधायक को शामिल करना चाहती है या नहीं ?

अध्यक्ष : यह तो नीतिगत मामला है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, यह कोई व्यवस्था है ही नहीं ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती मंजु अग्रवाल ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2108 (श्रीमती मंजु अग्रवाल, क्षेत्र संख्या-226, शेरघाटी)

(माननीय सदस्या अनुपस्थित)

माननीय सदस्य, श्री रणविजय साहू ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2109 (श्री रणविजय साहू, क्षेत्र संख्या-135, मोरवा)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत खेसरा में कब्रिस्तान का कोई प्रमाण नहीं है । हल्का खतियान के अनुसार भूमि बांसवारी एवं कृषि होती है । भूमि रैयती खाते की है ।

राज्य सरकार द्वारा सरकारी भूमि पर अवस्थित संवेदनशीलता के आधार पर चयनित कब्रिस्तानों की घेराबंदी कराये जाने की नीति है ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्री रणविजय साहू : अध्यक्ष महोदय, मुझे जवाब मिला है और महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि वहां वर्ष 2005 में ही जिला परिषद योजना के तहत कब्रिस्तान की घेराबंदी हुई थी जो अधूरा है और जो पदाधिकारी जवाब दिये हैं हमें लगता है कि ऑफिस में बैठे-बैठे जवाब को बना दिये हैं । हम माननीय मंत्री जी, आपके माध्यम से जानना चाहते हैं कि ताजपुर नगर परिषद वार्ड नंबर-23 में जो कब्रिस्तान है, सरकार उसको फिर से उसका सर्वे कराकर घेराबंदी पर विचार रखती है कि नहीं ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, माननीय सदस्य, अगर कहते हैं कि कब्रिस्तान है, जवाब आया है कि यह कब्रिस्तान नहीं है तो एक लिखित पूरा खाता, खेसरा के साथ दे दें, हम इसको दिखवा देंगे ।

अध्यक्ष : आप खाता-खेसरा के साथ एक लिखित दे दीजिए, माननीय मंत्री जी इसकी जांच करवा लेंगे । माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खां ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2110 (श्री शकील अहमद खां, क्षेत्र संख्या-64, कदवा)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि कटिहार जिला अंतर्गत डंडखोरा थाना सरकारी भूमि पर बने मॉडल थाना भवन में कार्यरत है, किंतु थाना परिसर की घेराबंदी नहीं हुई है । थाना परिसर की चहारदीवारी निर्माण हेतु प्राक्कलन की मांग पुलिस मुख्यालय के पत्रांक-266/आधु0, दिनांक-18.03.2023 द्वारा बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना से किया गया है। प्राक्कलन प्राप्त होने पर थाना परिसर की चहारदीवारी निर्माण के लिए अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, पूरक पूछिये ।

श्री शकील अहमद खां : महोदय, माननीय मंत्री, कब तक उसको करवा देंगे ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि आपके प्रश्न को गंभीरतापूर्वक लेते हुए निर्देशित किया गया है । भूमि भी जल्द उपलब्ध हो जाएगी तो कार्रवाई की जाएगी ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती शालिनी मिश्रा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2111 (श्रीमती शालिनी मिश्रा, क्षेत्र संख्या-15, केसरिया)

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री (लिखित उत्तर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर अस्वीकारात्मक है । वस्तुस्थिति यह है कि बिहार राज्य चीनी निगम के अधीन गया जिलान्तर्गत गुरारू इकाई एवं नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज इकाई जो चीनी मिल के रूप में कार्यरत थी क्रमशः 1990-91 एवं 1992-93 से बंद है ।

राज्य सरकार द्वारा उक्त इकाइयों को गन्ना आधारित उद्योग एवं अन्य उद्योगों की स्थापना के उद्देश्य से निविदा प्रक्रिया द्वारा वित्तीय सलाहकार SBI Caps के माध्यम से पांच निविदा आमंत्रित की गई । परंतु गया जिलान्तर्गत गुरारू चीनी मिल एवं नवादा जिलान्तर्गत वारिसलीगंज चीनी मिल के पुनर्जीवन हेतु कोई भी निवेशक सफल नहीं हो पाये ।

सरकार के निर्णयानुसार राज्य में Priority Sector उद्योगों की स्थापना हेतु बिहार राज्य चीनी निगम की बंद पड़ी गुरारू एवं वारिसलीगंज सहित 8 अन्य इकाइयों को बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (BIADA) को हस्तांतरित किया गया है ।

सरकार के स्तर से गुरारू एवं वारिसलीगंज चीनी मिल में डिस्टीलरी स्थापित करने की कोई कार्य योजना नहीं है । यदि कोई निवेशक द्वारा गुरारू एवं वारिसलीगंज इकाई में डिस्टीलरी की इकाई स्थापित करने का प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सरकार उन्हें नियमानुकूल अपेक्षित सहयोग प्रदान करेगी ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, मेरा पूरक है माननीय मंत्री जी से, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सन् 1990-91 और 1992-93 में गुरारू और वारिसलीगंज इकाई डिस्टीलरी बंद है और दुबारा से उसको स्थापित करने की सरकार की कोई योजना नहीं है । मैं कहना चाहती हूं कि हर बार यह प्रश्न आता है और हर बार सरकार कहती है कि योजना नहीं है । मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहती हूं, सरकार बहुत जागरूक है, तत्पर है औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के लिए तो क्या सरकार औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत बिहार राज्य निगम के बंद चीनी मिल एवं डिस्टीलरी को चालू कराने की कोई योजना का विचार रखती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गन्ना उद्योग विभाग ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर में बहुत स्पष्ट है कि सरकार के स्तर से गुरारू और वारिसलीगंज चीनी मिली में डिस्टीलरी स्थापित करने की कोई कार्य योजना नहीं है । यदि कोई निवेशक द्वारा गुरारू एवं वारिसलीगंज इकाई में चीनी उद्योग और डिस्टीलरी साथ में स्थापित करना चाहती है तो उसके लिए सरकार नियमानुकूल उसे अपेक्षित सहयोग करेगी ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, मेरा क्वेश्चन यही था कि सरकार अपनी तरफ से कुछ करना चाहेगी, एक क्वेश्चन यह था । दूसरा, मैं बोल देती हूं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : महोदय, वेलफेयर स्टेट में, वेलफेयर गवर्नमेंट खुद बिजनेस नहीं करती है । कोई कॉरपोरेशन जो पहले से स्थापित था, उसके द्वारा चलाये जा रहे सारे उद्योगों को वह पहले ही प्राइवेट सेक्टर में दे दिया गया है लेकिन यदि अभी भी कोई प्राइवेट सेक्टर में ही लोग आना चाहते हैं...

अध्यक्ष : इंवेस्टर यदि कोई आवें ?

श्री आलोक कुमार मेहता, मंत्री : जी, इंवेस्टर यदि आना चाहते हैं, वहां पर चीनी उद्योग लगाना चाहते हैं और चीनी उद्योग के साथ में इथेनॉल की जो इंडस्ट्री है उसके साथ लगाया जाएगा तो उसमें सरकार पूरा-पूरा सहयोग करेगी ।

श्रीमती शालिनी मिश्रा : महोदय, एक और पूरक है मेरा । वर्ष 2022-23 में बजट के समय में माननीय मंत्री जी ने वक्तव्य दिया था कि कोरोना काल में जो लोग लौटकर आ रहे हैं श्रमिकों के बीच रोजगार सृजन एवं गन्ना का उत्पादन बढ़ाने हेतु बिहार...

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये ।

श्रीमती शलिनी मिश्रा : महोदय, वही कह रही हूं । बिहार जैगरी इंडस्ट्रीज इंवेस्टमेंट प्रमोशन पॉलिसी बनायेगी, सरकार ने कहा था तो उसके तहत क्या उन चीनी मिलों और डिस्टीलरी को इसके लिए यूज करना चाहेगी सरकार ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी ने आपके प्रश्न का जवाब दे दिया है, इसलिए अब आप स्थान ग्रहण करें । अगर कोई आएगा प्राइवेट सेक्टर से तो सरकार उसका स्वागत करेगी, टर्म्स एंड कंडीशन पूरा करने के बाद से, उन्हें अनुमति दी जायेगी कि हां आप उद्योग लगावें ।

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह ।

टर्न-4/सत्येन्द्र/20-03-2023

तारांकित प्रश्न संख्या- 2112(श्री जनक सिंह,क्षेत्र सं0-116 तरैया)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: अस्वीकारात्मक । वस्तुस्थिति यह है कि माझोपुर चौक से तरैया थाना की दूरी 06 कि0मी0 है तथा अमनौर थाना की दूरी 05 कि0मी0 है । सड़क मार्ग संतोषजनक स्थिति में है । माझोपुर चौक से तरैया थाना पहुँचने में मात्र 6-8 मिनट एवं माझोपुर चौक से अमनौर थाना पहुँचने में मात्र 8-10 मिनट का समय लगता है । विगत पाँच वर्षों में हत्या-03, लूट-03, डकैती-00, गृहभेदन-00 एवं चोरी की-03 घटनाएँ घटित हुई है, परन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ गश्ती, बिट गश्ती, सुपर पेट्रोलिंग किये जाने पर अपराध नियंत्रण में है ।

वर्तमान में माझोपुर चौक पर ओ0पी0 बनाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछें ।

श्री जनक सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विधान-सभा क्षेत्र के तरैंया प्रखंड के माझोपुर चौक पर मैंने आग्रह किया था सरकार से कि वहां पर ओ0पी0 बनाया जाय । सरकार ने गंभीर विषय को नाकार दिया लेकिन मेरा यह कहना है कि वह जो चौक है, मैंने वहां के मढ़ौरा डी0एस0पी0 से पूछा कि वह जो चौक है वहां से मशरक, पानापुर, इसुआपुर, मढ़ौरा अन्य जितने अपराधी हैं उस रास्ते से होते हुए मुजफ्फरपुर की ओर या पटना के लिए रवाना हो जाते हैं इसलिए डी0एस0पी0 ने भी कहा कि नहीं, यहां पर बनाना जरूरी है लेकिन सरकार का जो जवाब आया है, यहां पर कोई औचित्य नहीं है इस प्रकार का जवाब आया है । इसीलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से पुनः मैं जानना चाहता हूँ कि रिपोर्ट तो आ गया है लेकिन वह स्थान जो है बड़ा गंभीर जगह है और वहां पर ठीक है, हम मानते हैं कि 5 कि0मी0 की दूरी पर तरैंया थाना है लेकिन वह जगह ऐसा है, जहां पुलिस की गश्ती दल कभी नहीं जाता है । वे पचरौल में रहते हैं, वहां से एक डेढ़ कि0मी0 की दूरी पर और हम भी नहीं चाहते हैं कि हर जगह पर ओ0पी0 बने लेकिन यह जगह उसके लिए अनिवार्य है । मैंने मढ़ौरा के डी0एस0पी0 से इस पर पुछा इसलिए मैं सरकार से जानना चाहता हूँ कि सरकार उस जगह पर बनाना चाहती है ओ0पी0 या नहीं?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, जनक बाबू बहुत बड़े क्रांतिकारी आदमी हैं । इनका तो देख ही रहे हैं हमलोग चेहरा, शक्ल, सूरत, जैसा जैसा करते हैं। उत्तर मैं पढ़ रहा हूँ..

श्री जनक सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये श्रेष्ठ हैं और हम आदर करते हैं लेकिन हम कौन सा ऐसा काम किये हैं, ये जिसके साथ बैठे हैं, जिस तरीके से ये श्रेष्ठ हमारी माननीय मंत्री हैं, अभिभावक हैं, इस तरह से बोलेंगे, ये हमारे चरित्र पर हनन कर रहे हैं

जिसका चरित्र खराब है उसके साथ सरकार बनाये हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोग के चरित्र की बात करते हैं।

(व्यवधान)

माननीय मंत्री, इस शब्द को वापस लें । पहले वापस लें, किस तरह से इन्होंने बात किया है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप अपना स्थान ग्रहण करें और अपने प्रश्न का जवाब सरकार से सुनिये ।

(व्यवधान)

श्री जनक सिंह: महोदय, हमारे चरित्र में क्या दोष है, क्या हम अपराधी हैं, इस पर उनको जवाब देना पड़ेगा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष: सवाल आपका है। वे जवाब दे रहे हैं सुनिये।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य, मैंने कहा कि प्रश्न काल को चलने दिया जाय । माननीय सदस्य जो प्रश्न पूछे हैं और सरकार जवाब दे रही है, इसमें दूसरा आदमी कभी इंटरफेयर नहीं करें । माननीय मंत्री गृह विभाग।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शांति बनाईए । आप स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, लोकतंत्र की यही खुशबू है कि विभिन्न पार्टियों के लोग भी आपस में परस्पर हंसी मजाक भी थोड़ा बहुत करते हैं । इस पर बहुत ज्यादा उत्तेजित होने का कोई औचित्य नहीं हैं । अब, अभी देख लीजिये महोदय कि ये कान में ईयर फोन लगाये हुए हैं जबकि हाउस चल रहा है, कोई कान में नहीं लगाये हुए हैं लेकिन ये लगाये हुए हैं, खैर छोड़िये ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: आप सुनिये न जवाब।

(व्यवधान)

जनक बाबू बैठिये ।

(व्यवधान)

समय बर्बाद करने से क्या फायदा है । सुनिये न उनका जवाब । आप अपना स्थान ग्रहण कीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: महोदय, मैं उत्तर पढ़ देता हूँ जिसे सम्पूर्ण सदन के लोग सुनेंगे । वस्तुस्थिति यह है कि माझोपुर चौक से तरैया थाना की दूरी 06 कि0मी0 है तथा

अमनौर थाना की दूरी 05 कि0मी0 है । सड़क मार्ग संतोषजनक स्थिति में है । माझोपुर चौक से तरैया थाना पहुँचने में मात्र 6-8 मिनट एवं माझोपुर चौक से अमनौर थाना पहुँचने में मात्र 8-10 मिनट का समय लगता है । विगत पाँच वर्षों में हत्या-03, लूट-03, डकैती-00, गृहभेदन-00 एवं चोरी की-03 घटनाएँ घटित हुई है, परन्तु स्थानीय पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई के साथ-साथ गश्ती, बिट गश्ती, सुपर पेट्रोलिंग किये जाने पर अपराध नियंत्रण में है ।

वर्तमान में माझोपुर चौक पर ओ0पी0 बनाने की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है ।

श्री जनक सिंह: महोदय, मेरा कहना है कि 5-6 थाना से जो अपराधी लूटकर या डकैती कर या जो भी घटना करते हैं, उसके लिए इतना आसान हो जाता है कि वहां से अनेकों जगह निकल जाते हैं इसीलिए मैंने डी0एस0पी0, मढ़ौरा से यह बात किया और उन्होंने भी कहा कि इस स्थान के लिए यहां पर ओ0पी0 होना अनिवार्य है । मैं सदन के सामने कह रहा हूँ, सभी माननीय सदस्यों की उपस्थिति में कह रहा हूँ। वहां पर डी0एस0पी0ने कहा, हमने कहा कि यह स्थान पर अनिवार्य है इसलिए कि वहां खाली पड़ता है और अपराधी अपराध कर के वहां से सीधे बाहर की ओर निकल जाते हैं और जो सात- मिनट की बात करते हैं, वह करीब करीब 15-20 मिनट लग जाता है इसलिए मै सरकार से ..

अध्यक्ष: जनक बाबू, एक प्रश्न पर इतना समय लेंगे तो बाकी सदस्यों का क्या होगा । सरकार के यहां कोई योजना नहीं है आप स्थान ग्रहण करें।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2113(श्री प्रेम शंकर प्रसाद,क्षेत्र सं0-99,बैकण्ठपुर)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: वस्तुस्थिति यह है कि गोपालगंज जिलान्तर्गत बैकुण्ठपुर थाना भवन के कार्य को वादी 1. वशिष्ट नारायण सिंह, पे0-स्व0 रामपुकार सिंह, सा0-सिरसा, थाना-बैकुण्ठपुर एवं अन्य बारह व्यक्तियों द्वारा माननीय न्यायालय सब-जज गोपालगंज के न्यायालय में बैकुण्ठपुर थाना के भूमि का मामला विविध वाद संख्या-26/21 एवं मूल हकीयत वाद संख्या-481/20 में अपील किया गया है, जिसके आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा बैकुण्ठपुर थाना भवन निर्माण कार्य पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया गया है । माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात थाना भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

अध्यक्ष: पूरक पूछिये।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद: पूरक नहीं हैं। जवाब मुझे मिल गया है,मंत्री जी को धन्यवाद ।

अध्यक्ष: जवाब मिल गया है?

श्री प्रेम शंकर प्रसादः जी।

तारांकित प्रश्न संख्या- 2114(श्री अनिल कुमार,क्षेत्र सं0- 24,बथनाहा,अ0जा0)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री:1- स्वीकारात्मक ।

2- स्वीकारात्मक ।

3- इस तरह का कोई प्रावधान नहीं है ।

अध्यक्ष: आप पूरक पूछिये ।

श्री अनिल कुमारः हमें मंत्री जी से यह पूछना है कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के द्वारा आयोजित बिहार पुलिस अवर निरीक्षक एवं प्रारक्ष अवर निरीक्षक में मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 से0मी0 तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग,अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति पुरूषों के लिए सामान्य से 5 से0मी0 कम यानी न्यूनतम ऊंचाई 160 से0मी0 निर्धारित किया गया है । महोदय, जब पुरूषों के लिए ये ऊंचाई निर्धारित किया गया है तो फिर महिलाओं में सामान्य जाति से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति महिलाओं को 5 से0मी0 छूट क्यों नहीं दिया जायेगा?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादवः महोदय, उत्तर स्पष्ट है इस तरह का न कोई प्रावधान है ,न कोई विचार है नियम है, उसी के अनुसार हो रहा है।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य,आप बैठ गये न?

श्री नंद किशोर यादवः महोदय, जवाब तो इनका देख ही लिया लेकिन महोदय, हम प्रश्न करते ही क्यों हैं । हम जन समस्याओं को उठाते हैं इसके माध्यम से और सरकार से प्रश्नों के माध्यम से जानकारी प्राप्त करते हैं और अपनी जानकारी के आधार पर सरकार से अपेक्षा करते हैं कि वह उसके आलोक में समुचित निर्णय करे । ये जब जबाब आता है कि कोई निर्णय नहीं है, कोई नीति नहीं है तो हम भी यही कहना चाह रहे हैं । प्रश्न को ही आप पढ़िये तो प्रश्न में ही साफ लिखा है कि विचार रखती है,नहीं तो विचार रखिये । विचार रखने के लिए आग्रह करना चाहते हैं और आप तो बड़ा संवेदनशील मंत्री हैं, पहले मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव,मंत्री: सुन लिया आपकी बात। सवाल है कि हाईट घटाने का काई विचार नहीं है तो ये मैंने कहा, उत्तर स्पष्ट लिखा हुआ है पहले इनके प्रश्न को ही देखिये महोदय, क्या यह बात सही है कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 165 से0मी0 तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित

जनजाति पुरूषों के लिए सामान्य से 5 से0मी0 कम यानी न्यूनतम ऊंचाई 160 से0मी0 निर्धारित किया गया है तथा सभी वर्गो के महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 155 सें0मी0 निर्धारित किया गया है तो स्पष्ट तो है कि महिलाओं के लिए 5 से0मी0 कम ऊंचाई है। अब इस पर विचार करने की कोई गुंजाईश नहीं है।

श्री नंद किशोर यादवः महोदय, बहुत संवेदनशील मामला है और इनलोगों के नौकरी का विषय है। माननीय मंत्री महोदय, मैं ये आग्रह करना चाहता हूँ, आप पढ़िये । आपने लिखा है सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के लिए 165 से0मी0 रखा है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति पुरूषों के लिए आपने 5 से0मी0 कम करके 160 से0मी0 रखा है लेकिन सभी वर्गो के महिलाओं के लिए 155 से0मी0 रखा है तो विचार करिये आप कि जो अति पिछड़ी जाति है अनुसूचित जाति है अनुसूचित जनजाति है उनकी महिलाओं को भी केवल 5 से0मी0 की ही छूट मिलने वाली है और सामान्य वर्ग और पिछड़े वर्ग की महिलाओं को 10 प्रतिशत की छूट मिलने वाली है, ये जो विसंगति है, उसको दूर करने की बात हम कर रहे हैं महोदय । आप प्रश्न को पढ़िये । आप क्या जवाब दे रहे हैं मैं इसकी विसंगति की बात कर रहा हूँ। मैं जबर्दस्ती घटाने की बात नहीं कर रहा हूँ ।

(क्रमशः)

टर्न-5/मधुप/20.03.2023

..क्रमशः...

श्री नन्द किशोर यादव : इसलिए इस प्वायंट पर ध्यान देने की आवश्यकता है । मैं इसका आपसे आग्रह कर रहा हूँ । आप कहते हैं कि सरकार महिलाओं के प्रति काफी संवेदनशील हैं तो संवेदनशीलता दिखाइये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, मैं फिर से पढ़ देता हूँ । सुनते नहीं हैं, थोड़ा सुनिये ।

श्री नन्द किशोर यादव : आप फिर से पढ़िये, आप गौर से पढ़िये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करिये ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : प्रश्न में ही है, इन्होंने जो प्रश्न किया है उसी को मैं पढ़ रहा हूँ, मैं उत्तर नहीं पढ़ रहा हूँ । प्रश्न ही इन्होंने किया है कि क्या यह बात सही है कि मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा में सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के लिए न्यूनतम ऊँचाई 165 सेंटीमीटर तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित-जनजाति पुरूषों के लिए सामान्य से 5 सेंटीमीटर कम यानी न्यूनतम ऊँचाई 160 सेंटीमीटर निर्धारित

किया गया है । इसमें विसंगति कहाॅं है ? जिनका यह माॅंग कर रहे हैं उनका 5 सेंटीमीटर पहले से कम है ।

श्री नन्द किशोर यादव : महोदय, आप पढ़िये । खुद आपको समझ में आयेगा कि मैं क्या कह रहा हूॅं । मैं कह रहा हूॅं कि जो सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूष हैं उनके लिए 165 सेंटीमीटर और उस वर्ग की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर, ठीक है । इसमें क्लीयर है । लेकिन अनुसूचित जाति और जनजाति के पुरूष हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरूष हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर और उनकी महिलाओं के लिए भी 155 सेंटीमीटर । तो मैं कह रहा हूॅं कि सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरूषों की तुलना में उनकी महिलाओं को 10 सेंटीमीटर की छूट है लेकिन अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं को उनके वर्ग के पुरूषों की तुलना में केवल 5 सेंटीमीटर की छूट है । यह जो विसंगति है उसको दूर करने की बात मैं कह रहा हूॅं । महोदय, यह गंभीर विषय है, जवाब को हल्के में नहीं दिया जाय । विचार कीजिये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने सरकार के सामने अपने पक्ष को रख दिया, अब सरकार उसकी जाॅंच-पड़ताल करेगी । अब माननीय सदस्य श्री जनक सिंह ।

(व्यवधान)

नहीं, अब आप नहीं पूछ सकते हैं, आप बैठ गये हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न संख्या-2115, श्री जनक सिंह (क्षेत्र सं0 116-तरैया)</u>

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री (लिखित उत्तर) : सारण जिलान्तर्गत ईशुआपुर प्रखंड के निपनियाॅं ग्राम एवं सहवां बाजार के 5 कि0मी0 के दायरे में भारतीय स्टेट बैंक की 01 शाखा तथा 6 ग्राहक सेवा केन्द्र स्थित है । इनके माध्यम से यहां के निवासियों को बैंकिंग सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

इनके अतिरिक्त ईशुआपुर प्रखंड अन्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक की 01 शाखा, केनरा बैंक की 01 शाखा, एच0डी0एफ0सी0 बैंक की 01 शाखा तथा उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक की 01 शाखा अर्थात कुल 05 शाखाएं एवं विभिन्न बैंकों की 14 ग्राहक सेवा केन्द्र कार्यरत है ।

मूलतः बैंक शाखा/आउटलेट खोलने का निर्णय बैंकों के द्वारा व्यावसायिक उद्देश्यों एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर लिया जाता है ।

अध्यक्ष : उत्तर मुद्रित है । पूरक पूछिये ।

श्री जनक सिंह : महोदय, उत्तर आया हुआ है । मैंने अपने विधान सभा क्षेत्र के ईशुआपुर प्रखंड के अन्तर्गत निपनियाॅं एवं सहवां में बैंक शाखा खोलने का आग्रह किया है, उसमें

सरकार का जवाब आया है कि यहाँ अभी नहीं खोला जायेगा और उन्होंने बताया है कि इस प्रखंड के अन्तर्गत एक स्टेट बैंक, एक केनरा बैंक और एक एच0डी0एफ0सी0 बैंक, जो कि नहीं है और फिर दूसरा है ग्रामीण बैंक इन्होंने दो दिखाया है । देखिये उत्तर है, वहाँ ईशुआपुर के अंदर तीन ग्रामीण बैंक है लेकिन कैसे सरकार अपनी खूबी को भी छिपा रही है, तीन ग्रामीण बैंक हैं और रिपोर्ट देखिये किस प्रकार का है कि दो ग्रामीण बैंक हैं जबकि ईशुआपुर में सरवारा में और छपिया में तीन ग्रामीण बैंक है ।

हमारा यह कहना है कि निपनियाँ और सहवां जो है, वह इन बैंकों से काफी दूरी पर हैं । आबादी वहाँ बहुत अधिक है निपनियाँ और सहवां में और कारोबारी भी लोग हैं । प्राय: घटनाएँ घट रही हैं, यहाँ के लोग सामकोरिया जाते हैं या अन्य स्थान पर जाते हैं, मढ़ौरा जाते हैं ।

अध्यक्ष : आप पूरक पूछिये । पूरक दो से तीन लाईन में होता है, आप पूछियेगा सरकार उसका जवाब देती है ।

श्री जनक सिंह : यहाँ के लोग मढ़ौरा जाते हैं, मढ़ौरा बैंक में जाते हैं, खाता भी जाँच करवा सकते हैं । मेरा यह कहना है कि सहवां और निपनियाँ कम से कम इन दोनों में किसी एक स्थान पर एक राज्यस्तरीय बैंक होना चाहिए, नेशनल स्तर पर बैंक होना चाहिए । मेरा यही आपसे कहना है चूंकि यहाँ आबादी है, यहाँ के लोग मढ़ौरा जाते हैं ।

अध्यक्ष : आपका यही सप्लीमेंट्री है ? आप स्थान ग्रहण करें । माननीय मंत्री जी ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, हमने तो उत्तर में बताया है कि दोनों गाँव के पास जो समकोरिया गाँव है वहाँ पर स्टेट बैंक की एक शाखा है जहाँ से सहवां की दूरी 3 कि0मी0, निपनियाँ की दूरी 5 कि0मी0 है, यह पहली बात । दूसरी बात, अन्य बैंकों की जो वहाँ ग्राहक सेवा केन्द्र चल रहे हैं आसपास में, 5-6 चल रहे हैं, उसकी भी बात हमने कही है और तीसरी बात महोदय, आज हम आसन के माध्यम से सदन को जानकारी भी देना चाहते हैं, जहाँ तक बैंकों की शाखाएँ खोलने का प्रश्न है, यह मुख्यमंत्री जी के निर्णयानुसार बिहार सरकार ने जो बैंकों से काम करने की आपस में एक समिति होती है, बैंकों के क्रियाकलाप की समीक्षा करने की जो एस0एल0बी0सी0 होती है, State Level Banker's Committee उसमें हमलोगों ने पारित करके अनुशंसा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय और इनका एक डी0एफ0एस0 जो होता है Directorate of Financial Services उसको हमलोगों ने भेजा है कि मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि हर पंचायत में कम से कम एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खुले और इतना ही नहीं, यह खुलने की स्थिति को सुगम बनाने के लिए

इन्होंने यहाँ तक ऑफर दे दिया है कि अगर जहाँ भूमि, भवन और ब्रांच खुले, यह सी0एस0पी0 नहीं जो ग्राहक सेवा केन्द्र होता है उसकी बात मुख्यमंत्री जी ने नहीं की है, इन्होंने जो बी0एम0 ब्रांच कहते हैं Brick and Mortar मतलब एक पक्के मकान में विधिवत शाखा खुले, उसके लिए इन्होंने यहाँ तक ऑफर दे दिया है कि हम जो पंचायतों में पंचायत सरकार भवन बना रहे हैं, जो ग्राम पंचायत स्तर पर एक सरकार की परिकल्पना है, वहाँ पर पंचायत स्तर के सारे जन-प्रतिनिधि हों, अधिकारी हों उनके बैठने की व्यवस्था है, यह सरकार की तरफ से हमने भारत सरकार, वित्त मंत्रालय को ऑफर दिया है कि अगर आप बैंक शाखा वहाँ खोलवाते हैं तो हम उसके लिए भूमि ही नहीं भवन भी आपको निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे ।

महोदय, इससे अधिक सरकार क्या कर सकती है ? मामला तो आप लोगों को वहाँ से करवाना है, वहाँ से निर्णय करवा दीजिये क्योंकि बैंकों की शाखा खोलना किसी राज्य सरकार के निर्णय पर नहीं निर्भर करता है, बैंक की शाखा हमेशा बैंक वहाँ की जो व्यावसायिक व्यवहार्यता होती है, जो वहाँ की कॉमर्शियल फिजिबलिटी होती है, उसको देखकर संबंधित बैंक ही निर्णय करते हैं । हमलोग अनुशंसा करते हैं और जहाँ तक अनुशंसा की बात है, हमने आपको विस्तार से बता दिया है कि बिहार सरकार और मुख्यमंत्री जी की विशेष रूप से सोच है, सोच नहीं है ऑफर है । उन्होंने कहा है कि अगर सरकार या वहाँ वित्त मंत्रालय निर्णय लेता है, बैंकों को निदेश देता है तो हमलोग उसको भूमि/भवन सब निःशुल्क उपलब्ध करा देंगे, हर पंचायत में एक राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा खुले । आप थोड़ी पहल वहाँ भी कर दीजिये, आपके यहाँ भी खुल जायेगा ।

अध्यक्ष : माननीय मुख्यमंत्री जी के कदम सराहनीय हैं । सब लोग मिल-जुलकर लगें और भारत सरकार के यहाँ जो ये लिखे हैं, वहाँ से स्वीकृति मिल जाय ताकि कॉमर्शियल बैंक खुल सकें ।

श्री जनक सिंह : महोदय, सदन के माध्यम से आम आवाम की समस्याएँ जहाँ भी जायं लेकिन हमारा यह कहना है कि जनहित में इन स्थानों पर बैंक खोलना अनिवार्य है। आप सीधे भारत सरकार पर बात रखकर पल्ला झाड़ते हैं । हमारी बात कम से कम यहाँ पर बैंक खोलने की इच्छा सरकार रखती है या नहीं ?

अध्यक्ष : सभी जगहों पर सरकार खोलने की बात कह रही है, सरकार कह रही है सभी जगहों पर ।

श्री जनक सिंह : महोदय, सरकार यहाँ से भारत सरकार को भेजेगी या नहीं ?

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा ।

(व्यवधान)

जवाब दे दिये तो अब क्या है ? माननीय सदस्य श्री नीतीश मिश्रा ।

तारांकित प्रश्न संख्या-2116, श्री नीतीश मिश्रा (क्षेत्र सं0-38, झंझारपुर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री (लिखित उत्तर) : 1- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष, 2020 में खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) के आलोक में राज्य सरकार की सेवाओं में समूह 'ग' के निम्नवगर्गीय लिपिक के 185 (एक सौ पचासी) पदों एवं कार्यालय परिचारी के 121 (एक सौ इक्कीस) रिक्त पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 29.08.2020 को विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये गये ।

रिक्तियों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति किसी संवर्ग में कुल बल (मूल कोटि) के 10 प्रतिशत के अंतर्गत की जानी है जबकि कतिपय कार्यालयों के रिक्ति की गणना कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत की गई है । साथ ही बहुत कम विभागों/जिला कार्यालयों से सूचना प्राप्त थी । अतएव विभिन्न विभागों/जिलों से पूर्व में भेजी गई रिक्ति में संशोधन कर मूल कोटि के 10 प्रतिशत के अंतर्गत रिक्त पदों की सूचना मांगी गई। किंतु पुनः समीक्षा में यह पाया गया कि प्रोन्नति के लिए आरक्षित पदों को समाहित करते हुए रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराई गई है ।

अतएव पुनः प्रोन्नति के लिए आरक्षित पदों को हटाते हुए खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु कुल बल (मूल कोटि) के 10 प्रतिशत के अंतर्गत रिक्ति की माँग की गई । जिसके आलोक में विभिन्न विभागों/जिलों से निम्नवर्गीय लिपिक के 273 (दो सौ तिहत्तर) पदों एवं कार्यालय परिचारी के 510 (पांच सौ दस) रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुई है ।

विगत 7 सालों से खेल कोटे से नियुक्तियों के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि दिनांक-29.08.2020 को खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0-8423/2020, 8272/2020 एवं 8514/2020 की समेकित सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-25.02.2021 को स्थगनादेश (Status quo) पारित किया गया जिसके कारण उक्त विज्ञापन के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई लंबित रही, (प्रति संलग्न) । माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक-25.07.2022 (प्रति संलग्न) को पारित आदेश में नियुक्ति प्रक्रिया को जारी रखने की अनुमति दी गई । जिसके आलोक में खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों के

सत्यापन के पश्चात नियुक्ति हेतु अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । 27 खिलाड़ियों का काउन्सलिंग किया जा चुका है। इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है ।

इसके पूर्व वर्ष 2015 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसके आलोक में 78 (अठत्तर) खिलाड़ियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है ।

2- उत्तर अस्वीकारात्मक है ।

3- वर्ष 2020 में प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में खिलाड़ियों के खेल प्रमाण पत्रों के सत्यापन के पश्चात नियुक्ति हेतु अग्रेतर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। कब्ड्डी खेल विधा के 05 (पाँच) खिलाड़ियों की औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित कर दावा/आपत्ति दिनांक- 10.03.2023 तक आमंत्रित की गयी है तथा 07 खेल विधाओं में 27 खिलाड़ियों का काउन्सलिंग किया जा चुका है । इनकी नियुक्ति की प्रक्रिया अंतिम चरण में है ।

इसके पूर्व वर्ष 2015 में उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था जिसके आलोक में 78 (अठत्तर) खिलाड़ियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में बॉक्सिंग खेल विधा के 05 (पाँच) खिलाड़ियों की औपबंधिक मेधा सूची प्रकाशित कर दावा/आपत्ति दिनांक- 10.03.2023 तक आमंत्रित की गयी है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बहुत डिटेल्ड उत्तर दिया है । मेरा मूल प्रश्न, जो बिहार सरकार की नियमावली है जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा देने के संबंध में यह प्रश्न है और माननीय मंत्री जी ने बहुत विस्तृत उत्तर भी दिया है ।

अध्यक्ष महोदय, सिर्फ दो-तीन पूरक मेरा है कि 2014 में बिहार सरकार ने नियमावली बनायी थी, अभी राज्य मंत्रिपरिषद् ने अफसर ग्रेड के लिए भी निर्णय लिया है, वह भी सराहनीय है । मेरा मूल प्रश्न है कि 2014 में जो नियमावली बनी जिसमें उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी सेवा में उनको एडजस्ट किया जायेगा, अब तक उसमें कितनी नियुक्तियाँ राज्य सरकार ने की है ? क्योंकि माननीय मंत्री जी के उत्तर में जो थोड़ा-सा यह प्रतीत हो रहा है कि 2014 से अब तक सिर्फ प्रोसेस में टाईम लगा है । जिलों से रिक्तियाँ कितनी हैं उसमें पहले एक संशय था, उसके बाद वह दूर हुआ, फिर माननीय उच्च न्यायालय में मामला गया, माननीय उच्च न्यायालय से जब फ्री हो गया,

...क्रमशः...

टर्न-6/आजाद/20.03.2023

..... क्रमशः .....

श्री नीतीश मिश्रा : उसके बाद भी लगभग 8-10 महीना बीत गये हैं । इसलिए मेरा प्रश्न अध्यक्ष महोदय, यह है कि अब तक कितनी बहालियां हुई हैं, 2014 की जो नियमावली थी और जो रिक्ति इन्होंने कहा है कि 273 निम्नवर्गीय लिपिक और 510 कार्यालय परिचारी, इस नियुक्ति को कितने समय अवधि में सरकार पूर्ण कर लेगी ?

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : महोदय, उत्तर स्पष्ट लिखा हुआ है । माननीय सदस्य का प्रश्न है कि - ‘‘ क्या यह बात सही है कि राज्य सरकार ने खेल कोटे से होने वाली नियुक्ति हेतु सभी जिला पदाधिकारियों से खेल कोटा की रिक्ति की मांग की गई है तथा विगत 7 वर्षों से खेल कोटे से नियुक्तियां नहीं हुई है ? इसका उत्तर है महोदय- वस्तुस्थिति यह है कि वर्ष 2020 में खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा बिहार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति नियमावली, 2014 (यथासंशोधित) के आलोक में राज्य सरकार की सेवाओं में समूह ‘ग’ के निम्नवर्गीय लिपिक के 185 पदों एवं कार्यालय परिचारी के 121 रिक्त पदों पर उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु दिनांक 29.08.2020 को विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित किये गये ।

रिक्तियों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि नियमानुसार उत्कृष्ट खिलाड़ियों की नियुक्ति किसी संवर्ग में कुल बल के 10 प्रतिशत के अन्तर्गत की जानी है जबकि कतिपय कार्यालयों के रिक्ति की गणना कुल बल के 10 प्रतिशत के अंतर्गत की गई है । साथ ही बहुत कम विभागों/जिला कार्यालयों से सूचना प्राप्त थी । अतएव विभिन्न विभागों/जिलों से पूर्व में भेजी गई रिक्ति में संशोधन कर मूल कोटि के 10 प्रतिशत के अंतर्गत रिक्त पदों की सूचना मांगी गई । किंतु पुनः समीक्षा में यह पाया गया कि प्रोन्नति के लिए आरक्षित पदों को समाहित करते हुए रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध कराई गई है ।

अतएव पुनः प्रोन्नति के लिए आरक्षित पदों को हटाते हुए खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु कुल बल (मूल कोटि) के 10 प्रतिशत के अंतर्गत रिक्ति की मांग की गई । जिसके आलोक में विभिन्न विभागों/जिलों से निम्नवर्गीय लिपिक के 273 पदों एवं कार्यालय परिचारी के 510 रिक्त पदों की सूचना प्राप्त हुई है ।

विगत 7 सालों से खेल कोटे से नियुक्तियों के संदर्भ में न्यायालय में मामले डाले गये और न्यायालय का फैसला आ गया है 25.07.2022 को, जल्द ही उसपर कार्रवाई किया जा रहा है, जल्द ही नियुक्ति हो जायेगी ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, बहुत ही विस्तृत उत्तर है, मैंने सदन का समय बचाने के लिए सीधे पूरक ही पूछा था और यह उत्तर मैंने देखा है । इसी उत्तर से मैंने पूरक पूछा है, मेरे मुख्य दो पूरक हैं एक तो जल्द कर लिया जायेगा, 2014 की नियमावली है और हमने स्पष्ट पूछा है कि अब तक कितनी नियुक्तियां हुई हैं ? मैंने स्वयं कहा है कि मामला कंफ्यूजन में था, संशय में था कि पद कितनी है, फिर मामला पटना उच्च न्यायालय में भी गया, उसके बाद भी जब उच्च न्यायालय का फैसला आया, उसके बाद भी लगभग 8-9 माह बीत चुके हैं । इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट जानना चाहा कि आखिर 10 माह के बाद भी आखिर प्रोसेस क्या हुई और अब तक कितनी नियुक्तियां की, जितने पद रिक्त हैं, उसका भी मैंने उल्लेखय किया है और यह माननीय मंत्री जी के ही उत्तर में है । इसके अलावा एक और पूरक है कि इन्होंने लिखा है कि 78 खलाड़ियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई है 2015 में जो विज्ञापन निकाले गये हैं तो जो 2015 के बारे में, माननीय मंत्री जी ने अभी 2020 के विज्ञापन का जिक्र किया और 2015 का जिक्र भी इन्हीं के उत्तर में है, उसमें 78 खिलाड़ियों की नियुक्ति की अनुशंसा की गई थी तो जो अनुशंसा की गई थी उनकी ज्वाईनिंग हुई है या नहीं हुई है, यह भी मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : कहां है इस प्रश्न में कि 78 की अनुशंसा की गई है ?

श्री नीतीश मिश्रा : यह आपके उत्तर में है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : उत्तर में कहां है ?

श्री नीतीश मिश्रा : आपके उत्तर में है, मैं विधान सभा से डाऊनलोड किया है ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : सुनिए न विधान सभा का । विगत 7 सालों से खेल कोटे से नियुक्तियों के संदर्भ में उल्लेखनीय है कि दिनांक 29.08.2020 को खिलाड़ियों की नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना द्वारा विज्ञापन प्रकाशित किया गया है किंतु माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0सं0-8423/2020, 8272/2020 एवं 8514/2020 की समेकित सुनवाई में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 25.02.2021 को स्थगनादेश पारित किया गया जिसके कारण उक्त विज्ञापन के आलोक में नियुक्ति की कार्रवाई लंबित रही और फिर हमने कहा कि माननीय

उच्च न्यायालय का फैसला दिनांक 25.07.2022 को आ गया और अभी 2023 है, अभी कार्रवाई की जा रही है ।

श्री नीतीश मिश्रा : अध्यक्ष महोदय, ...

श्री नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री : एक मिनट हम आपको बता देते हैं । खिलाड़ियों की बहाली कब शुरू हुई, सुनिए । बात को भूल रहे है । जब श्रद्धेय अटल जी की सरकार थी और उनके सरकार में जब हम रेल मंत्री थे तो हमने रेल मंत्रालय में खिलाड़ियों को नौकरी देने का काम शुरू किया सबसे पहले इस देश में और जब हम यहां आये, आपलोग तो साथ ही थे तो हमने बिहार में भी कह दिया कि खिलाड़ियों को नौकरी हम देंगे तो यह काम तो किया ही जा रहा है तो काहे इनसे आपलोग पूछ रहे हैं । कभी किसी को दिक्कत होगा तो ये बता सकते हैं । ये जानते नहीं है क्या, सब लोग जानते हैं । आपलोग तो थे ही, फिर आपलोग पूछ रहे हैं । हम तो चुपचाप बैठे हुए थे ।

लेकिन हां एक सवाल जो पूछा है भाई, आपका जो सवाल था और इन्होंने जो जवाब दिया, प्रश्न सं0-2114 वाला भी हम आपका देखे हैं, आपलोगों की बात हम सुन रहे हैं । ठीक है आपका सुझाव है, इसपर हम तत्काल करवाते हैं ।

<u>तारांकित प्रश्न सं0-2117(श्री विनय कुमार,क्षेत्र सं0-225,गुरूआ)</u>

(लिखित उत्तर)

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, मंत्री : 1. अस्वीकारात्मक है । ज्ञातव्य हो कि सर्विस प्लस पोर्टल का सर्वर केन्द्रीयकृत रूप से स्टेट डाटा सेंटर पटना में स्थापित है । अत: सर्वर स्पीड समान रूप से राज्य के सभी प्रखंडों में परिलक्षित होगा । यह भी पाया गया है कि 1 जनवरी, 2023 से 28 फरवरी, 2023 तक गुरूआ में 6798, गुरारू में 5789 एवं परैया में 4886 आवेदन प्राप्त हुआ था, जो कि समय-सीमा के अन्तर्गत निष्पादित भी कर लिये गये ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री विनय कुमार जी अधिकृत किया है श्री सतीश कुमार जी को, सतीश कुमार जी, आप पूरक पूछिए ।

श्री सतीश कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्राप्त है । इन्होंने आर0टी0पी0एस0 काऊंटर पर स्पीड को लेकर के, सर्वर डाऊन को लेकर के सवाल पूछे थे कि परैया, गुरारू और गुरूआ में लेकिन पूरे बिहार में सर्वर डाऊन की समस्या रहती है महोदय, इन्होंने अस्वीकार किया है प्रश्न को, क्या ऐसा कोई टॉल फ्री नम्बर जेनरेट करने का माननीय मंत्री जी विचार रखते हैं, जिससे कि सर्वर डाऊन हो तो आम जनता

उसको भेरीफाई कर सके या कम्प्यूटर ऑपरेटर जो बोल दे, उसको सही मानकर के वे घर चल जाते हैं और रोजाना परेशान किया जाता है ।

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, मंत्री : महोदय, अस्वीकारात्मक हमने इसलिए लिखा है कि चूँकि सिर्फ जनवरी एवं फरवरी माह में गुरूआ में 6798, गुरारू में 5789 एवं परैया में 4886 आवेदन स्वीकृत किये गये हैं और 100 प्रतिशत उसका कमप्लायंस भी हुआ है, इसलिए हमने अस्वीकारात्मक लिखा है और टॉल फ्री नम्बर है, माननीय सदस्य हमसे मिलेंगे, हम इनको बता देंगे ।

श्री सतीश कुमार : माननीय मंत्री महोदय से हम कहेंगे कि अगर टॉल फ्री नम्बर है तो उस काऊंटर पर लिखा जाय कि इसपर आम जनता भी इस टॉल फ्री नम्बर की सुविधा ले सके । इस तरह से गुपचुप तरीके से टॉल फ्री नम्बर रखने का क्या मतलब है महोदय ?

श्री मोहम्मद इसराईल मंसूरी, मंत्री : महोदय, यह ऑनलाईन है, ऐसा नहीं है । इनको बता दिया जायेगा, यह सार्वजनिक है । चूँकि क्वेश्चन में यह अंश नहीं है, नहीं तो हम इनको अभी बता देते ।

अध्यक्ष : माननीय नेता, प्रतिपक्ष ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में हैं और अभी आई0टी0 मिनिस्टर के संदर्भ में मुजफ्फरपुर में जो इनपर एफ0आई0आर0 के लिए ....

अध्यक्ष : नहीं-नहीं । आप स्थान ग्रहण करें । अभी प्रश्नकाल चल रहा है, जो आप अभी पूछ रहे हैं, वह सामयिक नहीं है । इसलिए माननीय सदस्या श्रीमती नीतु कुमारी, अपना प्रश्न पूछें ।

(व्यवधान)

आप स्थान ग्रहण करें । यह नहीं चलेगा । अभी प्रश्नकाल है । प्रश्नकाल को चलने दिया जाय । माननीय सदस्या श्रीमती नीतु कुमारी ।

तारांकित प्रश्न सं0-2118(श्रीमती नीतु कुमारी,क्षेत्र सं0-236,हिसुआ)

(लिखित उत्तर)

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : स्वीकारात्मक ।

वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नगत कब्रिस्तान की घेराबन्दी वर्ष 2009 में करायी गई है ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के द्वारा रिपोर्ट के बावजूद भी अभी तक कब्रिस्तान का घेराबंदी शुरू नहीं हुआ है । मैं आग्रह करती हूँ कि इसको जल्द से जल्द शुरू करा दिया जाय ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, गृह विभाग ।

श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव, मंत्री : जवाब दिया जा चुका है ।

श्रीमती नीतु कुमारी : अध्यक्ष महोदय, समय सीमा निर्धारित कर दिया जाय कि इसको कब तक कर दिया जायेगा ।

टर्न-7/शंभु/20.03.23

अध्यक्ष : अब तारांकित प्रश्न का समय समाप्त हुआ । माननीय सदस्यगण, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देना चाहता हूँ कि सरकार से आज भी सभी विभागों के शत-प्रतिशत उत्तर प्राप्त हुए हैं । माननीय सदस्यगण, अब प्रश्नोत्तरकाल समाप्त हुआ, जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हों उन्हें सदन पटल पर रख दिये जाएं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : असामयिक है, बिलकुल असामयिक है । अब कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जायेगी । माननीय सदस्यगण, आज दिनांक 20 मार्च, 2023 के लिए निम्न माननीय सदस्यों से कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है । श्री संजय सरावगी, श्री जनक सिंह, श्री पवन कुमार जायसवाल, श्रीमती गायत्री देवी, श्री राणा रणधीर सिंह, डा0 निक्की हेम्ब्रम, श्री अरूण शंकर प्रसाद एवं श्री केदार प्रसाद गुप्ता । आज सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में सम्मिलित अनुदानों की मांग पर वाद-विवाद एवं मतदान का कार्यक्रम निर्धारित है । अतः बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-172(3) एवं 47(2) के तहत नियमानुकूल नहीं होने के कारण कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सभी सूचनाओं को अमान्य किया जाता है ।

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : अध्यक्ष महोदय, सदन में कार्य-स्थगन आपने अमान्य कर दिया ये मामला माननीय मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लिये, सारे कागजात भी मांगे हमने उपलब्ध कराया । माननीय मंत्री पर आरोप है कि ये घर पर जाकर धमकाये उसको कि अभी बेटा का हत्या किये हैं अब दामाद का हत्या होगा ।

(व्यवधान)

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्यगण अपने स्थान पर खड़े हो गये।)

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें । नहीं आप बैठिए, आप स्थान ग्रहण कीजिए माननीय नेता प्रतिपक्ष । आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री मुकेश कुमार रौशन : महोदय, अभी बारिश होने के कारण काफी तूफान आया है, ओलावृष्टि हुआ है । वैशाली जिला के महुआ एवं कई प्रखंडों में गेहूं एवं आलू का फसल बर्बाद हुआ है किसानों के हित में मुआवजा देने की मांग करता हूँ ।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल होगा । माननीय सदस्य श्री गोपाल रविदास, अपने शून्यकाल की सूचना को पढ़ें । अब शून्यकाल की कार्यवाही चल रही है ।

शून्यकाल

श्री गोपाल रविदास : महोदय, पटना जिला अन्तर्गत प्रखंड फुलवारी शरीफ स्थित ग्राम बभनपुरा मुख्य रोड से ग्राम धुपारचक तक नहर पर पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप तो बोल ही देते हैं सुन ही लिये, अब क्या है ? आपने कहा सदन ने सुन लिया। अब स्थान ग्रहण कीजिए । आप डिप्टी सी0एम0 रहे हैं । एक आदमी खड़ा होकर कहेगा और बिना तैयार हुए आप जवाब दे दीजिएगा ? ऐसा होता है ? नहीं नियम नहीं है ऐसा नहीं है ।

श्रीमती मंजु अग्रवाल : महोदय, गया जिलान्तर्गत शेरघाटी प्रखंड के सत्संग नगर कोल्ड स्टोर से आमस प्रखंड के ग्राम वाजितपुर के बीच मोरहर नदी में पुल का निर्माण कराने की मांग करती हूँ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप बैठें, आप स्थान ग्रहण करें । आपका 50 शब्दों से ज्यादा था इसलिए आपके शून्यकाल को अमान्य किया गया । आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री सउद आलम : महोदय, किशनगंज जिला के ठाकुरगंज प्रखंड अन्तर्गत ठाकुरगंज बस्ता कोल्हा आर0डब्लू0डी0 पथ के बरचौंदी कब्रिस्तान के निकट से चिकचिका, मीराभीटा, घेघाटोली होते हुए मुर्गीहारा तक 5 कि0मी0 पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने की मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा,ने0वि0द0 : इस विषय पर सरकार मौन बैठी है.......

अध्यक्ष : आप सुनिये । यह शून्यकाल हो रहा है, नियम और प्रक्रिया को तोड़ने की कोशिश नहीं किया जाय । मैं शून्यकाल पढ़वा रहा हूँ इसमें जिसको मैं पुकारूँगा वे अपना शून्यकाल पढ़ेंगे । श्री सुरेन्द्र मेहता, माननीय सदस्य- नहीं हैं । श्री महानंद सिंह, माननीय सदस्य, अपने शून्यकाल की सूचना को पढ़ें ।

श्री महानंद सिंह : महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग में कई कार्य जोड़कर ग्लोबल निविदा से बड़े संवेदक के लिए ही जगह बनाया जा रहा है, छोटे संवेदकों के लिए कोई मौका नहीं मिलता है । सरकार से छोटे संवेदकों के लिए भी कार्य हेतु निविदा की मांग करता हूँ ताकि अधिकतर बेरोजगारों को रोजगार मिले ।

(इस अवसर पर विपक्ष के माननीय सदस्य अपने स्थान पर बैठ गये ।)

श्री श्याम बाबू प्रसाद यादव : महोदय, पूर्वी चम्पारण जिला के पिपरा विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत तेतरिया प्रखंड क्षेत्र में 17 मार्च को सुबह 4:30 बजे भारी बर्फबारी होने से मक्का, गेहूं, तिलहन एवं अन्य फसलों का भारी नुकसान हुआ है । हम सरकार से मांग करते हैं कि इसका आकलन कराकर जल्द ही मुआवजा दिया जाय ।

श्री अमरजीत कुशवाहा : महोदय, सिवान सहित पूरे बिहार के नगरपालिका, नगर परिषद् एवं नगर पंचायत सफाई कर्मियों का तीन माह का बकाया वेतन का भुगतान करते हुए

डेली वेजेज पर कार्यरत कर्मियों का मानदेय 18 हजार रूपये प्रति माह न्यूनतम मजदूरी करने की मांग करता हूँ ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, पठन-पाठन, विज्ञान, संस्कृति एवं अन्तर्राज्जीय खेलकूद के क्षेत्र में प्रतिष्ठित भोजपुर जिला अन्तर्गत तारामणि भगवान साव प्लस टू विद्यालय, कोइलवर को सड़क निर्माण के लिए सरकार 2019 में जमींदोज कर दी थी । पुनर्निर्माण के लिए सड़क पर स्कूल आंदोलन हुआ था । सरकार से स्कूल निर्माण की मांग करता हूँ ।

श्री वीरेन्द्र कुमार : महोदय, समस्तीपुर जिला अन्तर्गत रोसड़ा बाइपास दक्षिणी वाया एस0एच0-55 नजदीक धर्मकांटा से एस0एच0-55 दौलतपुर तक एवं मब्बी चौक से एस0एच0-55 सागी मोड़ तक बाइपास का निर्माण कराने की मांग सरकार से करता हूँ ।

श्री मुरारी मोहन झा : महोदय, दरभंगा जिला के सिंहवारा प्रखंड अन्तर्गत अरई विरदीपुर पंचायत के अरई ग्राम में रामकरण सहनी के घर से बनौली सीमा मस्सो पाकर तक नदी के तटबंध का मिट्टीकरण किया जाय । यह मैं मांग करता हूँ ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : झा जी, स्थान ग्रहण किया जाय, यह शून्यकाल है । इसपर बहस नहीं किया जाता है।

श्री संजय सरावगी : महोदय, राज्य के 600 से उपर इंटर स्तरीय एवं अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों को इंटर स्तरीय छात्रों के उत्तीर्णता के आधार पर मिलने वाली अनुदान की राशि 2015 से नहीं मिलने के कारण शिक्षकों, कर्मचारियों का जीवन भुखमरी के कगार पर है । सरकार अविलंब अनुदान की राशि का भुगतान करें ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : सरकार काफी गंभीरता से आपकी बातों को सुन रही है ।

श्री जयप्रकाश यादव : महोदय, अररिया जिलान्तर्गत नरपतगंज नगर पंचायत के वार्ड नं0-16 में एन0एच0-57 से बिहारी पासवान के घर तक भीसी पर जनहित में सड़क निर्माण की मांग सदन के माध्यम से करता हूँ ।

श्री अरूण सिंह : महोदय, रोहतास जिलान्तर्गत बिक्रमगंज में एक मात्र ऊर्दू मध्य विद्यालय है । इस ऊर्दू मध्य विद्यालय को टेन प्लस टू में उत्क्रमित करने की मांग करता हूँ ।

टर्न-8/पुलकित/20.03.2023

श्रीमती प्रतिमा कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, वैशाली जिलान्तर्गत राजापाकर प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी श्री मृत्युंजय कुमार चार वर्षों से पदस्थापित हैं, उनके विरूद्ध सरकारी योजनाओं में अपने रिश्तेदार की एजेंसी के द्वारा वित्तीय घपला की

जनशिकायतें हैं, मैं सदन के माध्यम से शिकायतों की जांच कर अविलम्ब सख्त कार्रवाई की मांग सरकार से करती हूं ।

श्री पवन कुमार जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, सरकार मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत पर पन्द्रहवें/षष्ठम वित्त आयोग की राशि में से वार्ड सदस्यों, पंचायती समिति सदस्य/जिला परिषद सदस्यों को क्षेत्रवार कार्यों के क्रियान्वयन हेतु राशि कर्णांकित करें ताकि सभी क्षेत्रों का विकास हो सकें ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राजवंशी महतो जी आप अपना शून्यकाल पढ़ें ।

श्री राजवंशी महतो : माननीय अध्यक्ष महोदय, बेगूसराय जिलांतर्गत हरिहर महतो उच्च विद्यालय अमारी, छोड़ाही को छात्रहित में इंटरस्तरीय कोड आवंटित करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्री रामबली सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, जहानाबाद जिला के हुलासगंज प्रखण्ड अंतर्गत सुरूजपुर पंचायत के भवानीपुर गांव के पास जलवार नदी से पईन निकलती है । निकास स्थल पर छिलका निर्माण होने से आस-पास के आधा दर्जन गांव का खेत सिंचित होगा ।

अत: सरकार से छिलका निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री मुकेश कुमार यादव : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला प्रखण्ड नानपुर, ग्राम- बहेराजाहिदपुर में 120 परिवार मुसहर समाज का मकान एन0एच0-527 सी0 में अधिग्रहण किया गया है । उक्त सभी परिवार के मकान का मूल्यांकन कर शीघ्र राशि भुगतान कराने तथा उन परिवारों को ग्राम के ही बिहार सरकार की जमीन में बसाने हेतु मांग सरकार से करता हूं ।

श्री राजीव कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिलान्तर्गत तारापुर विधान सभा क्षेत्र के.

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लीजिये । माननीय सदस्य श्री अजीत कुमार सिंह ।

श्री अजीत कुमार सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्य में किसानों से संबंधित योजनाओं का पंचायत स्तर पर प्रसार के लिए 2010 से पंचायत स्तर पर कार्यरत किसान सलाहकारों का समायोजन जनसेवक या ग्रामीण प्रसार कार्यकर्ता के पद पर करने की मांग करता हूं ।

श्री राजीव कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मुंगेर जिला अंतर्गत तारापुर विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत असरगंज प्रखंड में अमैया पंचायत के बैजलपुर गांव में बन रहे अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र में हो रहे विलंब तथा एक वर्ष पड़े कार्य को पुन: प्रारंभ कराने हेतु मैं सरकार से मांग करता हूं ।

मोहम्मद अनजार नईमी : माननीय अध्यक्ष महोदय, किशंनगंज जिलान्तर्गत झुंकी पुल का निर्माण कार्य पूर्ण है । निर्माण कार्य एक वर्ष पूर्व हो जाने के बाद भी विभागीय उदासीनता के कारण एप्रोच नहीं बन सका है, जिस कारण आवागमन बाधित है ।

एप्रोच की भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया पूर्ण कर आवागमन बहाल करने की मांग सरकार से करता हूं ।

श्रीमती गायत्री देवी : अध्यक्ष महोदय, सीतामढ़ी जिला के सोनबरसा प्रखंड अंतर्गत मढ़िया महादेव मठ पर भारी संख्या में लोग आकर जल चढ़ाते हैं ।

अत: सरकार से मांग करती हूं कि मढ़िया महादेव मठ के प्रांगढ़ का सौन्दर्यीकरण कार्य करावें ।

श्री मिश्री लाल यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, दरभंगा जिला के घनश्यामपुर प्रखंड के ग्राम घनश्यामपुर से बुढ़ैव इनायतपुर तक जर्जर सड़क का निर्माण जनहित में आवश्यक है।

अत: उक्त जर्जर सड़क के जीर्णोद्धार के निर्माण करने की सरकार से मांग करता हूं ।

श्री रणविजय साहू : माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्तीपुर जिला के मोरवा प्रखंड में प्रवाहित होने वाली नुन नदी में तटबंध नहीं रहने से चकपहाड़, चकसिकन्दर, गुनाई बसही आदि पंचायतों में प्रत्येक वर्ष एक बड़ी आबादी को विस्थापित होना पड़ता है ।

जनहित में गुनाई बसही से कोठिया पंचायत तक नुन नदी पर बांध निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री सत्यदेव राम : अध्यक्ष महोदय, सिवान जिलान्तर्गत सिवान प्रखंड में कचहरी स्टेशन के पास मैरवा सिवान रोड को लाइन पार करता है । जिससे काफी भीड़ एवं जाम लग जाता है, वहां पर ओवरब्रिज की आवश्यकता है ।

कचहरी स्टेशन के पास ओवरब्रिज बनाने हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजने की राज्य सरकार से मांग करता हूं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपने अपना शून्यकाल पढ़ दिया है, आपका शून्यकाल सुन लिया गया है ।

माननीय सदस्य श्री जनक सिंह ।

(अनुपस्थित)

माननीय सदस्य श्री छत्रपति यादव ।

श्री छत्रपति यादव : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया विधान सभा के मानसी प्रखंड अंतर्गत जनता प्लस-टू उच्च विद्यालय मानसी एवं श्री बनारसी प्लस-टू विद्यालय सैदपुर में भवन के अभाव में बच्चों का पठन-पाठन बाधित है ।

अत: भवन निर्माण कराकर पठन-पाठन सुचारू कराने की मांग करता हूं।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधान सभा क्षेत्रअंतर्गत कटियारी पंचायत के ग्राम कारी प्रहरी प्रोन्नत मध्य विद्यालय के पास फील्ड का समतलीकरण नहीं होने के कारण विद्यालयों के छात्र-छात्राओं एवं आसपास के ग्रामीण खेल से वंचित रहते हैं......

अध्यक्ष : माननीय सदस्या डॉ0 निक्की हेम्ब्रम, आपने शून्यकाल जो दिया था, उस शून्यकाल को आपने नहीं पढ़ा । आपने जो पढ़ा है वह शून्यकाल में नहीं दिया था इसलिए जो आप लिखकर के दें, वही पढ़ें । आपका शून्यकाल यहां है, जिसको आपने नहीं पढ़ा है इसलिए आपको शून्यकाल दिया जाता है, आप उसे पढ़ें ।

डॉ0 निक्की हेम्ब्रम : माननीय अध्यक्ष महोदय, कटोरिया विधानसभा क्षेत्रान्तर्गत दमोदरा पंचायत के आरपाथर सलैया रोड में सलैया गांव के पास पड़रिया नदी में पुल नहीं होने से अनेकों गांव के ग्रामीणों को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

अत: सरकार से उक्त नदी पर पुल निर्माण की मांग करती हूं ।

श्री भाई वीरेंद्र : अध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं, ये जो हमेशा शोर करते हैं कि महिला की देखरेख नहीं की जाती सशक्तीकरण में, अब देखिये अध्यक्ष महोदय ने कितना बढ़िया उदाहरण दिया है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री राणा रणधीर ।

श्री राणा रणधीर : माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्तर बिहार के शिवहर, पूर्वी-चंम्पारण व सीतामढ़ी जिले के 16.03.2023 को आंधी-पानी व भारी ओलावृष्टि से आम, लीची व रबी फसल के किसानों को हुए भारी नुकसान के मुआवजा हेतु सरकार से मांग करता हूं।

टर्न-9/अभिनीत/20.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, अब ध्यानाकर्षण सूचनाएँ ली जायेंगी । ध्यानाकर्षण के उपरांत समय बचने पर अगर सदन की सहमति हो तो शेष शून्यकाल की सूचनाएँ ली जायेंगी ।

ध्यानाकर्षण सूचनाएँ तथा उस पर सरकारी वक्तव्य

सर्वश्री भाई वीरेन्द्र, अजय कुमार एवं अन्य पाँच सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (शिक्षा विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री भाई वीरेन्द्र जी आपने तो सूचना पढ़ दी है ।

श्री भाई वीरेन्द्र : जी महोदय । मैंने सूचना पढ़ दी है, माननीय मंत्री से जवाब चाहिए ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग ।

श्री चन्द्र शेखर, मंत्री : महोदय, समय चाहिए ।

अध्यक्ष : ठीक है, माननीय मंत्रीजी को समय चाहिए ।

माननीय सदस्य श्री तारकिशोर प्रसाद अपनी सूचना को पढ़ें ।

श्री तारकिशोर प्रसाद, श्रीमती रेणु देवी एवं अन्य तीन सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, राज्य में पशुपालकों के द्वार पर पशु चिकित्सा सुविधा (डोर स्टेप पशु चिकित्सा सेवा) उपलब्ध कराने हेतु भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 307 एम्बुलेंस खरीदने हेतु 49.12 करोड़ की राशि दी है लेकिन अभी तक यह सेवा प्रारंभ नहीं हो पायी है, जिससे बेहतर पशु स्वास्थ्य प्रबंधन नहीं हो पा रहा है एवं इस सेवा से बिहार के पशु वंचित हैं । राज्य में पशुधन की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका है । आज भी बिहार के ग्रामीण क्षेत्र में दुधारू गाय/भैंस पर परिवार का आय निर्भर है ।

अतः केंद्र द्वारा दी गई राशि से पशुपालकों के द्वार पर एम्बुलेंस खरीद कर पशु चिकित्सा सुविधा पहुंचाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि केन्द्रीय प्रायोजित योजना राष्ट्रीय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम (LH & DCP) अंतर्गत Establishment and strengthening of Veterinary Hospitals and Dispensaries (LH & DCP) के तहत मोबाईल वेटनरी यूनिट (MVU) के क्रय हेतु अनावर्त्ती व्यय का वहन शत प्रतिशत केन्द्रांश के रूप में एवं मोबाईल वेटनरी यूनिट (MVU) के परिचालन हेतु आवर्ती व्यय का वहन केन्द्रांश 60 प्रतिशत एवं राज्यांश 40 प्रतिशत के अनुपात में किया जाना है ।

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अक्टूबर-2021 में भारत सरकार से 307 (तीन सौ सात) मोबाईल वेटनरी यूनिट (MVU) के क्रय हेतु राशि एवं दिशा-निर्देश प्राप्त हुए । पुनः वित्तीय वर्ष 2022-23 में मई 2022 में भारत सरकार के द्वारा राज्य को मोबाईल वेटनरी यूनिट (MVU) क्रय हेतु संशोधित दिशा- निर्देश दिया गया । भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देश के आलोक में 307 (तीन सौ सात) मोबाईल वेटनरी यूनिट (MVU) क्रय की कार्रवाई सम्प्रति प्रक्रियाधीन है । प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत मोबाईल वेटनरी यूनिट (MVU) शीघ्र व्यय कर ली जायेगी ।

वर्तमान में पशुपालन प्रक्षेत्र अंतर्गत 1137 (एक हजार सात सौ सैंतीस) पशु चिकित्सालयों एवं 40 (चालीस) अनुमंडल स्तरीय पशु चिकित्सालयों/

औषधालयों में 24x7, इंडोर पशु चिकित्सा सेवा एवं 100 पशु चिकित्सालयों में पैथोलॉजीकल जांच की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

साथ ही, विभाग द्वारा कुल 58 मोबाईल एम्बुलेट्री वैन के माध्यम से आपदा यथा बाढ़/सुखाड़ एवं सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर आयोजित कर पशुओं को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : महोदय, बिहार में पशु चिकित्सालय एवं पशु चिकित्सकों की कमी रही है । अब जो पशुपालक हैं वे पशु लेकर पशु चिकित्सालय बहुत नहीं जा पाते हैं और यह सुविधा भारत सरकार ने दी है और प्रक्रियाधीन है लेकिन एक समय-सीमा तय करके इस प्रक्रिया को पूर्ण करना लाजमी है, क्योंकि कलांतर में एम्बुलेंस क्रय की राशि और बढ़ेगी तो फिर अन्य कई प्रकार की कठिनाइयाँ आयेंगी कि केंद्र सरकार ने कहा है कि 307 एम्बुलेंस खरीदने हैं उसके विरूद्ध में इतनी राशि है लेकिन उसकी क्रय लागत फिर बढ़ गयी है, फिर निवेश लिया जा रहा है तो इन प्रक्रियाओं से बचने के लिए एक समय-सीमा निर्धारित करके उसकी खरीद की प्रक्रिया को प्रारंभ करके और नियत समय पर समाप्त किया जाय जिससे बिहार के किसानों को लाभ हो सके । इस तरह का एम्बुलेंस काफी लाभप्रद होगा, क्योंकि कई प्रकार की बीमारियाँ अलग-अलग ऋतुओं में होती हैं । यह एम्बुलेंस की सेवा काफी अच्छी सेवा है इसलिए सरकार से हमारा आग्रह है कि इसको एक नियत अवधि के भीतर इस प्रक्रिया को पूरा करके, पशुपालकों के द्वार तक इस यूनिट को पहुंचाने के लिए सरकार कबतक व्यवस्था करना चाहती है ?

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री जितेन्द्र कुमार राय, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैंने उत्तर में स्पष्ट कहा है कि प्रक्रियाधीन है, शीघ्र ही प्रक्रिया पूरा करके...

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, क्या प्रक्रियात्मक कार्रवाई सरकार ने शुरू कर दी है ?

श्री जितेन्द्र कुमार राय, मंत्री : जी महोदय ।

श्री राणा रणधीर : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी एक समय-सीमा बता दें । बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

अध्यक्ष : रणधीर बाबू, सरकार अपने स्तर से जो प्रक्रियात्मक कार्रवाई करनी होती है, आप भी मिनिस्टर रहे हैं, वह कार्रवाई कर रही है और माननीय तारकिशोर बाबू की जो चिंता है सरकार उनसे ज्यादा चिंतित है, चूंकि आर्थिक स्थिति, आर्थिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक समृद्धि आये इसके लिए पशु व्यवस्था और उसकी चिकित्सा करना अति आवश्यक है, इसलिए आप अपना स्थान ग्रहण करें । सरकार शीघ्रातिशीघ्र अपने स्तर से प्रक्रियात्मक कार्रवाई कर रही है

और नियमानुसार निश्चित रूप से क्रय करने की कार्रवाई करेगी । इसलिए हम आग्रह करेंगे कि आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री राणा रणधीर : महोदय, एक समय-सीमा बता देते...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब हो गया ।

माननीय सदस्य श्री प्रेम शंकर प्रसाद अपनी सूचना पढ़ें ।

सर्वश्री प्रेम शंकर प्रसाद, राजेश कुमार सिंह एवं अन्य दो सभासदों से प्राप्त ध्यानाकर्षण सूचना तथा उसपर सरकार (जल संसाधन विभाग) की ओर से वक्तव्य।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, गोपालगंज जिलांतर्गत गंडक नदी की तटबंध की सुरक्षा एवं सिंचाई हेतु विभाग ने राज्य स्तरीय चार सदस्यों की जांच टीम गठित की थी । जांच टीम ने अपने पत्रांक- 1801, दिनांक- 01.09.2021 के माध्यम से विभाग को जनहित में उक्त कार्यों की अनुशंसा कर दी थी लेकिन आजतक तटबंध की सुरक्षा हेतु कारगर कदम नहीं उठाया गया है जबकि विभागीय स्तर पर एजेंडा सं0-194/527/23 एवं 198/18/23 पिछले दो वर्षों से लंबित है । इसी संदर्भ में कुछ योजना का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा गया था जो पिछले वर्ष स्वीकृत होकर विभाग के पास लंबित है । स्लूईस गेट ध्वस्त हो जाने से खेतों का पटवन नहीं हो पाता है । बांस घाट मसूरिया एवं घोघरहॉ ध्वस्त स्लूईस गेट बाढ़ के समय टूट जाता है तो गोपालगंज, सिवान एवं छपरा शहर को डूबने से कोई नहीं बचा सकता है ।

अत: जनहित में उपरोक्त तटबंध के सुरक्षात्मक कार्य एवं ध्वस्त स्लूईस गेट का निर्माण कराये जाने हेतु हम सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हैं ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, उत्तर थोड़ा लंबा है । वस्तुस्थिति यह है कि बाढ़ 2020 के पश्चात् गोपालगंज जिले में..

अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, आपके ध्यानाकर्षण का उत्तर यदि लंबा है, लंबा हो भी सकता है, तो माननीय सदस्यों का जिन-जिन बिन्दुओं पर उनका प्रश्न है उसी दिशा में आप अपना उत्तर दे देंगे तो वे संतुष्ट हो जायेंगे ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : हां सर, मैं टच कर देता हूं, थोड़ा सा मैं बैक ग्राउंड, 2020 के पश्चात गोपालगंज जिलांतर्गत गंडक नदी से कटाव की आशंका वाले क्षेत्रों के निरीक्षणोपरांत तटबंध की सुराक्षात्मक आवश्यक कार्य हेतु चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया । समिति अपने पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन में गंडक नदी के बायें किनारे गोपालगंज परिक्षेत्र में सारण तटबंध एवं विभिन्न छरकियों के

सुदृढ़ीकरण का मंतव्य दिया है । साथ ही, समिति द्वारा यह भी प्रतिवेदित किया गया कि बाढ़ 2021 पूर्व विभिन्न स्थलों, जो विभन्न नाम हैं- हीरा पाकड़ छरकी, भैंसा पुरैनी छरकी, सलेमपुर छरकी, हसनपुर छरकी, तंडशपुर छरकी, बंधोली शीतलपुर छरकी, फजालापुर छरकी एवं मटियारी रिंग बांध पर कटाव निरोधक कार्य कराकर इसे सुरक्षित कर लिया गया है ।

उल्लेखनीय है कि बाढ़ 2020 अवधि में बंधोली शीतलपुर, फजालापुर जमींदारी बांध में टूटान के उपरांत माननीय मुख्यमंत्री खुद 2021 में स्थल निरीक्षण किये । तदोपरांत वहां पर स्टील शीट पाइल लगाकर काम किया गया है । पहली बार कुछ कमला में हुआ दूसरी बार गंडक में स्टील शीट पाइल लगाकर के काम किया गया । इसी तरह 2021 के पूर्व कराये गये कटाव निरोधक कार्य से बाढ़ अवधि 2021 में चार लाख क्विसेक से ज्यादा पानी आया लेकिन उससे कोई खतरा नहीं हुआ । साथ ही, 2022 में 4 लाख 45 हजार क्विसेक पानी आया, तटबंध सुरक्षित रहा । इनके तीन प्रश्न हैं । ..क्रमशः..

टर्न-10/हेमन्त/20.03.2023

श्री संजय कुमार झा, मंत्री(क्रमशः) : एक तो उन्होंने खुद दिया है 2023, लिखा है कि विभागीय स्तर पर एजेंडा संख्या- 194/527/23, फिर बोल रहे हैं कि दो वर्षों से लंबित है । यह तो 2023 में ही आया है । दो वर्षों से लंबित नहीं है और यह सी0डब्ल्यू0सी0 के पास है । 12.5 करोड़ से, क्योंकि इंटर स्टेट की रिवर है, गंडक जो है, जो स्टेट के बीच में रहती है । तो सी0डब्ल्यू0सी0 के पास लंबित है। हम लोग कॉर्डिनेट कर रहे हैं, जैसे ही आयेगा, उसमें जो करना है, वह काम हम लोग कर लेंगे । इसके अलावा जो इनका है कि बांसघाट, मसूरिया एवं घोघरहां ध्वस्त सुलिस गेट, उसमें ऑलरेडी काम चल रहा है, रिपेयर हो रहा है, बाढ़ से पहले वह काम पूरा हो जायेगा । इसके अलावा जो अन्य काम हमने किया है वहां पर और उस पर पटवन भी किया जायेगा, जैसे ही वह रिपेयर होता है, अभी काम चल रहा है । मैं सदन को भी बताना चाहता हूं, एक महत्वपूर्ण काम है कि विभाग के अनुरोध पर इन कार्यों के अतिरिक्त गोपालगंज जिला में बाढ़ के प्रभाव को कम करने हेतु सत्तर घाट पुल में लगभग एक हजार मीटर की लंबाई में अतिरिक्त वाटर वे आर0सी0डी0 के द्वारा, पुल निर्माण के द्वारा यह काम किया गया । इससे बांध पर पानी का प्रेशर कम हो गया है, यह काम पूरा हो गया है । इसी प्रकार दिनांक- 07 मार्च, 2023 द्वारा बिहार राज्य पुल निर्माण निगम से बंगरा घाट पुल के वेंटों की सफाई हेतु अनुरोध किया गया है एवं विभागीय पत्रांक 07 मार्च, 2023 द्वारा

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, पटना से डुमरिया घाट पुल में वेंटों की सफाई हेतु भी अनुरोध किया गया है । वर्तमान में तटबंध सुरक्षित है । बाढ़ अवधि में सतत निगरानी एवं चौकसी बरती जाती है । बाढ़ अवधि में तटबंध पर कटाव परिलक्षित होने पर बाढ़ संघर्षात्मक कार्य कराकर स्थल को सुरक्षित किया जायेगा । अन्य चीजों को मैंने नहीं पढ़ा, क्योंकि बहुत सारा बाढ़ निरोधक काम अभी चल रहा है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने उत्तर को सुन ही लिया । आप पूरक पूछना चाहते हैं, तो पूछिये ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : महोदय, मंत्री जी को मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आप हर साल वहां काम करते हैं । कभी 12 करोड़, कभी 15 करोड़, कभी 24 करोड, कभी 40 करोड़ का काम आप हर साल कराते हैं । आखिर आप एक ही बार, एक ही साल जो एजेंडा है, जो एजेंडा मैंने उनको दिया है, जो जी0एफ0सी0सी0 हो गया है । आखिर आप एक ही बार में 176 करोड़ का काम वहां से लेकर और जो प्वाइंट मैंने दिया है, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आता है । आप एक ही बार काम क्यों नहीं करा देते हैं कि आप हर साल जो बाढ़ निरोधात्मक काम करते हैं और सरकार का बेवजह पैसा खर्च होता है, हर साल उसमें लूट-खसौट होती है । उसको क्यों नहीं समाप्त कर देते हैं और रही बात सुलिस गेट की, तो सुलिस गेट चार लाख का गया है, चार सुलिस गेट बनाने हैं, जो आज से 100 वर्ष पुराना सुलिस गेट है, क्या वह एक लाख रुपये में बन पायेगा ? वह एकदम क्षतिग्रस्त है । पिछली बार हमारी ग्रामीण जनता ने सुलिस गेट को अपने अनुसार, सभी गांव के लोगों ने एकजुट होकर बोरा फेंककर उसको बंद करके रखा, वह कैसे एक लाख रुपये में होगा, जबकि बांध से, जो सारण तटबंध है उससे, कम-से-कम कमर से भी वह नीचे चला गया है । पानी आता है, तो सुलिस गेट के ऊपर से पानी बहता है । अगर बांस घाट मसूरिया एवं घोघरहां सुलिस गेट टूट गया, तो पूरा छपरा और सिवान भी बर्बाद हो जायेगा पानी से । क्योंकि गंडक नदी का बहाव डायरेक्ट वहीं जाता है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपने इस बात को ध्यानाकर्षण सूचना में लिखा है, आप पूरक पूछिये न ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : महोदय, मंत्री जी से मेरा पूरक यही है कि जो हर साल काम होता है, आप एक ही बार काम क्यों नहीं कराते हैं कि सरकार के ऊपर हर साल इतना बोझ डालते हैं ।

अध्यक्ष : माननीय मंत्री ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : माननीय अध्यक्ष महोदय, नदी अपना कोर्स बदलती रहती है । अब यह तो टेक्निकल बात हो गयी, अपना रूट बदलती रहती है । अब कुछ काम तो ऐसा है कि जैसे कोर्स बदलती है उस हिसाब से देशभर में, दुनियाभर में काम होता है । कुछ, जो ये एजेंडा बता रहे थे उसमें भारत सरकार का भी प्रश्न चिन्ह है रोड बनाने का । तो जो छरकी है, मेन बांध है सारण बांध और उसके बाद बहुत सारी छरकी हैं जिसके अंदर लोग रहते हैं और एक बांध टूटता है, तो सारी छरकी पर प्रेशर हो जाता है । जहां पर जो काम करना है, वह काम हम लोग कर देते हैं । एक बड़ा लेंथ का काम है, जो रोड बनाने की बात है वह सी0डब्ल्यू0सी0 के पास लंबित है और मैंने कहा कि जब दो इंटर स्टेट रिवर रहती हैं, तो जी0एफ0सी0सी0 और सी0डब्ल्यू0सी0 की परमिशन के बाद ही उस पर कोई प्रक्रिया शुरू होती है । सी0डब्ल्यू0सी0सी0 से बात चल रही है, और जैसे होगा फिर हम फेजवाइज उससे काम लेंगे ।

श्री प्रेम शंकर प्रसाद : महोदय, माननीय मंत्री जी ने सुलिस गेट के बारे में नहीं बोला ।

श्री संजय कुमार झा, मंत्री : सुलिस गेट का काम चल रहा है । ये बता रहे हैं कि वह टूट गया है, लेकिन मैं आश्वस्त करता हूं कि सुलिस गेट का काम ठीक से हो जायेगा।

अध्यक्ष : अब शून्यकाल की शेष सूचनाएं ली जायेंगी ।

शेष शून्यकाल

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री रामवृक्ष सदा ।

श्री रामवृक्ष सदा : अध्यक्ष महोदय, खगड़िया जिला के अलौली प्रखण्ड अंतर्गत गौरियामी पंचायत के लरही गंगासराय एवं चातर पंचायत के धीमकी में बागमती नदी पर पुलिया निर्माण की मांग करता हूं ।

श्री विनय बिहारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां दो मॉडल हाईस्कूल बलुआं तथा मरहियां दो वर्षों से बनकर तैयार हैं । पठन-पाठन तथा भवन के रख-रखाव की कमी से समस्या गंभीर है । पढ़ाई शीघ्र प्रारंभ हो, सदन के माध्यम से यह मांग करता हूं ।

श्री जनक सिंह : अध्यक्ष महोदय, पटना जिला के बेली रोड सहित राज्य की सभी सड़कों के निर्माण के दौरान बना पुरानी परत हटाये नयी सड़क का निर्माण करने के कारण सड़कों की ऊंचाई बढ़ रही है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है । इसकी जांच कराते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग करता हूं ।

श्री अरूण शंकर प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय पोषण मिशन अभियान के तहत राज्य के सभी प्रखण्डों में ICDS का ज्ञापांक- 2621, दिनांक- 17.05.2019 के द्वारा

प्रखण्ड परियोजना सहायक के पद पर नियुक्ति की गयी थी । तीन वर्षों के बाद हटा दिया गया है ।

उक्त ICDS को पुनः बहाल करने की मांग करता हूं ।

श्री केदार प्रसाद गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मुजफ्फरपुर जिला सहित उत्तर बिहार में बेमौसम बारिश एवं ठनका से गेहूं, दलहनी फसल, आम और लीची को भारी नुकसान हुआ। मनियारी, मीनापुर और कांटी में एक-एक की मौत हो गयी । फसल का मुआवजा, मृतकों को दस-दस लाख रुपये सरकार से देने की मांग करता हूं ।

श्री तारकिशोर प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, कटिहार जिला में ग्रामीण कार्य प्रमण्डल बारसोई अन्तर्गत कटिहार-डंडखोरा विभागीय पथ में खानाधार पर पूर्व से निर्मित पुल, 2017 की बाढ़ की विभीषिका में ध्वस्त हो ही चुका है जिससे आवागमन पूर्णतः बाधित है। यह पथ कई प्रखण्डों को जोड़ता है ।

अतः खानाधार पर नये पुल का निर्माण शीघ्र करावें ।

श्री सुदामा प्रसाद : माननीय अध्यक्ष महोदय, पटना जिला अन्तर्गत बिहटा थाना के कन्हौली निवासी शिक्षक राजकिशोर पंडित के 12 वर्षीय एकलौते पुत्र तुषार की फिरौती के लिए जघन्य हत्या करने वाले हत्यारे पर स्पीडी ट्रायल चलाकर कड़ी-से-कड़ी सजा दिलाने की मांग करता हूं ।

श्रीमती रश्मि वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से सभी सरकारी सार्वजनिक शौचालयों में महिलाओं एवं बच्चों के लिए फ्री सुविधा प्रदान करने की मांग करती हूं ।

अध्यक्ष : अब सभा की कार्यवाही 02.00 बजे दिन तक के लिए स्थगित की जाती है ।

टर्न-11/धिरेन्द्र/20.03.2023

(अंतराल के बाद)

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अध्यक्ष : सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है । वित्तीय कार्य लिये जायेंगे ।

वित्तीय कार्य

माननीय सदस्यगण, पथ निर्मण विभाग के अनुदान की मांग पर वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं मतदान होगा । इसके लिए 3 घंटे का समय उपलब्ध है । विभिन्न दलों को उनकी सदस्य संख्या के आधार पर समय का आवंटन निम्न प्रकार किया जाता है, इसी समय में से सरकार को उत्तर के लिए भी समय दिया जायेगा:

राष्ट्रीय जनता दल	-	58 मिनट
भारतीय जनता पार्टी	-	58 मिनट
जनता दल यूनाइटेड	-	33 मिनट
इंडियन नेशनल कांग्रेस	-	14 मिनट
सी॰पी॰आई॰ (एम॰एल॰)	-	09 मिनट
हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा	-	03 मिनट
सी॰पी॰आई॰(एम॰)	-	02 मिनट
सी॰पी॰आई॰	-	02 मिनट
ए॰आई॰एम॰आई॰एम॰	-	01 मिनट

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, 22 तारीख से नवरात्रा प्रारंभ हो रही है और महोदय, आज जो मुस्लिम कर्मचारियों के लिए एक धंटे का रिलीफ दिया गया तो जो नवरात्रा करते हैं उनके लिए भी, बैठे हुए हैं उप मुख्यमंत्री जी, उनको भी रिलीफ दिया जाय ।

अध्यक्ष : नेता प्रतिपक्ष, स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, ये तुष्टिकरण की राजनीति नहीं होनी चाहिए ।

अध्यक्ष : आपने सूचना दे दी । अब स्थान ग्रहण कीजिये ।

माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग । अपनी माँग प्रस्तुत करें ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि

''पथ निर्माण विभाग के संबंध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 59,18,86,67,000/- (उनसठ अरब अठ्ठारह करोड़ छियासी लाख सड़सठ हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

यह प्रस्ताव राज्यपाल की सिफारिश पर किया गया है ।

अध्यक्ष : इस मांग पर माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी, श्री कुमार शैलेन्द्र, श्री अरूण शंकर प्रसाद, श्री जनक सिंह, श्री अखतरूल ईमान एवं डॉ० सी० एन० गुप्ता से कटौती प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । ये सभी व्यापक हैं जिसपर सभी माननीय सदस्य विचार-विमर्श कर सकते हैं । माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी जी का प्रस्ताव प्रथम है ।

अतएव माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करें ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने 59,18,86,67,000/- (उनसठ अरब अठ्ठारह करोड़ छियासी लाख सड़सठ हजार) रुपये का जो प्रस्ताव दिया है, मैं राज्य सरकार के पथ निर्माण नीति पर विचार-विमर्श करने के लिए, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटायी जाय ।''

अध्यक्ष महोदय, एक-डेढ़ मिनट में, क्षेत्र का विषय है उसको बोल देता हूँ, फिर माननीय प्रमोद जी बोलेंगे ।

अध्यक्ष महोदय, मिथिला का मुख्यालय दरभंगा है, वहाँ पूरा जाम लगा रहता है, इसके लिए 50-50 शेयरिंग के आधार पर पथ निर्माण विभाग को आर०ओ०बी० बनाना था, उसमें 25ए बनार चौक और 26 नंबर म्यूजियम, ये दो आर०ओ०बी० हैं, इसका अभी तक डी०पी०आर० स्वीकृत नहीं हुआ है और अध्यक्ष महोदय, जो वी०आई०पी० रोड है, जो स्टेट हाइवे, इसका भी चौड़ीकरण का डी०पी०आर० बना हुआ है । मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूँगा और एक फ्लाईऑवर इस वी०आई०पी० रोड पर है, उस फ्लाईऑवर का भी डी०पी०आर० बना था, अध्यक्ष महोदय, मिथिला का मुख्यालय दरभंगा है, पूरा शहर जाम रहता है और चार सड़क पथ निर्माण विभाग ने अधिग्रहण किया था, शहर की मुख्य सड़क को। अध्यक्ष महोदय, एक है तारामंडल जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, दूसरी है मिर्जापुर से दरभंगा टावर, ये पूरा मुख्यालय है दरभंगा का, तीसरी है लक्ष्मीसागर की सड़क और चौथी है शिवाजी नगर सब्जीमंडी दरभंगा की, ये चारों सड़कों की बहुत-ही नारकीय स्थिति है और डी०पी०आर० भी बन कर आया हुआ है,

यह पथ निर्माण विभाग ने अधिग्रहण किया है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मैं आग्रह करूँगा कि ये तीन-चार बिन्दु जो हैं, एक आर०ओ०बी० वाला 25ए और 26 नंबर, चार सड़क जो अधिग्रहण हुआ है वह और एक वी०आई०पी० रोड का चौड़ीकरण और वी०आई०पी० रोड पर जो फ्लाईआवर है उसका डी०पी०आर०...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण किया जाय ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, पुल निर्माण निगम ने बना कर रखा है और ये चारों के लिए बस आग्रह करता हूँ कि इसको...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रमोद कुमार, अपना पक्ष रखें । आपका समय 18 मिनट है ।

श्री संजय सरावगी : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया और माननीय सदस्य प्रमोद जी इस पर विस्तृत रूप से पक्ष रखेंगे ।

श्री प्रमोद कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग का जो बजट पेश हुआ है और पथ निर्माण विभाग के जो कार्य हैं, इसमें शेरशाह सूरी जो रोड बनाये थे और उसके बाद आज पथ निर्माण विभाग की चर्चा हो रही है तो अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेय और उस समय के तत्कालीन संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रमोद महाजन जी को याद करना आवश्यक है । उन्होंने जो पार्लियामेंट में, एक रुपया जो पेट्रोलियम पर सेस दिया, जिसका परिणाम है कि आज पूरे देश में, महोदय, उसी एक रुपया से, केन्द्र सरकार की जो पेट्रोलियम के सेस की राशि है जिसका परिणाम है कि कोरिडोर उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम और गाँव का प्रधानमंत्री सड़क, स्टेट हाइवे और लंबी-लंबी, बड़ी-बड़ी चौड़ी सड़कों का, आज देश अपने अटल बिहार वाजपेय जी के बाद जो प्रगति पर गई है, जिस काम को आज देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मान्यवर नरेन्द्र भाई मोदी जी आगे बढ़ा रहे हैं और महोदय, वर्ष 2005 के पहले क्या स्थिति थी, हम वर्ष 2005 में विधायक बने और जब अपने क्षेत्र मोतिहारी से चलते थे तो पाँच घंटा समय लगता था और एन०डी०ए० की सरकार बनी तो उस समय सड़कों के बारे में कई तरह-तरह की बातें आयीं कि फलाने अभिनेता, फलाने अभिनेत्री की तरह ये सड़कें हैं और ऐसे-ऐसे कमेंट बिहार की सड़कों के बारे हुआ करता था लेकिन धन्यवाद है, जब एन०डी०ए० की सरकार वर्ष 2005 में आयी तो सड़कों का जाल बिछा और हमलोग जो पाँच घंटे में आते थे वह वर्ष 2005 के पहले, महोदय, आप स्वयं देखे हैं कि सिवान जाना कितना कठिन था, आपसे ज्यादा कौन जानेगा और महोदय, वर्ष 2005 के बाद जब सरकार बनी तो सड़कों का जाल बिछा और जिसका परिणाम हैं कि आज गाँव की सड़क और हर जगह सड़कों का इस एन०डी०ए० सरकार में जो काम हुआ है

और महोदय, इसी के तहत सड़कों और पुलों का जो वर्ष 2015-16 में 1,706 जो है पूंजीगत व्यय था और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क का 7,884 और राजस्व व्यय 1,706 और पूंजीगत व्यय 4,403 था और वर्ष 2022-23 में यह बढ़कर पुल और सड़कों का 4,544 और 3,821 हुआ तथा प्रधानमंत्री सड़क का 8,165 हो गया । महोदय, इस प्रकार राष्ट्रीय उच्च पथ जो 5,977 किलोमीटर और राज्य का जो उच्च पथ था वह 15,637 किलोमीटर, इसमें बिहार के 1,000 वर्गफीट पर 63.1 परसेंट की प्रगति हुई है जबकि पंजाब में 81.5 है और हरियाणा में 73.7 है । महोदय, वर्ष 2005 में एन॰एच॰ 3,537 किलोमीटर थी और वर्ष 2022 में 5,940 किलोमीटर हुई । महोदय, प्रधानमंत्री पैकेज के तहत 50,711 करोड़ रुपये की 75 परियोजनाओं को ली गयी, प्रधानमंत्री पैकेज से, जो बराबर ये लोग प्रधानमंत्री पैकेज की बात करते हैं और...

...क्रमशः...

टर्न-12/संगीता/20.03.2023

श्री प्रमोद कुमार (क्रमशः) : महोदय, जिसमें 24 एन0एच0ए0आई0 और 51 स्टेट रोड लिये गये और महोदय इस 24 में से 17 परियोजनाएं पूर्ण भी हो गईं और 51 में से 31 परियोजनाएं भी पूर्ण हो गईं और महोदय, आज इसी के लिए पी0एम0 पैकेज में अखबार में समाचार है कि 75 में से 35 सड़क परियोजनाएं अब तक पूरी नहीं हुईं प्रधानमंत्री पैकेज का है और महोदय...

(व्यवधान)

ये पुस्तकालय का है, ये बिहार लाइब्रेरी के पुस्तकालय का है । महोदय, ये पुस्तकालय सचिवालय का है आप ही के अधीनस्थ है पुस्तकालय और महोदय केंद्र ने बिहार को तय कोटे से...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, इन्हें अपना पक्ष रखने दिया जाय ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, बिहार को केंद्र सरकार ने तय कोटे से अधिक राशि दी, ये कोई पुराना समाचार नहीं है, 02.04.2022 का है और महोदय, प्रदेश में 2 हजार 468 करोड़ रुपये से 8 नेशनल हाईवे बनाने की योजना को मिली केंद्र की हरी झंडी, ये 09.01.2023 का समाचार है महोदय, जनवरी का है । महोदय, वाराणसी, औरगांबाद जो सिक्स लेन निर्माण 11 साल से अटका है बढ़ी 1250 करोड़ की लागत, ये महोदय समय पर जमीन नहीं देने के कारण हुआ । समय पर राज्य सरकार द्वारा सहयोग उचित नहीं करने के कारण लंबी परियोजना अटकी हुई है । महोदय, ये अखबार छापा है, अखबार और ये 09.01.2023 का समाचार है और महोदय, ये छोटे-छोटे दिक्कत महोदय, ये देश का चौथा स्तंभ है...

(व्यवधान)

ऐसा मत कहिए आपको जब आईना, महोदय विपक्ष का काम है आईना दिखाना...

(व्यवधान)

श्री संजय सरावगी : टोका-टोकी कर रहे हैं हुजूर बताइए...

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : महोदय, अखबार की चर्चा कर रहे हैं, अखबार पर यही कितना संज्ञान लेकर कितना विषय रखते थे और माननीय मुख्यमंत्री जी अखबार को ही संज्ञान में लेकर स्पेशल कमिटी भेज देते हैं जांच के लिए और...

अध्यक्ष : माननीय प्रमोद बाबू...

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अखबार का ये मजाक उड़ाते हैं...

अध्यक्ष : आप अपना पक्ष शुरू करें, क्योंकि आप ही के समय में से कट जायेगा ।

श्री प्रमोद कुमार : जी । महोदय, ये मैं सरकार को दर्पण दिखा रहा हूं, देश का चौथा स्तंभ है महोदय अखबार, विपक्ष का काम है महोदय दर्पण दिखाना, ये दर्पण दिखा रहे हैं और भेज देंगे महोदय प्रोसीडिंग का भी पार्ट बनाना चाहेंगे तो सर, दे देंगे । इसको समझना चाहिए और इसी प्रकार राज्य में 5 पुल के निर्माण में हुई देरी और सुस्त चाल से गंगा नदी पर इन सभी पुलों के बनने से होगी सुविधा, जो 5 पुल में 2400 करोड़ रुपया का लागत बढ़ गया । महोदय, देरी के कारण लागत बढ़ रहा है, कुशल सहयोग नहीं करने के कारण देरी के कारण, हमलोग विकास के साथ हैं लेकिन विकास में सहयोग जो सरकार की होनी चाहिए वह नहीं होने के कारण 2400 करोड़ रुपया लागत बढ़ गया महोदय, ये चीज अखबार लिख रहा है । ये सब इन्हीं के विभाग का आंकड़ा है और 4 सड़कों का 7 साल से निर्माण लागत दोगुनी, जो 4 सड़क भी है और महोदय, आज भारत सड़क निर्माण कार्य में घटिया सामग्री इस्तेमाल का आरोप । महोदय, इस प्रकार 56 साल बाद भी आज राष्ट्रीय उच्च पथ एन0एच0 की जो सड़क अधिग्रहण की भूमि है उसका समय पर दाखिल-खारिज नहीं करने के कारण आज 56 साल में दाखिल-खारिज नहीं होने के कारण एन0एच0ए0आई0 की सैकड़ों एकड़ जमीन पर अतिक्रमण और पक्के का मकान बन रहा है, नेशनल प्रोपर्टी है महोदय । राज्य सरकार की ये कारगुजारी की म्यूटेशन नहीं होने के कारण अवैध कब्जा हो रहा है, अवैध घर निर्माण हो रहा है और सरकार बैठी अपनी पीठ अपने ठोक रही है, अपने पीठ पर अपने थपथपा रही है देख लिया जाय महोदय, ये अखबार है, प्रोसीडिंग का पार्ट बना दीजिए इन लोगों को सुविधा होगी । और महोदय, 2 करोड़ का एक सड़क बना और सड़क बनते के साथ उखड़ गया तो इंजीनियर को जब उसके सुपर इंजीनियर कैफियत पूछे कि भाई

2 करोड़ का सड़क बनते के साथ कैसे उखड़ गया, तो इंजीनियर बोल रहे हैं कि ठंडा लगने से सड़क उखड़ गया, देख लीजिए । ठंड में उखड़ी 2 करोड़ की सड़क इंजीनियर बोले ठंड से ऐसा हुआ है अब महोदय, सड़कों को भी ठंड लगने से उखड़ जाता है । ये अखबार है श्रवण बाबू भेज देते हैं, थोड़ा पढ़ लीजिएगा खोल के । महोदय, ये कारगुजारी है मैं नहीं कह रहा हूं ये महोदय अखबार कह रहा है और समाचार...

(व्यवधान)

महोदय...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपना भाषण जारी रखें ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, पी0डब्लू0डी0 का रूल ऑफ लॉ है...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप शांति बनाए रखें ।

श्री प्रमोद कुमार : पी0डब्लू0डी0 का महोदय, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग का रूल ऑफ लॉ है कि...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : क्या व्यवस्था है आपका ?

श्री प्रमोद कुमार : कि जे0ई0 हर सात दिन में सड़क पर नहीं दिखे तो होगी कार्रवाई...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : एक मिनट प्रमोद बाबू, एक मिनट ।

(व्यवधान)

क्या व्यवस्था है ?

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, हमारा समय मत बर्बाद किया जाय ।

अध्यक्ष : बोलिए व्यवस्था जल्दी...

श्री सत्यदेव राम : महोदय, यही हमारी व्यवस्था है...

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, एक मिनट बढ़ाइये...

अध्यक्ष : हां, हो जाएगा ।

श्री सत्यदेव राम : कि सड़कों को ठंढ कबसे लगने लगी है...

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, ये हमेशा, जब हम बोलते हैं तभी इनको हिचकी आता है...

(व्यवधान)

श्री सत्यदेव राम : जिस सड़क की चर्चा माननीय सदस्य कर रहे हैं वह सड़क कब की बनी हुई है कि उसको ठंढ लग गई है ये बता दें जरा...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप अपना पक्ष जारी रखें ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, जब माननीय मंत्री श्री नन्द किशोर बाबू थे उसी समय लॉ बना नितीन जी के समय कि जे0ई0 हर 7 दिन में सड़क पर नहीं दिखा तो होगी कार्रवाई, जे0ई0 को 7 दिन में जाना है, एस0डी0ओ0 को 15 दिन में जाना है और इंजीनियर को महीना दिन में जाना है और सुपरिंटेडेंट को डेढ़ महीना में जाना है और चीफ इंजीनियर को 2 महीने में जाना है ये रूल बना है और कहीं पर महोदय, सभी माननीय विधायक लोग बैठे हैं, पूछ लीजिए कि इनके क्षेत्र में जे0ई0 7 दिन पर जाता है कि रोड का मेन्टेनेंस हो, रोड तो बन गये पहले महोदय और अगले वर्ष मार्च तक नहीं बन पाया पटना-गया-डोभी, माननीय हाई कोर्ट का ये आदेश है महोदय हाई कोर्ट का, उच्च न्यायालय यह कह रहा है बात समझिए ये जनहित की बात है और महोदय, इस तरह 23 नए रोड प्रोजेक्ट के टेंडर तक ले जाने की बड़ा टास्क मतलब कि महागठबंधन सरकार के लिए 41 हजार 422 करोड़ एन0एच0 परियोजना को गति देने की चुनौती और महोदय, 23 नए रोड का टेंडर का टास्क पूरा नहीं होने से लटक गया । महोदय, टोल प्लाजा पर कोई मानवीय सुविधा नहीं है, केंद्र ने बिहार के लिए 3 हजार 54 करोड़ रुपये की योजना को स्वीकृति दी और महोदय, बिहार में राम-जानकी मार्ग का पूरा हुआ हिस्सा फोर लेन में और ये सौगात केंद्र सरकार ने दिया है । महोदय, अभी जो राज्य में 5 हजार 153 करोड़ की 9 सड़क, एक ब्रिज परियोजनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी, ये 462 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए ए0डी0बी0 से लोन लेगा राज्य सरकार और उसमें भारत सरकार भी अपना पैसा देगा और उसी तरह रामपुर में 3 महीने में धंसा, महोदय देख लिया जाय नगर निगम, हमलोग नगर निगम के कई माननीय विधायक हैं नगर निगम के अधीन आने वाली ज्यादातर सड़कें बदहाल, वाहन चलाने में परेशानी, रामपुर में 3 महीने में धंस गईं 56 लाख की बनी सड़कें और महोदय, आज भारत की सरकार जो विकास के लिए राशी दे रही है और उसी राशि से एन0एच0, एन0एच0ए0आई0 और स्टेट हाईवे का काम हो रहा है और जिला मुख्यालय पर भी उसी राशि से काम करना है लेकिन महोदय...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री प्रमोद कुमार : जी ।

अध्यक्ष : आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री प्रमोद कुमार : हम बता रहे हैं । समय समाप्त कैसे हुआ है...

अध्यक्ष : नहीं, 18 मिनट का समय दिया गया था...

श्री प्रमोद कुमार : नहीं, नहीं, महोदय...

अध्यक्ष : और आपने 2 बजकर 24 मिनट पर प्रारंभ किया ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, अभी समय समाप्त नहीं हुआ है...

(क्रमशः)

टर्न-13/सुरज/20.03.2023

(क्रमशः)

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, अभी इसी प्रकार कला संस्कृति एवं युवा विभाग है और इसमें भी महोदय देख लिया जाय 2012-13 में ही इस स्टेडियम का टेंडर हुआ और तरैया विधान सभा सहित राज्य के कई जगहों पर यह टेंडर हो गया और काम पूरा नहीं हुआ...

(व्यवधान)

अभी तक काम पूरा नहीं हुआ । महोदय, इसको रख देते हैं मेज पर सरकारी डॉक्यूमेंट है और महोदय...

(व्यवधान)

2012-13 में हम नहीं थे । महोदय, और इस प्रकार हमारे क्षेत्र में भी...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य...

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, 2 मिनट सुना जाय । हमारे क्षेत्र में भी सड़क है और इसकी योजना भी आयी हुई है लेकिन वह काम पूरा नहीं हो रहा है, टेंडर भी निकाल दिया गया। मोतीझील के ऊपर एक रोड गया हुआ है लेकिन फंड अभी नहीं गया है । इसी प्रकार शहर के लिये जिलाधिकारी ने एक परियोजना, ओवरफ्लाई पुल मोतीझील पर बनाने का, उत्तर आया मंत्री महोदय का कि पुल बनेगा लेकिन अभी राशि नहीं है। महोदय, आज जो एन0एच0 से जुड़ा हुआ स्टेट हाइवे है, माननीय मंत्री महोदय को मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर आप एन0एच0 जैसे भारत-नेपाल । नेपाल का जो रोड बना है उससे जुड़ा हुआ जो स्टेट हाइवे है उसको एन0एच0 को दें कि कम से कम इनका भार तो ऊपर चल जायेगा और उसको भी डेवलप करें । महोदय, आज मोतिहारी कमिश्नरी लेवल का नगर निगम बना है और कई ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें जो नया नगर निगम में आया है और सरकार का संकल्प है महोदय पथ निर्माण विभाग के अधिकारी सुन रहे हैं । संकल्प है कि जो पथ निर्माण विभाग के मानक के सड़क होंगे, लंबी-चौड़ी सड़क होगी, उन सड़कों को अधिग्रहित करके और निर्माण करायें । राज्य पैमाने का संकल्प है महोदय जिसके

आधार पर अपने माननीय सदस्य बता रहे थे, हमलोगों के यहां से भी आया है, कई माननीय विधायकों के यहां से आया है । लेकिन वे जो परियोजानायें हैं, जिसका अधिग्रहण किया गया है उसका निर्माण अब तक नगर विकास विभाग से किया गया है और हमलोगों के यहां भी आधा पर सर्वे हुआ है और आधा...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, 7 मिनट जो आपको समय दिया गया था, उससे 7 मिनट ज्यादा हो गया ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, अभी देखा जाय, अभी बाकी है...

अध्यक्ष : है नहीं, यह तो आप ही के दल ने दिया है इसलिये मैं बोल रहा हूं ।

श्री प्रमोद कुमार : महोदय, इस प्रकार हम आपसे राज्य की जनता की तरफ से माननीय मंत्री महोदय और बिहार सरकार से कहना चाहता हूं कि जो योजनाएं लंबित हैं । पहले क्या था कि दोगुना योजना लेते थे, अब चार गुना योजना ले लेते हैं और राशि होती नहीं है और काम ठंडे बस्ते में बंधा जाता है । तो उतनी योजना ही लें जितनी क्षमता है और क्षमता से अधिक गच्छ लेते हैं और काम पूरा होता नहीं है और संवेदक देखता रहता है कि किस पर कितना आवंटन गया और उसके हिसाब से काम शुरू किया । तो महोदय इस प्रकार हम कहना चाहेंगे कि सरकार की जो क्षमता है, उस क्षमता के हिसाब से काम करे और आर्ट एंड कल्चर विभाग जो स्टेडियम बनाया, व्यायामशाला बनाया उसकी मेंटनेंस पॉलिसी बनाये और हमारे यहां एक जार्ज ऑरवेल पार्क है उस पार्क के डेवलपमेंट की बात भी माननीय मंत्री जी बताये लेकिन राशि का अभाव बता दिये । तो महोदय यह राशि का अभाव है तो आखिर उसकी व्यवस्था करें और इसी तरह लंबित योजनाओं को क्यों और लंबा कर रहे हैं । महोदय, आपने जो अवसर दिया आपको, अपने नेता प्रतिपक्ष, जनक भाई और अपने क्षेत्र की जनता के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री छोटे लाल राय अपना पक्ष रखें । आपका समय मात्र 8 मिनट है ।

श्री छोटे लाल राय : थोड़ा बढ़ा दीजिये महोदय ।

अध्यक्ष : बोल दीजिये सब ।

श्री छोटे लाल राय : अध्यक्ष महोदय, हम कटौती प्रस्ताव के विपक्ष में और सरकार के पक्ष में बात रखने के लिये खड़े हैं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आप टेबल पर रख दीजिये । माननीय सदस्यगण, आप टेबल पर रख सकते हैं अपने भाषण को लेकिन प्रोसिडिंग का अंश वह नहीं बनेगा ।

श्री छोटे लाल राय : हम पहले इस सरकार के मुखिया आदरणीय नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी जी को धन्यवाद और बधाई देते हैं कि जिन्होंने अपना वादा बिहार की जनता से तय किया था कि 5 घंटे में हम बिहार के किसी जिला से हम पटना में पहुंचेंगे, राजधानी में पहुंचेंगे और करके दिखाने का काम किया है इसलिये इस सरकार को हम धन्यवाद और बधाई देते हैं । बहुत सी चर्चाएं हमलोगों को करनी है साथियों...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री छोटे लाल राय जी आप आसन की तरफ देखिये और अपनी बात को बोलते रहिये ।

श्री छोटे लाल राय : महोदय, हम तो आप ही की तरफ देखकर बोल रहे हैं ।

अध्यक्ष : हां बिल्कुल इधर ही ध्यान दीजिये ।

श्री छोटे लाल राय : सरकार ने जो काम किया है अनेकों प्रकार के, हमारे मित्र साथी प्रमोद भाई बोल रहे थे वह भी तो सरकार के मंत्री थे, उनको तो अपने राज्य में काम कराना चाहिये । एक छोटा उदाहरण देते हैं कि हमारे तेजस्वी जी ने...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : प्रमोद बाबू आप बोल चुके हैं । आप बोले हैं, काफी बोले हैं ।

श्री छोटे लाल राय : हमारे उप मुख्यमंत्री जी ने एक चिट्ठी भारत सरकार को लिखने का काम किया है कि छपरा से हाजीपुर का एन0एच0 इन लोगों से 14, 15 साल में आज तक नहीं बन पाया, इससे और कोई ग्लानि का काम नहीं हो सकता है । हम बतला दें मित्रों कि बहुत से काम जो पेंडिंग...

(व्यवधान)

बना लिये हैं तो जाकर देख लीजिये एक बार प्रमोद भाई, एक बार जाकर तो देखिये ।

अध्यक्ष : आप अपना पक्ष रखिये ।

श्री छोटे लाल राय : महोदय, हम अपनी बात ही रख रहे हैं जो बात होगी वह तो कहेंगे...

अध्यक्ष : आप अपना एचीवमेंट बोलिये ।

श्री छोटे लाल राय : महोदय, आज क्या स्थिति है, आज स्थिति यह बनी हुई है कि आप कहीं, हमें जहां 4 घंटा लगता था वहां 50 मिनट में पहुंच रहे हैं । हम राज्य के जितने भी प्रशासन हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि जिन्होंने इस तरह का काम करके दिखाया है । साथियों क्योंकि समय बहुत कम दिये हैं, हमलोगों का समय थोड़ा ज्यादा बढ़ाना था कारण कि परसा की जनता की जो मांग है, हमें 3 बार परसा की जनता ने इस सदन में भेजने का काम किया है, उनकी भी बात और उनके भी

प्रस्ताव को रखना है । हम धन्यवाद देते हैं इस सरकार को कि अगर 14 बाईपास का इन्होंने टेंडर किया है जिसमें परसा की जनता के लिये भी एक बाईपास देने का काम किया है इसलिये बधाई देते हैं । बहुत से काम हमलोग चाहते हैं माननीय मंत्री जी जब हैं तो दूसरी बात हम रखेंगे । सरकार के जो विकास हैं सबलोग जानते हैं, मन से वे लोग जो बोल लें लेकिन वे भी जानते हैं कि सरकार ने क्या प्रगति किया है, क्या काम कर रही है यह छिपा हुआ नहीं है । लेकिन अपने क्षेत्र के कारण क्योंकि समय अध्यक्ष महोदय आपने बहुत कम दिया है इसलिये जो जनता हमको भेजी है, उसके संबंध में हम कुछ चर्चा आपके यहां करने जा रहे हैं। महोदय, एक सड़क है जो हमलोग परसा से सुतीहार जाते हैं, ये दोनों पी0डब्लू0डी0 के सड़क के बीच का है और हम उससे थोड़ा आगे जायेंगे तो एन0एच0 है छपरा और मुजफ्फरपुर की ओर । उसमें थोड़ा सा मात्र 8 किलोमीटर हम रोड बना देते हैं तो जो परसा हम घुम कर आते हैं, हम सीधे परसा से कस्सा चले जायेंगे । ये आग्रह है कि उसको भी आप पी0डब्लू0डी0 में ट्रांसफर करके 8 किलोमीटर रोड को बनवा दीजिये । एक आग्रह है महोदय हमारे पदाधिकारी भी यहां हैं कपरफोड़ा दरिहारा रोड हमलोग पी0डब्लू0डी0 में लिये हैं लेकिन स्ट्रेंथनिंग उसका छोटा है, उसको चौड़ीकरण करने के लिये शायद प्राक्कलन भी 33 करोड़ का आ गया है । आग्रह है कि उस सड़क को भी थोड़ा दिखवाकर कराने का कृपा करेंगे । मित्रों हमारे आदरणीय जो उप मुख्यमंत्री हैं, पथ निर्माण मंत्री उस समय थे इन्होंने सोनपुर दरिहारा रेवा घाट पथ पी0डब्लू0डी0 को ट्रांसफर करके बनाने का काम किये हैं । आग्रह है कि उसको अगर समय मिले तो एस0एच0 में जोड़ दीजिये, वह बहुत बड़ा सड़क है जो सबलोगों का उद्गम, हमारे अध्यक्ष महोदय भी जानते हैं उनको भी जरूरत पड़ता है तो उससे जाते रहते हैं ।

(क्रमशः)

टर्न-14/राहुल/20.03.2023

श्री छोटे लाल राय (क्रमशः) : इसीलिए आग्रह है कि उस काम को भी वरीयता सूची में रखने का काम करेंगे । महोदय, सरकार के विकास की बात आज देखिये अटल पथ बनने से क्या हुआ, गंगा पथ बनने से क्या हुआ, मुम्बई में हम लोग जाते थे देखते थे कि समुद्र के किनारे कैसे लोग बैठे रहते हैं लेकिन आज अटल पथ और गंगा पथ पर जब रात में हम लोग जब वापस आते हैं तो देखते हैं कि लाखों की भीड़ इस सरकार को बधाई देने के लिए तांता लगा रहता है कि इस तरह की भी सड़क बिहार में बनकर तैयार हुई है । हम तो बहुत बात बोलना चाहते थे लेकिन समयाभाव है तो हम आग्रह करेंगे कि आज के बजट में और विभाग जुड़े हुए हैं

हमारे कला, संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री हैं ये स्टेडियम भी बनाने की कोशिश करेंगे । इसमें दो जगह हैं एक परसा शहर के बीच में जगह है और हम लोग चाहते हैं कि अगर उनकी भी कृपा होती तो मारर और मस्तिचौक में स्टेडियम बनवाने का काम करेंगे । दूसरा, पंचायती राज विभाग है । अध्यक्ष महोदय, एक आग्रह है, सुनते हैं कि अशोक सम्राट हॉल के लिए पैसा गया है लेकिन उसका कोई मापदंड नहीं दिया गया है कि कैसे करना है, पैसा गया हुआ है तो उसको भी बनवा दिया जाय सरकार से यही आग्रह है और सरकार से हम मांग करते हैं कि जो हम बोले हैं उस पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है । शायद समय अब समाप्त होने वाला है । हम लोगों के जो गुरू हैं हमारे लालू प्रसाद जी, सबसे पहले छपरा से आये थे, छपरा उनका क्षेत्र रहा है इसलिए तेजस्वी जी से आग्रह करते हैं कि उनका भी वही क्षेत्र हुआ, जुड़े हुए हैं इसलिए छपरा जिले पर विशेष ध्यान दें और अगर भारत सरकार काम करने में कोई कोताही करती है तो हम लोगों की बहुत शिकायत रही है कि हाजीपुर एन0एच0 से जो छपरा है उसको निर्माण करने के लिए आप अपने ढंग से कोई व्यवस्था करिये कि उसका निर्माण हो जाये । कम से कम छपरा जाने में सब लोगों को सहूलियत हो जाये इतना कहते हुए सरकार को हम बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि और अपने काम में तेजी लाये । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री कृष्ण कुमार मंटू अपना पक्ष रखें । आपका समय 10 मिनट है ।

श्री कृष्ण कुमार मंटू : महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मुझे सदन में बोलने का मौका देने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय सचेतक महोदय एवं अमनौर की महान जनता को धन्यवाद देता हूं । महोदय, मैं आपसे यह आग्रह करना चाहूंगा कि आज पंचायती राज विभाग का भी बजट है और हम पंचायती राज के विषय पर ही कुछ बात करना चाहेंगे क्योंकि हम भी पंचायती राज से ही आप लोगों के बीच आये हैं । वर्ष 2001 में मुखिया के रूप में काम करने का मौका मिला तो वर्ष 2006 में प्रखंड प्रमुख प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने का मौका मिला, वर्ष 2009 में को-ऑपरेटिव के पैक्स अध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका मिला और वर्ष 2010 से आप सबों के बीच विधान सभा में आने का मौका मिला । निश्चित रूप से एन0डी0ए0 के शासन में पंचायतों का विकास हुआ है हम लोग तो वर्ष 2001 से देख रहे हैं । पहले हम लोगों के समय बहुत चर्चा थी पी0पी0 और एम0पी0 की मतलब प्रमुख पति और मुखिया पति । एन0डी0ए0 की सरकार ने महिलाओं को, अतिपिछड़ा वर्ग को,

अनुसूचित जाति वर्ग को आरक्षण दिया, उन्हें अधिकार दिया वे पद पर आयें लेकिन आज पंचायत प्रतिनिधियों की स्थिति बंधुआ मजदूर की हो गयी है । नीचे के प्रतिनिधि उन्हें मान-सम्मान नहीं देते हैं और उनका अधिकार नहीं लेने देते हैं । संयोग से यहां पर प्रत्यय अमृत जी बैठे हुए हैं इनके ऑफिस में हम लोग जाते हैं, इनके दर्जनों ऑफिस हैं जहां जाने पर बैठने का वेटिंगरूम है किताबें रखी रहती हैं, अखबार रखे रहते हैं, लोग पढ़ते हैं समझते हैं और पंचायतों में क्या हमारे पंचायत प्रतिनिधि को यह सुविधा नहीं मिलनी चाहिए ? जब वे पंचायत में जाते हैं तो रोड पर धक्का खाते हैं, धूप में खड़े रहते हैं, आर0टी0पी0एस0 काउंटर पर नेट नहीं रहता है कि उनका काम हो । इस तरह अनेक स्थितियां हैं जिसमें आज सुधार लाने की जरूरत है । वे पंचायत प्रतिनिधि हमारे सैनिक हैं, पंचायत प्रतिनिधि बिहार विकास के सैनिक हैं और सैनिक के मनोबल को तोड़कर कोई लड़ाई नहीं जीती जा सकती है इसलिए पंचायत प्रतिनिधियों के मनोबल को बढ़ाने की जरूरत है, उन्हें आगे बढ़ाने की जरूरत है और तभी हम ग्राम स्वराज के सपने को साकार कर सकते हैं जो महात्मा गांधी जी की सोच थी और हमारे पूर्वजों की सोच थी कि बिहार और राज्य का विकास पंचायत से ही होगा और पंचायत प्रतिनिधि के अधिकारों में जब कटौती होगी, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टाइड और अनटाइड दो योजना चलती हैं और उसे चुनने का अधिकार न ग्राम पंचायत को है और न पंचायत समिति को है । उसे चुनने का अधिकार उन लोगों को है ही नहीं वहां राशि जाती है और योजना चुनी हुई रहती है इस तरह की अनेक चीज हैं । आप पंचायत सरकार भवन बनाये, पंचायत सरकार भवन दिखावे की वस्तु बनकर रह गया है, पंचायत सरकार भवन में सरकार के पत्र के बावजूद कोई अधिकारी, कर्मचारी वहां नहीं बैठते हैं कि जनता का काम हो सके और वह सिर्फ दिखावे का एक भवन बनकर रह गया है और उस भवन में जंगल उपज गया है । हम तो देखते हैं बहुत सारी जगह पर हम मंत्री जी से आग्रह करना चाहेंगे तथा जानना भी चाहेंगे कि कितने पंचायत सरकार भवन जो बने हैं उसमें काम चल रहा है, हमारे सभी जनप्रतिनिधि यहां बैठे हुए हैं हम दावे के साथ कहते हैं किन्हीं के क्षेत्र में यदि मेरी बात गलत हो तो उठकर मेरा विरोध कर सकते हैं, मेरी बात को काट सकते हैं । यह सच्चाई है कि पंचायत सरकार भवन बना है लेकिन उसमें जो अधिकारी/कर्मचारी की प्रतिनियुक्ति की जाती है वे वहां पहुंचते नही हैं, वहां विकास पहुंचता नहीं है इसलिए उस पर त्वरित कार्रवाई की जरूरत है । आर0टी0पी0एस0 काउंटर, हमारे विधायक महोदय ने सवाल उठाया था क्वेशचन में वह मेरा भी क्वेशचन था, संयोग से मेरा क्वेशचन नहीं आया लेकिन नेट बंद रहता

है, नेट काम नहीं करता है जो कार्य का समय दिया गया है उस समय में वह पूरा नहीं होता और सारे प्रखंडों यही स्थिति है । एक प्रखंड नहीं हम तो पूरे जिले में देखते हैं सभी जगह वही स्थिति प्रखंडों की बनी हुई है । पंचायत प्रतिनिधि का सहयोग करने के लिए बी0पी0आर0ओ0, डी0पी0आर0ओ0 की व्यवस्था की गयी है लेकिन वे लोग पंचायत प्रतिनिधि का सहयोग नहीं उनका शोषण करते हैं । आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों के यहां एक बी0पी0आर0ओ0 महोदय हैं जो खुलेआम पंचायत प्रतिनिधियों से राशि मांगते हैं । मेरे पास उसकी ऑडियो क्लिप है यदि अध्यक्ष महोदय चाहेंगे तो मैं उसे सुना सकता हूं और मंत्री महोदय यदि कार्रवाई का आश्वासन देते हैं जो कहते हैं कि अगर हमको पैसा नहीं पहुंचेगा तो पंचायत में जांच कर कार्रवाई की जायेगी, जबर्दस्ती जांच की जायेगी और बिना गलती के आपको परेशान किया जायेगा । मंत्री महोदय यदि कार्रवाई करना चाहेंगे तो दावे के साथ कहते हैं कि उनके पास हम ऑडियो क्लिप को पहुंचाने का हम काम करेंगे । इसके साथ ही, हम माननीय मंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि जर्जर भवन चाहे अमनौर प्रखंड का कार्यालय हो, चाहे परसा प्रखंड का कार्यालय हो, चाहे मकेर प्रखंड का कार्यालय हो । हमारे भाई, साथी विधायक जी बोल रहे थे परसा के बारे में, संयोग से उनके हम वोटर भी रहे हैं एक ही मेरा क्षेत्र है एक प्रखंड दो भागों में है आधे के प्रतिनिधि छोटे लाल भाई, आधे के प्रतिनिधि हम हैं और उस प्रखंड की बिल्डिंग कितने वर्षों से बनी हुई है, उन्हीं से पूछ लिया जाय उसकी क्या स्थिति है । शायद हमारी बात पर सदन को भरोसा नहीं हो या आपको नहीं हो लेकिन उस बिल्डिंग की क्या स्थिति है हम मांग करते हैं मंत्री महोदय से कि वहां अमनौर, मकेर और परसा में बिल्डिंग बनाई जाय जिसमें पंचायत प्रतिनिधियों के बैठने की, उन्हें जाने की सुविधा जो भी हो सके उसको मिले यही मैं आपसे मांग करता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ आपने हमें बोलने का मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद । जय हिंद ।

टर्न-15/मुकुल/20.03.2023

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती मीना कुमारी । अपना पक्ष रखें, आपका समय 10 मिनट का है ।

श्रीमती मीना कुमारी : माननीय अध्यक्ष महोदय, बिहार सरकार ने जो वर्ष 2023-24 के लिए पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, कला संस्कृति एवं युवा विभाग एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए जो बजट का प्रावधान किया है, मैं उसके पक्ष में बोलने के लिए खड़ी हूं । महोदय, मैं धन्यवाद

देना चाहती हूं अपने विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को, बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को तथा वित्त मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी को जिन्होंने बिहार में विशेषकर सड़कों और पुलों के लिए अपने कुल व्यय का 4 प्रतिशत आवंटित किया है और साथ ही मैं धन्यवाद देना चाहूंगी आपको और मुख्य सचेतक श्री श्रवण कुमार जी को जो आज इस सदन में मुझे बोलने का मौका दिया । अध्यक्ष महोदय, मानव शरीर में जो महत्व रक्त संचार का है वही महत्व सभ्यता एवं जीवन तथा देश और राज्य की प्रगति में सड़क निर्माण का है । महोदय, आज बढ़ता बिहार न्याय के साथ विकास जो बिहार में हो रहा है उससे विपक्ष भी मुकर नहीं सकती । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार सरकार के द्वारा सड़क आधारभूत संरचना के नेटवर्क को सतत सुदृढ़ करने एवं राज्य के किसी भी कोने से अधिकतम 05 घंटे में राजधानी पटना पहुंचाने के लक्ष्य की प्राप्ति आज यह दर्शाती है कि बिहार में पथ निर्माण विभाग कितने अच्छे तरीके से काम कर रहा है । इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आमजन के लिए लोकार्पित किया गया है, उनमें से प्रमुख हैं, महात्मा गांधी सेतु के पूर्वी लेन का लोकार्पण किया गया है उसमें उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के आवागमन सम्पर्कता सुगम हुआ है । मुंगेर रेल-सह-सड़क परियोजना का कार्य पूर्ण कर लोकार्पित किया गया है, जे0पी0 गंगा पथ परियोजना के दीघा से पी0एम0सी0एच0 तक का लोकार्पण किया गया । माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार के द्वारा, पथ निर्माण विभाग द्वारा सात निश्चय पार्ट-2 सुलभ सम्पर्कता के तहत राज्य में सुगम एवं निर्बाध आवागमन को सुनिश्चित बनाये रखने निमित राज्य के सभी शहरों एवं सघन बसावटों से होकर गुजरने वाले मार्गों में आवश्यकतानुसार बाइपास पथ/फ्लाइओवर के निर्माण योजना के तहत कुल 14 (चौदह) बाइपासों के निर्माण हेतु 195.38 करोड़ रुपये की लागत राशि से स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें निविदा की कार्रवाई विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है । राज्य के अधीन सड़क नेटवर्क को सुदृढ़ करने के उद्‌देश्य से नाबार्ड ऋण सम्पोषित योजना अन्तर्गत वर्ष 2021-22 में कुल 20 पथों (लम्बाई 259.43 कि0मी0 एवं लागत 718.69 करोड़) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा कुल 18 अदद् पुल/पुलिया के निर्माण के लिए 103.42 करोड़ की लागत से स्वीकृति प्रदान की गई है । हमारी बिहार सरकार पंचायती राज में भी अहम भूमिका निभाई हुई है । उसमें मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के सतत् क्रियान्वयन हेतु दीर्घकालीन अनुरक्षण नीति लागू है । जिसमें वार्ड सदस्यों को अनुरक्षक के रूप में चिन्हित किया गया है जिन्हें 2 हजार रुपया मानदेय के रूप में तथा प्रति घर 30

रुपया प्रति माह संकलित उपभोक्ता शुल्क की आधी राशि प्रोत्साहन राशि के रूप में प्रावधानित की गयी है । साथ ही, राज्य योजना मद में 2000 रुपया अनुदान मद में प्रतिमाह/वार्ड राशि उपलब्ध कराई गयी है । अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार के माध्यम से पंचायती राज में, पंचायती राज विभाग के अंतर्गत क्रियान्वित मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना के तहत वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति के माध्यम से विभागीय संशोधित लक्ष्य 57,995 के विरुद्ध 57,693 वार्डों में पेयजल आपूर्ति कार्य पूर्ण कर लिया गया है एवं शेष 302 वार्डों में जारी कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जायेगा । इसी प्रकार मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना के तहत राज्य के कुल 1,14,507 वार्डों के बसावटों में गली-नाली का निर्माण हो गया है । पंचायती राज के तहत बहुत सारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें जल-जीवन हरियाली, सभी गांवों में सोलर स्ट्रीट लाइट लगायी जायेगी जो हर वार्ड में ब्रेडा के द्वारा 10 से 11 वार्ड में लगेगा सोलर लाइट । हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सपना है कि हर गांव को एक शहर की तरह बसाया जाय, उसमें उस ब्रेडा कम्पनी को रख-रखाव का भी जवाबदेही पांच साल के लिए दिया गया है । अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार कला के क्षेत्र में भी बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारा योगदान दिया है । उसमें मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत सभी जिलों के हर प्रखंड में सरकार के द्वारा स्टेडियम निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें अभी तक 199 स्टेडियमों का निर्माण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है और 353 की स्वीकृति प्रदान की गई है । इसी के तहत मुख्यमंत्री खेल विकास योजना अन्तर्गत 23 जिलों में 41 एकलव्य राज्य आवासीय खेल प्रशिक्षण केन्द्र स्वीकृत हैं, जिसमें से वर्तमान समय में 39 प्रशिक्षण केन्द्र संचालित हैं । कुल 07 नये केन्द्रों की स्वीकृति हेतु कार्रवाई प्रक्रियाधीन है । अध्यक्ष महोदय, हम भी मधुबनी जिला से आते हैं और हमारे मिथिला के लिए भी मिथिला चित्रकला संस्थान, मधुबनी के भवन का निर्माण 2448.58 लाख की लागत से निर्माण किया जा रहा है । सर्टिफिकेट कोर्स एवं डिग्री कोर्स संचालित है । अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी और बिहार सरकार ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के कल्याण हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है । जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के बच्चों/बच्चियों के लिए बी0पी0एस0सी0 की पी0टी0 पास करने पर 50 हजार रुपया और यू0पी0एस0सी0 की पी0टी0 पास करने पर 1 लाख रुपया उनको प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता है, जिससे वे

अपनी आगे की पढ़ाई पूरी कर सकें और अपने सपनों को वे साकार कर सकें । यू0पी0एस0सी0 में 113 एवं बी0पी0एस0सी0 में 3394 अभ्यर्थियों ने इसका लाभ उठाया है और वर्ष 2022-23 में 6.50 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है । अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग में इस तरह की बहुत सारी योजनाएं, गरीब लोग जिसको कोई देखने वाला नहीं था हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 18 सालों में जो सत्ता संभाली है उसमें वे गरीब/दबे-कूचले वर्गों के लिए जो कदम उठाये हैं वह सराहनीय है । इसमें मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम अंतर्गत सहायता योजना, नये आवासीय विद्यालय एवं छात्रावास की स्थापना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावास अनुदान योजना, बिहार अनुसूचित जनजाति शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना योजना । अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार के लोगों के लिए जो किया है वह आने वाले समय में बहुत कम उम्मीद किया जा सकता है कि अब कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो इस तरह से गरीब लोगों के लिए सोचेगा, वे भीम राव अम्बेडकर के कदमों पर चलकर गरीबों के लिए अपना सपना साकार कर रहे हैं । अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग को हमारा कुछ सुझाव है, जो हमारे क्षेत्र के अधीन भी है । तेनुआही चौक (एन0एच0-227) से खुटौना (एस0एच0-2 लेन) जिसको 15 किलोमीटर चौड़ीकरण करवाना है । अध्यक्ष महोदय, यह खुटौना मुख्य सड़क है, वह जनहित में अति आवश्यक है इसलिए इसको प्राथमिकता में इसको ले लिया जाय । एक पथ निर्माण विभाग से ही, जब माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले साल गये थे, जल संसाधन विभाग का जो साढ़े 4 करोड़ का जयनगर में उद्घाटन किये थे तो मुख्यमंत्री महोदय को वहां पर जयनगर में रेलवे गुमटी है वहां पर बस एक मिनट की दूरी को 2 किलोमीटर घूमकर उनको भी जाना पड़ा तो उस समय ये घोषणा करके आये थे कि जयनगर में बाइपास बनवायेंगे । उसको भी गंभीरता से ले लिया जाय, उस पर भी ध्यान देकर उसको बनवा दिया जाय । अध्यक्ष महोदय, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग को भी मेरा एक सुझाव है कि जो खाजेडिह में 13 वर्षों से जो स्टेडियम अर्धनिर्मित है उसका सारा काम हो चुका है, हमको लगता है कि वह लास्ट स्टेप में है उसको जल्द-से-जल्द करवा दिया जाय, यही मैं आपसे आग्रह करूंगी । अध्यक्ष महोदय, मैं एक महिला प्रतिनिधि हूं और बिहार की महिलाएं उन्नति और स्वालंबन चाहती हैं । साथ आना शुरुआत होती है, साथ रहने से प्रगति

होती है और साथ काम करने से सफलता मिलती है । इसी आशा के साथ मैं इस बजट का समर्थन करती हूं और उम्मीद करती हूं । पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर आगे बढ़े । अन्त में मैं अपनी बातों को विराम देते हुए विपक्ष के लिए इस पंक्ति को कहना चाहूंगी :

''जब भारत अपना बिखरा था, तब चन्द्रगुप्त ने अखण्ड किया,
फिर अपनी कलम के दम पे उसे भीमराव ने बुलन्द किया ।

XXX

अध्यक्ष : माननीय सदस्या, आपका समय ।

श्रीमती मीना कुमारी : अध्यक्ष महोदय, सिर्फ एक लाइन बची हुई है ।

XXX

जागो देशवासियो, जागो । जय हिन्द, जय भारत, जय नीतीश कुमार, जय बिहार ।

(व्यवधान)

टर्न-16/यानपति/20.03.2023

अध्यक्ष: माननीय सदस्य श्री भीम कुमार सिंह, अपना पक्ष रखें । आपका समय मात्र 5 मिनट।

श्री भीम कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय......

(व्यवधान)

अध्यक्ष: शांति बनाए रखें ।

श्री भीम कुमार सिंह: सरकार द्वारा जो पथ निर्माण विभाग की मांग......

(व्यवधान)

अध्यक्ष: क्या बोलना चाहते हैं, माननीय भीम बाबू, एक मिनट । बोलिये ।

श्री संजय सरावगी: माननीय सदस्या ने जो शब्द का इस्तेमाल किया है कि इस देश की कुर्सी पर कौन बैठा है, वह असंसदीय शब्द है अध्यक्ष महोदय और देश के प्रधानमंत्री जी पर ऐसा शब्द बोलना यह घृणित कार्य है अध्यक्ष महोदय, उसको प्रोसीडिंग से निकाला जाय ।

अध्यक्ष: मैं उसको दिखवा लूंगा । असंसदीय होगा......

श्री संजय सरावगी: नहीं अध्यक्ष महोदय, देश के प्रधानमंत्री जी के बारे में अपशब्द बोला गया है अध्यक्ष महोदय......

अध्यक्ष: आपने सूचना दी, उसको कार्यवाही से मैं निकलवा दूंगा । बैठिए । मैंने कहा कि कार्यवाही से निकलवा दूंगा ।

(व्यवधान)

अब इतना समय आप क्यों बर्बाद कर रहे हैं । मैंने कहा कि आपने सूचना दी, मैं देख लूंगा और उसको कार्यवाही से निकलवा दूंगा । अब बैठिए । माननीय सदस्य श्री भीम कुमार सिंह जी, अपना पक्ष रखें ।

श्री भीम कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा जो पथ निर्माण विभाग की मांग प्रस्तुत की गई है उसके समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । महोदय, आपका ध्यान मैं औरंगाबाद जिला के गोह विधान सभा क्षेत्र की तरफ आकृष्ट कराते हुए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराता हूं । हसपुरा बाईपास का डी0पी0आर0 पथ निर्माण विभाग द्वारा बनवाने के बावजूद अभी हसपुरा बाईपास नहीं बन सका महोदय जिसके कारण हसपुरा बाजार में जाम की गंभीर समस्या लगी रहती है । महोदय मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हसपुरा बाईपास को जितना शीघ्र हो बनवाने की कृपा करें । हसपुरा प्रखंड के बस स्टैंड से अमझर शरीफ होते हुए त्रिसंकट बैकुंठ पथ लगभग 20 वर्षों से जर्जर स्थिति में है उसको बनवाने की अति आवश्यकता है ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष: क्या हुआ ।

(व्यवधान)

श्री भीम कुमार सिंह: वह सड़क ग्रामीण कार्य विभाग ने लगभग 15 वर्ष पहले बनवाया था आज इसकी स्थिति काफी जर्जर है और मैं आपके माध्यम से......

अध्यक्ष: विधान सभा के माननीय सदस्य के अलावे रिपोर्टर को छोड़कर कोई अन्य सदन में प्रवेश नहीं करेंगे ।

(व्यवधान)

चलिए हो गया, बोलिये ।

श्री भीम कुमार सिंह: महोदय, वह सड़क ग्रामीण कार्य विभाग ने बनवाया था, लगभग 15 साल पहले, आज इसकी स्थिति काफी जर्जर है और ग्रामीण कार्य विभाग ने आर0सी0डी0 को अपना प्रस्ताव भी दिया है यह सड़क शुरू से और अंत तक दोनों सड़क आर0सी0डी0 से मिलता है जिसकी दूरी लगभग 13 कि0मी0 है महोदय । इसको मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं सरकार से कि इस सड़क को बनवाया जाय । औरंगाबाद जिला हसपुरा से अरवल से संभुआटेरी होते हुए मेहंदिया तक जो पथ एन0एच0 139 से मिलता है वह काफी जर्जर है, यह अरवल जिला में पड़ता है महोदय और आर0ई0ओ0 विभाग ने आर0सी0डी0 विभाग को अपना प्रस्ताव दिया है इसको अपने में समाहित करके और इसको बनवाया जाय । यह सड़क दो जिला

को जोड़ती है इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि इस सड़क को पथ निर्माण के अधीन लेकर के जितना जल्दी हो बनवाया जाय । गोह प्रखंड में रफीगंज, महुआधाम रोड से दनियाहर होते हुए प्राथमिक विद्यालय भवानीपुर तक बाईपास सड़क बनवाना अतिआवश्यक है महोदय, क्योंकि पुल के चलते वहां जाम लग जाता है और काफी लोगों को परेशानी होती है और सरकार के पास जगह भी है और इस सड़क के बन जाने से गोह बाजार के जाम की समस्या भी समाप्त हो जाएगी । गोह प्रखंड के उपहारा पंचायत के बिलारू और हथियारा पंचायत के मठियागांव के बीच पुनपुन नदी पर पुल अतिआवश्क है जनहित में महोदय, यह मांग सदियों से चली आ रही है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि इस पुल को बनवा दिया जाय, यह पुल दो प्रखंड को जोड़ता है । गोह प्रखंड के मीरपुर पंचायत के अंकुरी गांव और हंसपुरा प्रखंड के मलहारा पंचायत के जखौरा गांव के बीच पुनपुन नदी पर पुल निर्माण कराने की कृपा की जाय महोदय । रफीगंज के धावा नदी में बाघासोती गांव एवं बेरीगांव के बीच पुल निर्माण अतिआवश्यक है महोदय, इस पुल के बन जाने से जिला में लोगों को जाने में बहुत ही शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा और जिला से लोग जुट जाएंगे इसलिए इस पुल को मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा इसको जितनी जल्द हो बनवाया जाय महोदय । हसपुरा प्रखंड के धुसरी पंचायत के ग्राम भौली एवं ग्राम कैथी के बीच पुनपुन नदी पर पुल बनवाना अतिआवश्यक है महोदय । लगभग 50 गांव को यह पुल जोड़ता है इसलिए वह नदी वहां काफी गहरा है महोदय इसलिए आपके माध्यम से मैं आग्रह करूंगा कि इसको बनवाया जाय महोदय और मैं अपने आदरणीय माननीय उप मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि बहुत सारे कार्य हमारे क्षेत्र में हो रहे हैं, पथ निर्माण विभाग के माध्यम से इसलिए मैं माननीय उप मुख्यमंत्रीजी सह पथ निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं ।

अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ । अब आप स्थान ग्रहण करें, बहुत-बहुत धन्यवाद । माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह अपना पक्ष रखें, आपका समय 10 मिनट ।

श्री संजय कुमार सिंह: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका हृदय से हम आभार प्रकट करते हैं......

(व्यवधान)

देखिए, थोड़ा धैर्य से सुन लीजिए । माननीय अध्यक्ष महोदय आपका हम हृदय से आभार प्रकट करते हैं कि आपने मुझको समय दिया है बोलने का, अपने नेताओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं......

अध्यक्षः   माननीय सदस्य, इत्मीनान से आप अपने पक्ष को रखिए ।

श्री संजय कुमार सिंहः महोदय, एकदम इत्मीनान से, मैं अपने नेताओं के प्रति भी आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने आज बोलने का हमको समय दिया है, मैं अपनी उस लालगंज की जनता के प्रति आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने आज मुझको इस सदन में चुनकर भेजा है और इस बिहार के अंदर आवाज बनने की हमको ताकत दी है । बंधुओ, दो विषय ध्यान रखना है, यह सदन वैचारिक विषय का सदन है, यह सदन केवल आरोप और प्रत्यारोप का नहीं है और वह पढ़ लीजिए संसदीय लोकतंत्र में विरोधी दल भी सरकार का अंग है, हम भी सरकार के अंग हैं । इसका ध्यान रखते हुए......

अध्यक्षः   आप अपनी बात को रखिए, वह सबलोग पढ़े हुए हैं । कोई आदमी नहीं होंगे जो नहीं पढ़ लिए होंगे, आप अपनी बात को रखिए । अपना समय नहीं बर्बाद करें ।

श्री संजय कुमार सिंहः अध्यक्ष महोदय, हमारा सौभाग्य है कि हमारे जिले से ही पथ निर्माण मंत्री और बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी चुनाव जीतकर आते हैं, मैं अभी बजट भाषण उनका देख रहा था, मैं अभी उनके इस किताब को देख रहा था और मैं थोड़ी सी बात अपने क्षेत्र की कहूंगा इसलिए पहले कह दूंगा क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरी बातों से तिलकी लग सकती है और मेरा विरोध शुरू हो । अध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र में एक सराय से लेकर लालगंज को जोड़नेवाली सड़क है, 44 करोड़ की इस योजना को पहले से 5.7 मीटर की सड़क है, अभी उसको 7 मीटर करने की योजना है विगत एक वर्ष से लगातार वह फाइलों में दौड़ रही है, मैं यह नहीं समझता हूं और जब अंतिम मुकाम पर आया तो आठ महीने, सात महीने पहले आनेवाली सरकार उसपर कुंडली मारकर बैठ गई है, वैशाली जिले की यह महत्वपूर्ण सड़क है । दूसरा विषय है हाजीपुर से वैशाली को जानेवाली सड़क है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी बुद्ध सम्यक संग्रहालय के लिए वहां हर हफ्ते, हर महीने जाते हैं, मेरा अनुरोध होगा कि उक्त सड़क जो 7 मीटर चौड़ी है जिसके कारण प्रत्येक माह में दर्जनों एक्सीडेंट से लोग मर रहे हैं उसको कम से कम 10 मीटर किया जाय ताकि विदेशों से आनेवाले पर्यटक भी उसको अच्छा महसूस कर सकें और अच्छी सड़क बन सके । (क्रमशः)

टर्न-17/अंजली/20.03.2023

श्री संजय कुमार सिंह (क्रमशः) : तीसरा विषय है हमारा, लालगंज 1857 में नगरपालिका बना था, शायद बिहार का कोई वैसा क्षेत्र नहीं होगा जो इतना पुराना नगरपालिका क्षेत्र होगा, परंतु वहां की सड़कें जर्जर हैं । हमारा अनुरोध होगा पथ निर्माण मंत्री महोदय

से कि वहां की सड़कों को आप गोद लीजिए और लालगंज की सड़कों को जो घाघरा नहर से लेकर के प्रखंड कार्यालय होते हुए मुख्य मार्ग को जोड़ती है, उसको आप पथ निर्माण में लेकर के निर्माण कराने की कृपा करिए । चौथा विषय है कि...

(व्यवधान)

एन0डी0ए0 के विषय पर आ रहे हैं । चौथा विषय है कि हमारे यहां बांध पर सड़क की बहुत जरूरत है । डेढ़ किलोमीटर बांध पर सड़क की जरूरत है, कृपा करिए वहां की जनता भी आपको धन्यवाद देगी, वहां की जनता भी आपके प्रति आभार प्रकट करेगी । अध्यक्ष महोदय, मैं अभी बजट भाषण देख रहा था और अभी देख रहा था कि पांच हजार करोड़ का प्रस्ताव बिहार की सरकार ने रखा है, उनका पूरा बजट पांच हजार करोड़ का है । आप में से कल-परसों कोई कह रहे थे परसों कि ''माल महाराज का, मिर्जा खेले होली'' कैसे होगा ? सवा लाख करोड़ प्रधानमंत्री जी ने इस बिहार को दिया है, बिहार की सड़कें बन रही हैं सवा लाख करोड़ से और पांच हजार करोड़ की सड़कें बनाकर और उसमें भी वेतन देकर आप इठला रहे हैं, इतरा रहे हैं और सवा लाख करोड़ रुपया एक और एक केंद्र सरकार ने बिहार की सड़कों को दिया है । ये हम नहीं बोल रहे हैं, बिहार सरकार की ये किताब बोल रही है कि सवा लाख करोड़ की परियोजनाएं बिहार के अंदर भारत सरकार की दी हुई चल रही हैं ।

(व्यवधान)

आपको तो बोलने का अधिकार ही नहीं है ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, शांति बनाये रखें ।

श्री संजय कुमार सिंह : अभी के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी, एन0डी0ए0 के मुख्यमंत्री थे, यह हमेशा ध्यान रखिएगा और अभी वे महागठबंधन के मुख्यमंत्री हैं इसका भी ध्यान रखिएगा । जब एन0डी0ए0 के मुख्यमंत्री थे, इस किताब में एक भी उल्लेख नहीं है कि आठ महीने के अंदर की सरकार क्या कर रही है, क्या करने वाली है, केवल एक उल्लेख हमको दिखा है । पहले जब किताबों के पन्ने हम पलटते थे तो हजारों-हजार करोड़ की परियोजनाएं केवल नालंदा जिले में दिखाई पड़ती थीं । आज इस किताब के पन्ने पर लिखा है 1600 करोड़ रुपया केवल एक राघोपुर के क्षेत्र में, जहां से हमारे उप मुख्यमंत्री जी जीतकर आते हैं वहां पर बजट दिया गया है, बाकी पूरा बिहार सूना रहेगा । बिहार के, यह 1600 करोड़ है देखिए, यह मैं नहीं बोल रहा हूं, यह आपकी किताब बोल रही है । अगर 1600 करोड़ की योजना एक विधान सभा में दी जाएगी और 40 करोड़ की हमारी योजनाओं को लटकाया जाएगा तो यह हमारी क्षेत्र की जनता के साथ न्याय नहीं हो सकेगा ।

अध्यक्ष महोदय, ये जो महागठबंधन वाले लोग हैं उनको बोलने का अधिकार नहीं है। हमने वह दिन देखा है जब इस बिहार के अंदर एक पथ निर्माण मंत्री थे, पता नहीं महरूम हैं कि जीवित हैं, मैं नहीं जानता हूं लेकिन इलियास हुसैन साहब थे, वे इलियास हुसैन साहब जेल क्यों गए ? अलकतरा घोटाले में जेल गए, शर्म करिए आप । बिहार की सड़कें आपने नहीं बनाईं, अगर सड़कें बनी हैं बिहार में तो वह हमने बनाया है, हमारी एन0डी0ए0 की सरकार ने बनाई है, हमारे मंत्रियों ने बनाया है, हमारे लोगों ने बनाया है । जिस चमचमाती सड़कों को आप पीठ थपथपा रहे हैं वे सड़कें हमारी बनाई हुई हैं, वे सड़कें हमारे मंत्रियों ने बनाकर के आपको दी हैं और आप इठलाइए मत, वहां से उस इलियास हुसैन जी के अलकतरा घोटाले वाले बिहार की सरकार को हमने निकाल कर के एन0डी0ए0 की सरकार में लाया है और हमने बिहार के अंदर चमचमाती हुई सड़क दी है और आप उस सड़क पर जो इठला रहे हैं, ये किताबें लिख रहे हैं यह पूरा का पूरा पुलिंदा एन0डी0ए0 की सरकार में किए गए काम का ब्यौरा है । आपके आठ महीने की सरकार का ब्यौरा नहीं है । आप शर्म करिए इस बात पर ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, एक-दो मिनट का समय दिया जाय ।

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री संजय कुमार सिंह : महोदय, मैं अभी पढ़ रहा था कि जिस पांच हजार करोड़ का बिहार सरकार का बजट है ये केवल...

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री शकील अहमद खां, अपना पक्ष रखें । आपका समय 14 मिनट है ।

श्री शकील अहमद खां : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती प्रस्ताव के खिलाफ खड़ा हुआ हूं । हुजूर-ए-आला, पक्ष और विपक्ष हमारे डेमोक्रेसी की खूबसूरती है इसका एकरार हम सब लोगों को है और विपक्ष अपना एक क्रेटिकल असेसमेंट रखता है और पक्ष जो है उस असेसमेंट को लिखकर के या समझ करके उसको जोड़ने का प्रयास करता है । उसी तरह से हमारे देश का जो स्ट्रेक्चर है फेडरल स्ट्रेक्चर है । केंद्र जो है और राज्य, दोनों सरकारें एक दूसरे के लिए पूरक भी होती हैं और एक दूसरे के कल्याणकारी योजनाओं को, जो जनता को लाभ मिले उसके लिए करती हैं । सरकारें जो हैं वह इरादों से चलती हैं, सरकारें जब इरादा करती हैं तब काम आगे बढ़ता है और वह इरादा हमको आज दिखता है । पक्ष और विपक्ष के मामले में मेरे पास पुराने, यह खूबसूरत संयोग है कि वर्ष 2022-23 का भी बजट मेरे पास है और यही सुंदरता भी है कि जब लोग विपक्ष में होते हैं तो उन बातों के खिलाफ

बोलते हैं जिनके पक्ष में खड़े होते हैं और यह बड़ी अजीब बात है और अच्छी बात भी है कि ये दोनों हमारे पास हैं । नितिन जी, मेरे अजीज भाई हैं और माननीय सदस्य हैं ये दोनों पेज भी सोलह पेज के हैं, सोलह ही सोलह पेज है इसमें, तो यह अच्छा लगता है इसमें वाद-विवाद होता है । एक शेर याद आ गया और ये शेर माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री और इस सरकार के लिए है, जो मैंने इरादे की बात की और यह लीडरशिप के ऊपर भी आती है कि ''निगह बुलंद, सुखन दिल-नवाज'', निगह बुलंद, समझ रहे हैं-ऊंची सोच की, सुखन दिल-नवाज-आपके बात करने का अंदाज प्यारा हो, तो

''निगह बुलंद, सुखन दिल-नवाज,
जां पुर-सोज, आपके दिलों में दर्द भरा हो,
यही है रख्त-ए-सफर, मीर-ए-कारवां के लिए,
जो कारवां को आगे लेकर चलता है ।''

उसके लिए ये सारे गुण उसमें होने चाहिए । दिक्कत यह है कि मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, दिक्कत यह है कि हमारे यहां आज के दिन में लोग जनता के बीच में बोल जाते हैं वायदे कर लेते हैं और उन वायदों को, एक और साहब हैं, मैं नाम भी नहीं ले रहा हूं, वे कहते हैं कि वह वायदा नहीं था, जुमले थे तो-

''सुखन दिल-नवाज जां पुर-सोज, इरादे कहां गए ।''

मुझे आज अफसोस है, आप सब के पास यह कॉपी होगी । मुझे अफसोस इस बात का है कि हमारे उप मुख्यमंत्री, जो आपके भी उप मुख्यमंत्री हैं, बिहार के हैं, केंद्र प्रायोजित योजनाओं के मामले में उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ रहा है इसलिए कि उनको देरी हो रही, यह कभी ऐसा नहीं होता, यह शर्मनाक स्थिति क्यों पैदा होती है क्योंकि दो सब्जेक्ट में खास तौर पर हमको लगता है कि केंद सरकार को और आप सब लोगों को यह सोचना चाहिए कि जैसे कि इंडो-नेपाल बॉर्डर, 552 किलोमीटर का बॉर्डर एरिया है, छह-सात जिले से गुजरता है और मंत्री जी जब अपनी बात रखेंगे तो वे बताएं यहां पर कि क्या उस योजना में देरी हो रही है कि नहीं हो रही है और अगर हो रही है तो किसके कारण से हो रही है, क्या केंद्र उसमें रोड़े अटका रहा है, क्या वजह है और अगर यह वजह है तो इसका मतलब है कि केंद्र सरकार, बिहार सरकार की मदद नहीं करना चाहती है, यह मैं कहना चाहता हूं । महोदय, क्योंकि वह सड़कें बहुत इंपोर्टेंट है, उन सड़कों का निर्माण समय पर हो जाना इंपोर्टेंट है और इसीलिये आप सब लोगों से मैं कहता हूं, आग्रह करता हूं कि हमारे बहुत सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो बिहार से पार्लियामेंट में हैं

उनसे कहिए कि इन योजनाओं के लिए, इसीलिये तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहां जाते हैं कि अपने-अपने राज्य के बारे में बात करेंगे । मैं कभी नहीं देखता कि मनरेगा के मंत्री हों या किसी और चीज के मंत्री हों, प्रधानमंत्री आवास योजना के मंत्री हों, वे यह कहें, बिहार को खास तौर पर कि बिहार में इन योजनाओं में कमी हो रही है उसकी वजह क्या है ? क्या वजह है, आपको इसलिए मैं कह रहा हूं, आपका रहना बहुत इंपोर्टेंट है, विपक्ष की जरूरत बहुत इंपोर्टेंट है, इसलिए जब दिल्ली सरकार में हम जाते हैं, भारत सरकार में तो हमारी जिम्मेवारी बनती है और एक बात और याद दिला दूं, जब इरादे मजबूत होते हैं तो सरकार किस कलर की है वह नहीं देखा जाता । आप रिकॉर्ड देख लें बिहार का फ्रॉम 2004 टू 2014 आपके केंद्रांश का पैसा बिहार के लिए किस अनुपात में था और आज किस अनुपात में है, पता कर लें । कौन थी सरकार उस वक्त, माननीय मनमोहन सिंह, यू0पी0ए0 की सरकार थी और लालू प्रसाद जी उसमें रेलमंत्री थे और यहां सब लोग थे । कौन थे वे लोग ? इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं...

(व्यवधान)

अध्यक्ष : वे अपना पक्ष रख रहे हैं । आप स्थान ग्रहण करें ।

टर्न-18/सत्येन्द्र/20-03-2023

श्री शकील अहमद खां: मैं तो तथ्यों के आधार पर अपने विपक्ष के साथियों से कहना चाहता हूॅं कि अगर 2004 से 2014 तक एक सरकार थी, भारत की सरकार थी, मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उसके पहले फोर लेनस की शुरूआत हमारे मरहूम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शुरू किया, उसकी हम सराहना करते हैं । हमने तो मना नहीं किया लेकिन आपको तो ये सराहना करनी चाहिए कि जब यहां सरकार एन0डी0ए0की थी तो उस समय केन्द्र की एक ईमानदार, एक वफादार जो सरकारी थी और उस समय किसी के साथ डिस्क्रीमिनेशन नहीं हो रहा था । ये होती ईमानदार सरकार और ये होता है उसका अंदाज । अब मैं कुछ चीजें कहना चाहता हूॅं और माननीय उपमुख्यमंत्री जी, जिनके ऊपर आप टीका-टिप्पणी करते रहते हैं कीजिये, कोई दिक्कत नहीं और अभी कुछ दिन तक चलेगा । यह बात मैंने पिछले दिनों में भी कहा था। एक शेर है उपमुख्यमंत्री जी और पूरा सदन सुन रहा है।

उम्र वेशक कम है लेकिन मुझे तजुर्बे बहुत हैं,
मुझे मारने वालों से कह दो कि मुझे चाहने वाले बहुत हैं,
और कुछ सवालों का जवाब, जवाब नहीं वक्त देता है,
और वक्त जो जवाब देता है, वह लाजवाब होता है।

इसलिए मैं कहना चाहता हूॅं कि आज मुझे बहुत तकलीफ हुई, उपमुख्यमंत्री जी का जब यह रिपोर्ट देखा । मैं ये कहना चाह रहा हूॅं, आप देखिये कि बिहार जिसने रोड के मामले में, कम्युनिकेशन के मामले में एक लम्बी प्रगति की है हमारे माननीय नीतीश जी की अगुआई में तो इससे कहां इंकार किया जा सकता है। क्या आप और हम इंकार करेंगे ? मैं तो बहुत ही सुदूर इलाके में रहता हूॅं जो यहां से 350 कि0मी0 दूर है । वाकई में और योजनाओं के माध्यम से, खासकर जब सात निश्चय(1) और सात निश्चय(2) आया, छोटी छोटी गलियां हमारी जो थी और आपकी, वह बनीं पंचायत के माध्यम से, समिति के माध्यम से बनी जो बहुत सारे, हजारों दलित के इलाके में वो सड़कें गयी हैं, यह सच है और इसलिए वह आंकड़ें देना चाहता हूॅं आंकड़ें ले लीजिये, इनको मैं जवाब देता हूॅं । देखिये, आपके अभी तक राष्ट्रीय उच्च पथ 5977 कि0मी0 बना और उसके बाद जो यहां का वृहत जिला पथ है वह 15637कि0मी0 बिहार ने बनाया है, तो आप इस सच्चाई से कैसे इंकार कर सकते हैं। आप सच से इंकार नहीं कर सकते हैं इसलिए मैं आपसे यह कहना चाहता हूॅं, जहां तक बात पैसा का है,तो बकाई में यह कहां से आयेगा । जब इस देश का 12 लाख करोड़ रू0, चंद लोगों को टैक्स के पैसे को 2-4 घरानों को दे दी जायेगी तो पैसा कहां से आयेगा? यह सवाल है । महोदय, जब 2014 में सरकार बनी थी तो उस समय जो दुनिया का 6ठें स्थान पर था और वह आज तीसरे स्थान पर आ गया है। यहां सवाल वही है, सवाल यह है कि आपने दोस्तों के माध्यम से जनता की गाढ़ी कमाई को बांट दिया है, यह सच्चाई है और आईना दिखाया जा रहा है, हमारे देश और समाज को दिख रहा है । महोदय, जहां तक देश की आर्थिक स्थिति की बात है, इसके मजबूत हुए बिना देश समाज तरक्की नहीं कर सकता है । आर्थिक स्थिति अगर हमारी कमजोर होगी महोदय, आज किसको नहीं पता है कि डॉलर के मुकाबले में हिन्दुस्तान का रू0 कमजोर हुआ है और यह किसके जमाने में हुआ, किसको नहीं मालूम कि हिन्दुस्तान में जो बुनियादी चीजें हैं, चाहे वह गैस हो, तेल हो इसका असर पड़ता है पहले जो प्रति बैरल कम पैसे में तेल मिलता था उस समय पेट्रोल और डीजल की कीमतें क्या थीं, विपक्ष के मित्रों, यह दोहरा चरित्र से लाभ कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं अपने स्पीच के खात्मे पर आता हूॅं । मैं चाहता हूॅं कि हमारी ये सरकार जो आज है, उसको मैं कुछ राय देना चाहता हूॅं और यह सब लोगों के लिए राय है । मेरी राय यह है कि हमारा पूरा बिहार प्रदेश कई इलाके में बंटा हुआ है और जो तरक्की के मापदंड है, वह भी कई जगह बंट जाते हैं तो खासतौर पर जो सीमांचल का इलाका है, सीमांचल का इलाका ऐसे तो हमारे तमाम जिले बाढ़ से और सुखाड़ से ग्रसित रहता

है लेकिन सीमांचल के जिला में जो सड़कें बनती हैं और टूट जाती हैं तो सीमांचल के इलाके के जो पथ चार जिलो को जोड़ता है, उसका ख्याल ज्यादा रखा जाय। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी राय है कि आपके पथ निर्माण विभाग की बहुत सारी सड़कें सिंगल लेन की है तो जो सिंगल लेन की सड़कें हैं उसको डबल कैसे बदला जाय, आसानी से जल्दी कैसे बदला जाय,, उसके लिए पैसे का प्रोविजन कैसे किया जाय उसका ख्याल सजेशन के तौर पर सरकार रखती है तो उसका लाभ सबको होगा । होगा कि नहीं? बोलिये, ताली तो बजाईए। मुहब्बत से बात कीजिये, डिबेट प्यार से होता है, मैं तो चाह रहा था अभी बचौल भाई रहते तो और मजा आता, बातचीत होती, बहरहाल और जब सड़कें बनती है तो उसके दोनों तरफ, इसे आप और हम सभी महसूस किये होंगे कि वहां पर मिट्टी की भराई नहीं होती है जिससे फ्लैंक ठीक नहीं होती है तो दुर्घटना की संभावनाएं हो जाती है। जब भी कोई संवेदक सड़क बनाता है तो सड़क के निर्माण में इस बात का खास ख्याल जो हमारे पदाधिकारी है, इस पर रखा करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा । ये दो-तीन सजेशन थे हमारे जो मैं देना चाहता हूँ, आप इसको जरूर रखें। एक और है जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी है, उसके बारे में भी जिक्र है, कुछ पढ़ लिया करो भाई सी0एस0आर0 फंड बहुत जरूरी है। सी0एस0आर0 फंड चूंकि समाजिक कामों में लगता है, मैंने देखा है लिस्ट है बहुत, सी0एस0आर0 फंड को अगर ज्यादा बढ़ाया जाय तो सामाजिक सरोकार में काम आयेगा और ये भी मनमोहन सिंह के जमाने में हुआ था कि कम्पनियां जो पैसे बनाती है, वह ढ़ाई प्रतिशत सामाजिक सरोकार में लगायेगी, यह सत्य है। जैसे मनरेगा सत्य है, जैसे 70 हजार करोड़ रू0 किसानों की माफी सत्य है, उसी प्रकार यह भी सत्य है कि ढ़ाई प्रतिशत पैसा सामाजिक सरोकार में लगेगा । इस बात पर तो बजाओं, तालियां बजाओ। इसीलिए इन दो मामले में मंत्री जी जवाब देंगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ी, कौन सी बदनियति थी कि उसकी वजह से बिहार को नुकसान उठाना पड़ा । इसी सदन ने बिहार के तमाम सदस्यों ने स्पेशल राज्य का दर्जा मांगा था और मांगने के बाद भी आजतक नहीं मिला जिसमें आप भी शामिल थे । बोलिये आप अपने मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट को कि दिल्ली में जायें और जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनको ये कहें कि बिहार की हालत खराब हैं फिर मैं चाहता हूँ कि बिहार को यह दर्जा मिले, असत्य बोलकर नहीं निकला जा सकता है।

(क्रमशः)

टर्न-19/मधुप/20.03.2023

...कमशः...

श्री शकील अहमद खाँ : सवा लाख करोड़ रूपये का जो यह वादा, वादा ही वादा, कितने पैसे आउट ऑफ सवा लाख अभी तक बिहार को दिये गये, आज इसको बताया जाय । ऐसे स्वीपिंग रिमार्क्स दे दीजिएगा ? ऐसे ही स्वीपिंग बात कह दीजिएगा कि इतना दिया गया । कितना दिया गया ? इसलिये फेडरल स्ट्रक्चर में जो बात होती है, केन्द्र की जिम्मेदारी और राज्य की जिम्मेदारी एक-दूसरे से बच नहीं सकती लेकिन केन्द्र सरकार अगर ईमानदार हो...

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हुआ ।

श्री शकील अहमद खाँ : सर, बस आखिरी हो गया ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपका समय समाप्त हो गया ।

श्री शकील अहमद खाँ : बस अब आखिरी शेर है, सर । यह शेर हमारे मुख्यमंत्री जी अभी यहाँ रहते तो बड़ा मजा आता क्योंकि आप सब लोग थे, आप सब लोगों ने उनके सानिध्य में काम किया है, बिहार को तरक्की करते हुए देखा है । आपने वह बजट पेश किया है जब आप मंत्री थे तो यह शेर बहुत मजेदार है, सुन लीजिए बड़ा मजेदार है - अब वही शख्स बगावत पर उतर जाया है, हुजूर, यह आखिरी शेर है।

अब वही शख्स बगावत पर उतर आया है,
मुद्दतों जिसने मेरे घर का नमक खाया है ।

ताज्जुब है लेकिन यह जम्हुरियत की खूबसूरती है । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें । माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य मनोज मंजिल जी, जरा स्थान ग्रहण कीजिये ।

माननीय सदस्य ।

श्री राजू कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं साहेबगंज विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ । अभी एक सूचना है कि साहेबगंज विधान सभा क्षेत्र में माधोपुर हजारी एक गाँव है, उस माधोपुर हजारी गाँव में बिहार सरकार के अनेक पेड़, दसों पेड़ काटकर गिराये जा चुके हैं । माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्री अभी यहाँ पर हों या उनके कोई पदाधिकारी हों तो पता करें । मैंने अभी रेन्जर को फोन किया और रेन्जर जिस अंदाज में बात किया, आप हमलोगों के संरक्षक हैं । मैंने कहा हुजूर प्रणाम, मैं साहेबगंज विधायक बोल रहा हूँ, वह बोला कि कटना है तो कटने दीजिये । वहाँ पर पेड़ अभी कट रहे हैं, वहाँ पर आर0जे0डी0 का बोर्ड लगाकर, राष्ट्रीय जनता

दल का बोर्ड लगाकर गाड़ी लगा हुआ है और वहाँ पर दसों पेड़ काटे जा रहे हैं । अभी-अभी की बात है ।

अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कीजिये । आपने सूचना दिया ।

माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल । आपका समय 6 मिनट है ।

(व्यवधान)

शांति बनाये रखें ।

श्री मनोज मंजिल : माननीय अध्यक्ष महोदय, आज एस0सी0/एस0टी0 पर भी वाद-विवाद है । मैं धूमिल के शब्दों से शुरू करता हूँ -

''लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो,
उस घोड़े से पूछो जिसके मुँह में लगाम है ।''

महोदय, अभी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण का रिपोर्ट मैं पढ़ रहा था । आज भी एस0सी0/एस0टी0 के 49.8 प्रतिशत लड़के-लड़कियाँ हाई स्कूल की शिक्षा पूरी नहीं कर पाते, बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं ।

(इस अवसर पर माननीय उपाध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

अगर आदिवासी की बात करें तो 31.6 प्रतिशत बच्चे-बच्चियाँ हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाते । टीचर की बहाली होने वाली है, अब बी0एड0 का फीस डेढ़ से दो लाख रूपया कर दिया गया । अब एस0सी0/एस0टी0 के बच्चे इतना फीस कहाँ से अदा कर पायेंगे तो मास्टर नहीं बन पायेंगे एस0सी0/एस0टी0 के बच्चे-बच्चियाँ । कैग का रिपोर्ट हमने देखा कि एस0सी0/एस0टी0 छात्रवृत्ति फंड के 8800 करोड़ रूपये सड़क बनाने में, सरकारी भवन बनाने में, तटबंध में, बिजली के क्षेत्र में खर्च कर दिया गया । यह असंवैधानिक है, यह हकमारी है । सरकार को यह अधिकार नहीं है ।

लोहिया जी ने एक बात कही थी बहुत महत्वपूर्ण -

''चपरासी हो या राष्ट्रपति की संतान,
सबको शिक्षा एक समान ।''

महोदय, हम कहना चाहते हैं कि आज भी, हमारे संविधान का प्रिएम्बल भी कहता है कि अवसरों में समानता हो और इसलिए बिहार में हमारी सरकार है, समान स्कूल प्रणाली की स्थापना के लिए समान स्कूल प्रणाली विधेयक हाउस में लाया जाय । अमीर हो, गरीब हो, जाति, वर्ग, लिंग, अमीरी, गरीबी, धर्म के आधार पर बिना भेदभाव के सभी बच्चों को शिक्षा पाने का अधिकार है, समानता और सामाजिक न्याय का सिद्धांत है ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति-शांति । बोलने दीजिए ।

श्री मनोज मंजिल : महोदय, गरीब बच्चों के मेरिट पर बात होती है कि आरक्षण पर ये लोग आये हैं विश्वविद्यालय में नौकरी में, हम कहना चाहते हैं कि प्रतिभाएँ जातियों के गर्भों में नहीं पला करती, एक समान शिक्षा व्यवस्था लागू कराओ, पता चल जायेगा कि किसकी माएँ तेज बेटा पैदा करती हैं, पता चल जायेगा ।

इसलिये अभी आज विधान सभा में बहस हो रही थी, आप जानते हैं, सरकारी रिपोर्ट है, बिहार में नवयुवतियाँ, बच्चे कुपोषण की चपेट में हैं, एनीमिया के शिकार हैं, अगर सामान्य वर्ग के, पिछड़ा वर्ग के जो पुलिस की बहाली में, पुलिस में, दारोगा में हाईट है 165 सेंटीमीटर तो एस0सी0/एस0टी0 के लड़कों के लिए 160 सेंटीमीटर हो सकता है तो फिर एस0सी0/एस0टी0 लड़कियों के लिए और 5 सेंटीमीटर घटा दिया जाय, हमारी बहनें लम्बी नहीं हो पाती हैं, माँ के पेट में कुपोषण का शिकार हो जाती हैं, वे भी सिपाही और दारोगा में बहाल हो जातीं । मैं समझता हूँ कि इस सवाल के पक्ष में पूरा हाउस होगा । मित्रों, जब से इस विचारधारा के लोग देश की सत्ता में आये हैं तब से शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव, उत्पीड़न बढ़ा है । रोहित बेमुला को भा0ज0पा0 के छात्र नेता सुशील कुमार ने, भा0ज0पा0 के सांसदों ने उत्पीड़न किया, वे लेटर लिखते हैं कि इस देश में हमारी कीमत एक जाति तक है, एक वोट तक है, इस देश में हमारी मस्तिष्क और इस मुल्क में हमारी जो कुर्बानी है इसकी पहचान नहीं हैं, हमारा जन्म एक दुर्घटना है और वे शहीद हो जाते हैं । ये इन्द्र कुमार तीसरी क्लास का बच्चा उच्च जाति के टीचर के मटके से पानी पीता है तो उसको अपनी जान गँवानी पड़ती है । ये दर्शन सोलंकी को आत्महत्या करना पड़ता है । पाल तन्वी को जातिगत भेदभाव से अपनी जान गँवानी पड़ती है । ये लोग आज दलितों को कहते हैं कि हिन्दू हो । साम्प्रदायिक राजनीति में ले जाना चाहते हैं । अरे भाई, कब से दलित हिन्दू हो गये, शुद्र कब थे । आपने तो उनको मानवीय अधिकार से, ज्ञान से, एक मनुष्य होने का स्वाभिमान ही पैदा नहीं होने दिया । आप कहते हैं कि हिन्दू हो । अरे भाई, आपको हमारी मूंछें नहीं बर्दाश्त होती, हमें घोड़ी पर चढ़ना आपको मंजूर नहीं और हाथरस में हमारी बहन को सामूहिक बलात्कार करके रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ी जाती है, गर्दन मरोड़ दिया गया, जीभ काट लिया गया और इस देश में बलात्कार के पक्ष में कोई डिफेंड करने वाले लोग हैं ।

...क्रमशः...

टर्न-20/आजाद/20.03.2023

..... क्रमशः .....

श्री मनोज मंजिल : ये कौन लोग हैं भाई, इस देश के बड़े नेता जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हुए हैं । वे कहते हैं कि कब्र से निकाल करके बलात्कार करो । कोई कहता है, ये लोग कहते हैं कि कब्र से निकाल कर बलात्कार करो । कोई कहता है कि वोटिंग राईट छीन लो, कोई नरसंहार करने का आह्वान करता है । दलितों को हिन्दू बनाते चल रहे हैं ......

उपाध्यक्ष : अब कनक्लूड कीजिए ।

श्री मनोज मंजिल : यह समाज सामंतशाही से लड़ा है, यह समाज मनुवादी, ब्रह्मणवादी से लड़कर आगे बढ़े हैं और यह जो हमारी लड़ाई जो सामंती, फांसीवादी, सम्प्रदायिक निजाम है, इससे भी लड़ेंगी और यह लड़ाई भगत सिंह, अम्बेदकर के रास्ते हिन्दुस्तान के लाल किले तक पहुँचेगी, इसलिए हमलोग आये हैं । आप बेच डाले, रेल, एल0आई0सी, बैंक का निजीकरण कहां बचा सरकारी नौकरी ? इसलिए हम कहते हैं कि दलितों को आप प्राइवेट सेक्टर में आरक्षण दो, जुडिशियरी में आरक्षण दो । रेल बेच दिया, भेल, सेल, खान, खजाना सब बेच दिया, यह देश तुम्हारी जागिर है, तुम देश के मालिक हो ? देश का मालिक तुम नहीं हो, हमारे पुरखों ने इस देश के मजदूर, किसानों ने अपने खून पसीनों से इस मुल्क को आजाद कराया है । इस मुल्क को संजाया, बनाया है । इस देश का प्रधानमंत्री कोई हो सकता है लेकिन इस देश का मालिक आप नहीं, इस देश का मालिक हम हैं, इस देश की लाखों-करोड़ जनता है और इसलिए हम कहने के लिए आये हैं ।

मित्रों कि आज बिहार में जो जमीन का सवाल है, लाखों-लाख एकड़ जमीन बड़े भू-दारियों के कब्जे में है । हम कहना चाहते हैं कि हमारी यहां पर महागठबंधन की सरकार है, हम यह कहना चाहते हैं माननीय मंत्री जी से, सरकार से कि आप आगे बढ़िए, गैर सरकारी, गैर-मजरूआ जमीन को देने के लिए आप आगे बढ़िए, महागठबंधन की ताकत आपके साथ है और लाल झंडे की ताकत सबसे अग्रिम मोर्चे पर है । बड़े भू-दारियों के कब्जे से जमीन को मुक्त कराईए, भूमिहीन गरीबों को, दलितों को जमीन वितरण करने का काम करिए । इ0डब्लू0एस0 लाते हैं, संविधान के मूल भावना आरक्षण के मूल प्रावधान का उल्लंघन करके लाते हैं । इकोनोमिकली वीकर सेक्शन को हमने 10 प्रतिशत आरक्षण दिया । आरक्षण किसलिए मिला था । जो सदियों से सताये गये लोगों को ऐतिहासिक रूप से सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से .....

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री मनोज मंजिल : शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों को सामाजिक समानता के लिए आरक्षण लाया गया था लेकिन आपने इ0डब्लू0एस0 ला दिया । यह जो आपका 10 प्रतिशत आरक्षण है, इस 10 प्रतिशत के माध्यम से एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 के 50 प्रतिशत आरक्षण को आप खत्म करना चाहते हैं ? हम सरकार से मांग करते हैं, बिहार में हमारी सरकार है, एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0 का जो रिजर्वेशन का दायरा है, उसके दायरों को बढ़ाईए और महागठबंधन नई मंजिल में जायेगी और.....

उपाध्यक्ष : अब आप समाप्त करें ।

श्री मनोज मंजिल : इसलिए इन्हीं चन्द बातों को कहते हुए मैं अपने क्षेत्र की जनता को धन्यवाद देते हुए अपने माननीय नेता महबूब आलम, सत्यदेव राम, अरूण जी को धन्यवाद देते हुए, आपको भी धन्यवाद देते हुए इन्कलाब जिन्दाबाद, महागठबंधन जिन्दाबाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य डॉ0 अनिल कुमार, आपका समय 3 मिनट है ।

डॉ0 अनिल कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट और समय बढ़ाया जाय, तीन मिनट में क्या बोल पायेंगे ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांग पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार दिन प्रतिदिन एक से एक नए आयाम स्थापित कर रही है । विकास की ऐसी पटकथा इन्होंने लिखी है इन्होंने कि आज सम्पूर्ण देश में उसकी चर्चा होती है । कोई ऐसा सेक्टर नहीं है जिसमें देखने लायक, महसूस होने लायक काम नहीं हुआ हो । कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो ऐसा लगता है अकल्पनीय काम हुआ है । पथ निर्माण विभाग ने जिस तरह से बिहार के हर कोणे को सुगमता के साथ जोड़ने का काम किया है, बिहार हर कोने से राजधानी पहुँचने के लिए मात्र पाँच घंटे के अन्दर पहुँचने की व्यवस्था की है । सड़कों का ऐसा जाल बिछाया है कि लोग देखकर के हैरानी हो जाते हैं । केवल पटना ही नहीं अपितु राज्य के हर बड़े शहरों में आर0ओ0बी0 एवं फ्लाईओवरों का जाल बिछाकर लोगों को जाम से मुक्ति दिलाने का काम किया । महात्मा गाँधी सेतु के पूर्वी लेन को चालू करके उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार के आवागमन को फिर से सुगम किया गया । मुंगेर रेल सह सड़क परियोजना हो या जे0पी0गंगा पथ परियोजना के दीघा से पी0एम0सी0एच0 का लोकर्पण विकास की पटकथा में एक मील का पत्थर है ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पथ निर्माण विभाग पूरी तरह से योजनाओं को जमीन पर उतारने का काम कर रहा है और

इसके लिए पूरा विभाग माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी धन्यवाद के पात्र हैं ।

महोदय, इसी क्रम में मैं अपने विधान सभा टेकारी के जो स्टेट हाईवे-69 पर स्थित है, जो सात निश्चय पार्ट-2 के तहत टेकारी बाईपास चयनित है, इसमें सरकार से आग्रह है कि शीघ्रता से निविदा निकाल करके अगले वित्तीय वर्ष में इस बाईपास का निर्माण कराने की कृपा करें, जिससे वहां के लोगों को जाम से मुक्ति मिले । वहां परैया ब्लॉक से टेकारी अनुमंडल आने के लिए सिंगल रोड है, इसलिए आग्रह है कि 15 कि0मी0 लम्बा रोड को पथ निर्माण विभाग लेकर इसको चौड़ीकरण करा दे । महोदय, इसी क्रम में गया जो हमारा बिहार के लिए पर्यटन के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बोधगया का ख्याति पूरे विश्व में है । देश दुनिया के पर्यटक वहां सालों भर आते हैं । गया में पितृ पक्ष के दौरान 5 लाख लोग प्रतिदिन आते हैं । गया शहर जाम प्रतिदिन रहने से वहां के लोग तबाह रहते हैं । इसलिए आपके माध्यम से ......

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

डॉ0 अनिल कुमार : आपके माध्यम से माननीय पथ निर्माण मंत्री जी को ध्यान आकृष्ट कराते हुए कहना चाहता हूँ कि पूरे सूबे में बहुत काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है । उसी क्रम में गया में अगर तीन फ्लाईओवरों का निर्माण करा दिया जाय तो लोगों को बहुत ही राहत होगी और देश-दुनिया में एक अच्छा मैसेज जायेगा । जैसे नई गोदाम से जी0बी0 रोड, राय काशीनाथ मोड़, गोबलबिगहा होते हुए सिकरिया मोड़ तक, दूसरा- रेल ओवरब्रीज होते हुए डेल्हा बाजार से डेल्हा थाना तक, तीसरा- जैन धर्मशाला होते हुए डेल्हा कण्डीनवादा तक । इन तीनों फ्लाईओवरों को बना देने से गया को जाम से मुक्ति मिल जायेगी ......

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप समाप्त कीजिए ।

डॉ0 अनिल कुमार : एक मिनट महोदय । अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग में बिहार में बहुत अच्छा काम हो रहा है । हम देखेंगे तो अनुसूचित जाति/जनजाति विभाग को मेरा कुछ सुझाव है, 2012-13 में अनुसूचितजाति-जनजाति विभाग का बजट मात्र 40 करोड़ था, 2023-24 में इसे बढ़ाकर 180 करोड़ किया गया । इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद । साथ ही सरकार से आग्रह है कि जनसंख्या बढ़ोतरी होने के कारण एस0सी0/एस0टी0 विभाग का बजट 500 करोड़ करने का आग्रह करता हूँ । दूसरे राज्यों में पढ़ने वाले एस0सी0/एस0टी0 विद्यार्थियों के साथ अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को 85हजार

रू0 से लेकर एक लाख रू0 तक, 25 हजार रू0 की छात्रवृत्ति सरकार द्वारा दी जाती थी, जिसे बंद कर दिया गया है ......

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य अब आप समाप्त कीजिए । माननीय सदस्य श्री अजय कुमार, आपका दो मिनट समय है ।

श्री अजय कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पथ निर्माण विभाग के अनुदान मांग के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हूँ । पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो सड़कें बनी है बिहार के अन्दर, वह हम कह सकते हैं कि एक तरीके से बिहार के लिए एक लाईफ लाईन का काम कर रहा है । पथ निर्माण विभाग के और जो कार्यक्रम आगे होना है, उसको भी मैं पढ़ा हूँ लेकिन मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ पथ निर्माण विभाग को और वह सुझाव मैं यह देना चाहता हूँ कि पथ निर्माण विभाग कभी-कभी ग्रामीण कार्य विभाग के सड़कों को अधिग्रहण करती है और उसको अधिग्रहण करके उसको खुद बनाती है । उसके लिए कोई नियम होना चाहिए कि आप कितनी लम्बी सड़कों को और कितनी उपयोगी सड़कों को आप पथ निर्माण विभाग में आप टेकओवर करते हैं । मैं समझता हूँ कि जो सड़कें कम से कम दो प्रखंडों को जोड़े या कम से कम 10 कि0मी0 से जो ज्यादा लम्बी सड़क हो, उसको पथ निर्माण विभाग को टेकओवर करना चाहिए । पथ निर्माण विभाग के द्वारा जो सड़कें बनती है, वह काफी मजबूत सड़कें बनती है । लेकिन उन सड़कों के साथ-साथ मेरा आपसे अनुरोध है, सरकार से अनुरोध है कि उसके बगल में जो फ्लैंक नहीं बनता है, उससे जो कठिनाईयां होती है, उसपर ध्यान देना चाहिए और जब सड़कें ऊँची बनती है तो जल-जमाव की जो समस्या बनती है तो उसके साथ-साथ आपको उसमें ड्रैनेज सिस्टम को भी उसके साथ जोड़ना चाहिए । खासकर के मैं विभूतिपुर विधान सभा क्षेत्र के एस0एच0-55 का जो पारा के सामने सड़कें बनी है, वह डेढ़ फीट ऊँची सड़क बनी है और वहां पर ड्रैनेज की बहुत बड़ी समस्या है, जल-जमाव लग रहा है, उसपर मैं ध्यान आकृष्ट करते हुए एस0एच0-88 जो विभूतिपुर के ही दरौनिया से सिंघिया तक का जो सवाल है, वहां पर भी ड्रैनेज का सवाल है, पथ निर्माण विभाग के सड़क के बगल में उसकी जरूरत है । सिंघिया घाट स्टेशन में ही एस0एच0-88 में ही अगर ओवरब्रीज नहीं बनाया जायेगा तो आपका इतनी चौड़ी सड़कों का बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा, इसलिए ओवरब्रीज का भी वहां निर्माण होना जरूरी है ।

...... क्रमशः .....

टर्न-21/शंभु/20.03.23

श्री अजय कुमार : क्रमशः...पंचायती राज विभाग से सिर्फ मेरा एक अपील है कि आप जिस तरह से फंड वहां डेवलपमेंट के लिए देते हैं वहां उसके साथ इन चीजों को जोड़िये कि जिला परिषद् में जो खर्च करने के लिए आप योजना चलाने के लिए जो देते हैं वह हर जिला परिषद् सदस्य कोई हो उस योजना को चलाने में उसकी भागीदारी सुनिश्चित हो ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री अजय कुमार : एक सेकेंड सर, उसी तरीके से आप प्रखंड समिति में भी करें । कला संस्कृति विभाग से हम अपील करना चाहते हैं कि मैंने देखा कि आपने इसमें कई संग्रहालय का निर्माण किया । क्या मैं इस सदन में इस बात को रख सकता हूँ कि जन नायक कर्पूरी ठाकुर जिनकी भूमिका न सिर्फ इस सदन के अंदर बल्कि बिहार के निर्माण में रहा । उनकी आवाज, उनके काम बिहार के लाखों लाख, करोड़ों करोड़ पीड़ित जनता के लिए............

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री अजय कुमार : एक सेकेंड सर, यह बहुत महत्वपूर्ण है । मैं यह मांग करता हूँ कि क्या सरकार उनके लिए समस्तीपुर जिला में उनके नाम पर कोई संग्रहालय बनाने का इरादा रखती है कि नहीं । मैं प्रस्ताव करता हूँ कि जरूर आप इसको जोड़ने का काम करेंगे चूंकि यह करोड़ो करोड़ जनता की उम्मीद से जुड़ा हुआ सवाल है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ सरकार का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : अभी समय निर्धारित हैं न, बाकी समय मिलेगा तो उसपर कुछ बोलियेगा, समय का अभाव है । माननीय सदस्य श्री राम रतन सिंह जी, प्रारंभ करें ।

श्री राम रतन सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट का वक्त हमें दिया है आपने इसके लिए बहुत-बहुत आभार । पहली बात मैं कहना चाहता हूँ बिहार सरकार के द्वारा खासकर के पथ निर्माण मंत्री के द्वारा बिहार में जो सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है वह काबिले तारीफ है और उसमें जहां-जहां जो त्रुटि है केवल उसकी चर्चा मैं करना चाहूंगा । मैं कहना चाहूंगा कि इन त्रुटियों को अगर दूर कर दिया जाय तो निश्चित तौर पर सड़कें बिहार में मैं समझता हूँ कि दूसरे तमाम प्रदेशों से बिहार सड़कों के मामले में आगे देखने को मिलेगा । इसीलिए मेरी समझ है कि खासकर के पथ निर्माण मंत्री जी से मैं कहना चाहूंगा कि अभी दो सड़कें बन रही है- राष्ट्रीय उच्च पथ को छोड़ दिया जाय तो पथ निर्माण विभाग और ग्रामीण विकास विभाग और दोनों सड़कें करोड़ों करोड़ रूपये की लागत से बन रहा है । मैं कहना

चाहता हूँ कि इन दोनों सड़कों के माध्यम से बेगुसराय का मटिहानी विधान सभा और बेगुसराय का तेघड़ा विधान सभा दोनों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन कठिनाई क्या है, क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ । मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि सड़कों पर वर्षों से गुप्ता लखमिनियां बांध पर सैंकड़ों की संख्या में बाढ़ कटाव प्रभावित होकर लोग सड़कों पर बसे हुए हैं, बांधों पर बसे हुए हैं जिसकी वजह से वर्षों से वह सड़क निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक आधा अधूरा है, पूरा नहीं हो सका है । इसलिए इस संबंध में बिहार सरकार का ध्यान हम खींचना चाहते हैं कि जो लोग बांध पर बसे हुए हैं उनको शीघ्र बसाने का उनके लिए जमीन अर्जित करके उनको बसाने की व्यवस्था की जाय । तभी सड़कों का जाल जिसकी चर्चा मैंने की जो बिहार में अन्य राज्यों के मुकाबले बिहार आगे बढ़ रहा है सड़कों के मुकाबले में तो निश्चित तौर पर उसमें चार चॉंद लगेगा । इन्हीं चन्द बातों को कहेंगे हम ज्यादा कुछ कहने के लिए तैयार भी नहीं हैं । हम यही कहना चाहते हैं आपसे कि आप जिन बातों को इस सदन के माध्यम से रखने का प्रयास कर रहे हैं और खासकर के सड़कें जो बनती है उसपर गरीब लोग भी चलते हैं, अमीर भी चलते हैं और गांव के अंदर सही मायने में सात निश्चय-1, सात निश्चय-2 जो गांव में, टोले में, मोहल्ले में जहां आज तक सड़कें नहीं बनी थी, जहां आज तक लोग पगडंडी पर किसी तरह से चलते थे । आज लोग सड़कों पर चलकर अपने मंजिल तक पहुंचते हैं ।

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री राम रतन सिंह : आपका आदेश हो गया । मैं बैठ रहा हूँ लेकिन आपको फिर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने हमें समय दिया तो निश्चित तौर पर आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

सुश्री श्रेयसी सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सर्वप्रथम मैं जमुई की जनता का तहेदिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे चुनकर इस लोकतंत्र के मंदिर में भेजने का काम किया है । साथ ही साथ मैं आसन को और आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया है । अपने नेता प्रतिपक्ष और भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करती हूँ । उपाध्यक्ष महोदय, ऐसा प्रतीत होता है कि बिहार में जो विकास की लहर बह रही थी वह अचानक से रूक गयी है, ऐसा लगता है कि लकवा मार गया है । आज राज्य सरकार की उपलब्धि का अगर हम आकलन करेंगे तो पता चलता है कि केन्द्र सरकार से बनाये जा रहे नेशनल हाइवे सिर्फ वही रह गया है राज्य सरकार के पास दिखाने के लिए । मैं माननीय मंत्री पथ निर्माण, भारत सरकार का तहेदिल से

शुक्रिया अदा करती हूँ कि बिहार में उन्होंने ये कार्य करने का काम किया है और साथ ही यह सुझाव देती हूँ कि हमारे जो माननीय मंत्री राज्य सरकार हैं वे उन्हें अपना प्रेरणास्रोत मानकर स्टेट हाइवे और मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड का भी काम इसी तरह से आगे बढ़ायें । उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों और माननीय संजय भैया और प्रमोद जी ने अपनी बात बहुत ही मजबूती से रखा । उस बात की मैं ज्यादा विवरण नहीं करूँगी लेकिन मैं यह जरूर बताउंगी कि बिहार में इस वक्त 3500 कि0मी0 लंबी नेशनल हाइवे या तो बन रहे हैं या उनके चौड़ीकरण का काम चल रहा है । साथ ही साथ केन्द्र सरकार के भारत माला परियोजना के अन्तर्गत बिहार में 650 कि0मी0 लंबे राजमार्ग निर्माण का कार्य जारी है । पूर्वी और पश्चिमी बिहार को जोड़ने के लिए पांच जगह पर फोरलेनिंग का काम चल रहा है, उत्तर और दक्षिणी बिहार को जोड़ने के लिए छः जगह पर फोरलेनिंग की परियोजनाएं चल रही है । साथ ही साथ महोदय आपको याद दिला दें कि प्रधानमंत्री के पैकेज के अन्तर्गत 54 हजार करोड़ और भारत माला परियोजना के तहत 62 करोड़ यानी टोटल 1 लाख 16 हजार करोड़ के आसपास की राशि दी गयी है जिससे विभिन्न पथ पर कार्य चल रहा है । उपाध्यक्ष महोदय, सवाल बहुत ही सरल है कि इस आंकड़े में जो आंकड़ा आपने किताबों में दर्शाया है, अपने बजट में दर्शाया है । उसमें राज्य सरकार के पैसे और भूमिका कहां आती है सवाल सिर्फ इतना सा है । महोदय, साथ ही हाऊस के सभी सदस्यों को यह बताना चाहूंगी कि नाबार्ड में हर वित्तीय वर्ष की तरह जून के महीने में 2 हजार करोड़ की योजनाएं लिखी गयी थी जिनकी स्वीकृति जुलाई तक हो जानी थी, लेकिन आज तक जो 2 हजार करोड़ रूपये रेखांकित थे नाबार्ड में आर0सी0डी0 विभाग के लिए उसकी स्वीकृति नहीं मिली है । वह टेंडर प्रक्रिया में नहीं गया है, यह पैसा उसी तरह से व्यर्थ जा रहा है । महोदय, माननीय मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री सभी लोग जानते हैं कि हमारे साथ स्कूल में भी पढ़े थे और खेल में भी रूचि रखते हैं । उपाध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है कि 8 अगस्त, 2022 को इन्होंने शपथ ग्रहण किया था और आज 7-8 महीना होने जा रहा है लेकिन माननीय मंत्री के पास इतना भी समय नहीं मिला कि माननीय नीतिन गडकरी जी से जाकर मिल लें और राज्य या केन्द्र सरकार की जो टसल चल रही है या जो बात खुलकर नहीं हो पा रही है उसमें समन्वय बैठाने का काम करें जिससे बिहार के विकास का कार्य आगे बढ़ सके । साथियों इन्हीं शब्दों के साथ मैं बताना चाहूंगी कि पथ निर्माण की अगर हम बात करें तो नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे की जो कुल लंबाई होती है उसका अनुपात यानी रेशियो 1:1 की होनी चाहिए । हालांकि नेशनल हाइवे की कुल लंबाई स्टेट हाइवे से अधिक हो

सकती है, लेकिन उदारता के साथ भी हम बिहार की बात करें और अनुपात क्रमशः बतायें तो ये 3:2 से भी अधिक नहीं होगा । इसका मतलब ये है कि नेशनल हाइवे की कुल लंबाई लगभग 5970 कि0मी0 है ।

(क्रमशः)

टर्न-22/पुलकित/20.03.2023

सुश्री श्रेयसी सिंह (क्रमशः) : जबकि राज्य के स्टेट हाईवे की लम्बाई मात्र 3,630 कि0मी0 के आसपास है, साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि जो हमारे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड होती है उसकी चौड़ाई जो इन्टरमीडियेट लेन होती है वह लगभग 5.5 मीटर की होनी चाहिए लेकिन बिहार में एक तिहाई ऐसी डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड है जिसकी सिंगल लेन सिर्फ और सिर्फ 3.75 मीटर की है यानी ग्रामीण सड़क के बराबर है, इन्हें हमें चौड़ीकरण करने का कार्य अवश्य करना चाहिए और जल्दी करना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ जो आज सबसे बड़ी दिक्कत बिहार में मुझे दिखाई देती है वह यह है कि हम रोड बना देते हैं, पुल बना देते हैं लेकिन एप्रोच रोड नहीं बन पाती है । मैं यह जानना चाहूंगी कि ऐसे कितने पुल और सड़क बनी हैं जिनका एप्रोच रोड नहीं होने के कारण वह ऑपरेशनल नहीं हो पाते हैं । क्या माननीय मंत्री यह बता सकते हैं कि आज ऐसी कितनी रोड है जो सिर्फ एप्रोच रोड न होने के कारण ऑपरेशनल नहीं है । उपाध्यक्ष महोदय, बजट का सत्र चल रहा है, हमारे राज्य की तरह अन्य राज्यों में भी इसी बजट के ऊपर चर्चा हो रही है, पार्लियामेंट में भी चर्चा हो रही है । अगर हम अपने साथी प्रदेशों की बात करें, राज्यों की बात करें जहां पर भारतीय जनता पार्टी या एन0डी0ए0 की सरकार है तो यहां पर बैठें कई साथियों को जरा मिर्ची सी लग जाती है, इसीलिए हम अपनी तुलना वैसे राज्यों के साथ करेंगे जहां पर यू0पी0ए0 की सरकार है, जैसे कि राजस्थान की बात करें तो वहां का पथ निर्माण का बजट 6,500 करोड़ के आसपास है जबकि बिहार में उससे भी कम बजट है, साथ ही साथ अगर झारखंड की बात करें तो 6,300 करोड़ का बजट है, जो कि बिहार से ज्यादा है । छोटे राज्य जैसे छत्तीसगढ़ की बात करें तो 3,500 करोड़ का बजट है जबकि बिहार का बजट और बिहार में जितने लोग हैं, Bihar is the third Largest populated State in this country. उपाध्यक्ष महोदय, क्या यहां का बजट बाकी इन राज्यों से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर हम अपने उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर पथ निर्माण का बजट 30,000 करोड़ है और महाराष्ट्र में 14,225 करोड़ का ये बजट पेश किया गया है । साथ ही साथ साथियों हम आपको यह भी बता दें अभी हमने आप लोगों को नाबार्ड के बारे में जानकारी दी । अगर हम ए0डी0बी0 (एशियन

डेवलपमेंट बैंक) की बात करते हैं तो हर साल नई योजनाएं वहां पर लिखाई जाती थी, हर वित्तीय वर्ष में ये योजनाएं लिखी जाती थी लेकिन सरकार कह लीजिये, माननीय मंत्री कह लीजिये या माननीय मंत्रिगण कह लीजिए, इस वित्तीय वर्ष ए0डी0बी0 में एक भी योजना नहीं लिखी गयी है, क्या यह सरकार की सुस्ती है, क्या यह सरकार की लापरवाही है, इसका जवाब भी हम जरूर सुनना चाहेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, पूरे बजट की किताब में केन्द्र की योजनाओं की चर्चा की गयी है, इस बात को हमारे भाई माननीय सदस्य श्री संजय जी ने बड़ी मजबूती से कहा है कि इस किताब में ये रिपोर्ट आप ही को आईना दिखाने का काम कर रही है । ये जितनी भी योजनाएं लिखी गयी है ये पूरी की पूरी तरह से केन्द्र सरकार की योजनाएं है और पूर्व में चल रही जितनी भी योजनाएं थी वे माननीय मंत्री नितीन नवीन जी के कर-कमलों द्वारा की गयी थी ।

उपाध्यक्ष महोदय, हम थोड़ा सा समय और मांगेगे, वह इस कारण क्योंकि आज पथ निर्माण के साथ-साथ कला, संस्कृति एवं युवा विभाग पर भी बजट है । महोदय, एक अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाज और एक सदस्य होने के साथ आप हमारा समय थोड़ा सा और बढ़ा दीजिये, मात्र दो मिनट का समय और हम लेंगे । उपाध्यक्ष महोदय, वर्ष 2021 की बात थी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी उस समय नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, हम सत्ता पक्ष में पीछे बैठे थे, उन्होंने उस वक्त हमसे पूछा कि बिहार में खेल की और खेल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, उसका क्या स्टेटस है, उसके बारे में आप क्या सोचती है ? उस समय सत्ता पक्ष में रहने के कारण उस बात का जवाब हम मजबूती से नहीं दे पाये थे लेकिन आज जरूर कहना चाहेंगे, उपाध्यक्ष महोदय, उसी दिन स्पोर्ट विश्वविद्यालय का और इन्टनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का स्पोर्ट विधेयक पास हुआ था । उपाध्यक्ष महोदय, यह पूरा विश्वविद्यालय 740 करोड़ 90 एकड़ में बनने जा रहा था, उस दिन उम्मीद की एक किरण सभी खिलाड़ियों के लिए दिखने लगी थी कि शायद बिहार के बच्चे भी बिहार में स्पोर्ट्स कर पायेंगे, आगे बढ़ पायेंगे लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, आज तक जो शिलान्यास हुआ, उसके बाद एक भी ईंट नहीं जोड़ी गयी है, यह काम कब पूरा होगा, क्या यह बिहार का सपना सिर्फ अधूरा रह जायेगा, इतना ही हम जानना चाहते हैं । महोदय, पूरे 15 साल से हमारा कैरियर रहा है, हम बिहार के लिए निशानेबाजी करते हैं, भारत के लिए निशानेबाजी करते हैं लेकिन आजतक बिहार की सरकार ने एक भी शॉटगन सूटिंग रेंज का निर्माण कार्य नहीं किया । बिहार की ऐसी बेटी आज विधान सभा में खड़े होकर बोल रही है, जिसको राष्ट्रपति ने 2018 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया है । एक भी

शॉटगन सूटिंग रेंज नहीं होने का कारण क्या है, ये माननीय खेल मंत्री, माननीय उप मुख्यमंत्री जो खुद खेल में इतना रूचि रखते हैं, इसका जवाब हमें जरूर दें । उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमें इतना समय दिया, इस समय के साथ एक लाईन कह दूं क्योंकि माननीय सदस्य श्री शकील अहमद जी कुछ नमक की बात कर रहे थे तो मैं भी उनको बोलना चाहूंगी -

''न बोला वंदे मातरम्, सरे आम हो गये,
खाया वतन का नमक और आज XXX हो गये ।''

उपाध्यक्ष : अब अपना भाषण समाप्त कीजिये ।

सुश्री श्रेयसी सिंह : इन्हीं शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद ।

माननीय सदस्य श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज पथ निर्माण विभाग के बजट की मांग के समर्थन में और कटौती प्रस्ताव के विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे एक साथी ने एक शेर लिखा है, इससे मैं अपनी शुरूआत करना चाहता हूं, हमारे एक साथी ने हमारे नेता के लिए लिखा है -

''निकला वो कर्त्तव्य के पथ पर, अपनी माटी के कर्ज तले,
समझता हूँ कि आज हमारे इशारों पर ठोकर है खड़ी
रूकेगा न वो, झुकेगा न कभी, इन फांसीवादी ताकतों से,
इस समाजवाद की आंखों में, आंधी में, न जाने कितने तानाशाह फनाह हुए।''

इन्हीं बातों की शुरूआत के साथ माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जिस तरह से बिहार लगातार विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और जब उसको और ऊंचा आयाम पर ले जाना है और एक कीर्तिमान स्थापित करना है, वैसी परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा कि कुछ महत्वपूर्ण विभागों जिससे आम जनता का बहुत ज्यादा सरोकार है, किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया जाना चाहिए, जिससे वे लम्बे समय के कार्यकाल से असंतुष्ट थे, चाहे वह स्वास्थ्य व्यवस्था का मामला हो, जिसकी शिकायतें कोरोना के समय बहुत ज्यादा देखने को मिल गयी, चाहे नगरों की बदहाल स्थिति हो जो लगातार पन्द्रह वर्षों में भी कई शिकायतें उनको मिलती रही, कानों तक आती रही। चाहे पथ निर्माण, जिसको 13 करोड़ जनता को यातायात सुलभ कराना, पुल-पुलिया उपलब्ध कराना, वृहद पुल बनाना जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी पथ निर्माण विभाग की थी, उन्होंने देखा कि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जब 2015 में इस विभाग

की जिम्मेदारी को संभाले थे तो किस बेहतर ढंग से उन्होंने काम किया, अपने चंद समय के कार्यकाल में लगातार विभाग के केन्द्रीय मंत्री से बार-बार मिलना, नितिन गडकरी जी से मिलना, रेल मंत्री जी से आर0ओ0बी0 के संबंध में मिलना और बिहार में जो उन्हें चंद समय मिला था उसमें एक कीर्तिमान स्थापित किया, जिसको देखते हुए आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तमाम महत्वपूर्ण जिम्मेदारी इनको दी ताकि बिहार जो कई क्षेत्रों में तेज गति से आगे नहीं बढ़ रहा है, वह एक मजबूत कंधा, मजबूत विश्वास आदरणीय तेजस्वी यादव पर दिया है, उन्हें पूरा विश्वास है कि बिहार जिस गति से बढ़ना चाहिए, जो कोई भी गाड़ी अगर तेज गति से बढ़ना चाहती है तो उसके दोनों पहिया कहिये या बड़ी गाड़ी है तो उसके चारों पहियों का बेहतर ढंग से काम करना आवश्यक है लेकिन नीतीश कुमार जी जिस गति से आगे बढ़ रहे थे, उनकी गाड़ी का कोई एक पहिया ठीक तरह से काम नहीं कर पा रहा था और जिसकी वजह से बिहार उस मुकाम तक नहीं पहुंच सका । इसलिए जो पीछे रह गया, उसको सही लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए तेजस्वी यादव जी के मजबूत कंधों पर विश्वास किया और इन्हें बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देने का काम किया है।

महोदय, हम विश्वास दिलाते हैं कि जिस तरह से उन्होंने पिछले 15, 17 और 18 महीनों में काम किया था, उससे तेज गति से, तमाम विभागों में दो-चार महीनों में ही हमने तमाम विभागों में एक क्रांतिकारी बदलाव होते हुए देखा है । आप पथ निर्माण विभाग में ही देखेंगे कि लगातार जो बिहार में तमाम योजनाएं चल रही थी, चाहे वृहद जिला पथ का मामला हो जिसमें 2000 किलोमीटर सड़क का काम बहुत तेज गति से हो रहा है और 272 किलोमीटर मजबूतीकरण का कार्य भी बहुत तेज गति से हो रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न-23/अभिनीत/20.03.2023

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन (क्रमशः) : महोदय, सात निश्चय प्रोग्राम के तहत प्रत्येक जिले में बाईपास बनाने का संकल्प लिया गया है ताकि जिलों में जो जाम की स्थिति पैदा होती है, वह जाम न लगे बल्कि जिला के बगल से तमाम बड़ी गाड़ियां दूसरे जिले में प्रवेश कर जाय । यह महत्वाकांक्षी परियोजना बहुत तेज गति से काम कर रही है । हमारे समस्तीपुर में भी इस योजना के तहत बाईपास का निर्माण कराया जा रहा है, इसके लिए हम माननीय मंत्रीजी को बधाई देते हैं । पूरे बिहार के तमाम जिलों में यह काम किया जा रहा है इसके लिए हम उनको धन्यवाद देते हैं । नाबार्ड सम्पोषित योजना के तहत पूरे बिहार

में बहुत बेहतर ढंग से जो काम देखने को मिल रहे हैं उसके लिए भी हम इनका आभार प्रकट करते हैं । उसके तहत 20 पथों का जो काम अभी 718 करोड़ की लागत से हो रहा है उसके लिए, चाहे नालंदा जिला के अंतर्गत नूरसराय में हो, चाहे पटना के लोदीपुर में हो, मनेर के हल्दी छपरा में हो, दरभंगा में हो, भोजपुर में हो, रोहतास में हो, सीवान में हो तमाम जगहों पर जिस तरह से नाबार्ड के तहत बेहतर ढंग से काम हो रहा है उसी तरह केंद्रीय सड़क अवसंरचना निधि के तहत जो काम सी0आर0आई0एस0 के तहत होता है उसमें भी हम देख रहे हैं कि बहुत तेज गति से, बिहार की तमाम पटना जिलांतर्गत मीठापुर खगौल का मामला हो, चाहे चितवाना का मामला हो, चाहे बक्सर, मधुबनी, गया तमाम जिलों में जिस तेज गति से काम हो रहा है निश्चित रूप से बहुत ही सराहनीय है और नेपाल सीमा के बॉर्डर पर जो हमने देखा कि वहां पर 552 किलोमीटर का काम जिस तेज गति से हो रहा है जो आवश्यक है, क्योंकि हमारे दूसरे देश का बॉर्डर है, उसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं । राज्य उच्च पथ के मामले में जिस तरह से तीन हजार किलोमीटर जो स्टेट हाईवे सड़क है जिसका काम बहुत तेज गति से किया जा रहा है उसके लिए और कटिहार बलरामपुर में, बेतिया में, गोविंदपुर में तमाम जगहों पर लगभग तीन हजार करोड़ की लागत पर बड़े पैमाने पर स्टेट हाईवेज के निर्माण का काम किया जा रहा है । तमाम आर0ओ0बी0 के क्षेत्र में, हमने देखा कि पिछले 9-10 सालों से केंद्र में आपकी सरकार है और 15 साल से आप बिहार में हैं, यहां आर0ओ0बी0 कितने बनायें ? यहां पर नंद किशोर जी को लंबा समय मिला, तमाम मंत्री लोग रहें, आर0ओ0बी0 बिहार में सौ से ज्यादा स्वीकृत हैं, जो रोड और ओवर ब्रिज बनने हैं, तामम सदस्यों, आपके क्षेत्र में भी होगा और हमारे क्षेत्र में भी है लेकिन हमें लगता है, हम 12 साल से चिल्लाते रहे कि समस्तीपुर शहरी क्षेत्र में आर0ओ0बी0 बनाइये, आर0ओ0बी0 बनाइये, आर0ओ0बी0 बनाइये, पूरे शहर में जाम की स्थिति रहती है । 15 सालों में 100 पुल लंबित रहें, नहीं बनें । पिछली बार जब बने थे माननीय मंत्रीजी, तब इन्होंने जाकर रेल मंत्री से कई बार बातें कीं, उस बात में आगे बढ़ा है, दो, चार, दस पुलों को स्वीकृति मिली है, आगे एम0ओ0यू0 हुआ है । आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि जल्द ही हमलोगों का प्रयास होगा कि जो भी महत्वपूर्ण पुल वगैरह हैं उनको बनाने का काम करेंगे । हमने तो लगातार बोला कि समस्तीपुर जिला जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिला है, कर्पूरी ग्राम के बगल में और समस्तीपुर मुख्यालय में आर0ओ0बी0 की आवश्यकता है लेकिन कभी

भी जननायक कर्पूरी ठाकुर के प्रति सम्मान नहीं रहता है जिसके कारण वहां का काम 10-15 स्वीकृत हुए भी तो वह नहीं हुआ । हमें पूरा विश्वास है कि हमारे नेता जननायक कर्पूरी ठाकुर के अनुयायी हैं, समस्तीपुर जिले के आर0ओ0बी0 सहित तमाम समस्याओं का निराकरण करेंगे । हमने देखा है कि लगातार केंद्र सरकार के द्वारा, जो एन0एच0ए0आई0 की प्रशंसा कर रहे थे, एन0एच0ए0आई0 के जिस काम की दो साल, तीन साल कार्यावधि है, दस-दस साल में काम नहीं हो रहा है । वैसी एक सड़क नहीं है, ऐसी सड़कों की मैं गिनती बता सकता हूं जिनको दो सालों में पूरा कर दिया जाना चाहिए था । बिहार सरकार ने जो भी लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम हैं उसके लिए प्रधान सचिव स्तर के, विभागीय स्तर के भूमि से संबंधित तमाम अधिकारियों को डिप्यूट कर रखे हैं जो हर महीने मॉनिटरिंग करते हैं कि भाई एन0एच0ए0आई0 का काम तेज गति से हो, किसी तरह की बाधा उत्पन्न न हो । उसके बावजूद आप देखेंगे कि महेशखूंट और सहरसा का मामला पिछले आठ साल से काम चल रहा है, हाजीपुर-मुजफ्फरपुर का मामला पिछले 8-9 साल से काम चल रहा है, एकदम धीमी गति से चल रहा है । जिस तरह से आप देश को ले जाना चाहते हैं हमलोग उस गति से काम करना नहीं चाहते हैं, हम तेज गति से काम करना चाहते हैं । एक योजना आठ-आठ साल, दस-दस साल, बारह साल तक, आप किस तरह से काम करना चाहते हैं ? इसके लिए पत्राचार भी किया गया है । हाजीपुर-छपरा सड़क जिसके बारे में माननीय छोटे जी भी उठा रहे थे कि पिछले आठ साल से लंबित है । एन0एच0ए0आई0 काम कर रहा है लेकिन किस तरह से काम कर रहा है, जबकि बिहार सरकार ने जो भी लैंड से संबंधित समस्याएं हैं उनके निदान के लिए तमाम जो संबंधित और सक्षम अधिकारी हैं उनको प्रतिनियुक्त कर रखा है कि किसी तरह की समस्या उत्पन्न न हो । देखिए, बिहार में जो भी काम होगा वह न्याय के साथ काम होगा । एक न्याय का काम आदरणीय लालू प्रसाद जी ने किया जो सामाजिक न्याय की धारा को मजबूत करने का काम किया । दूसरा न्याय का काम नीतीश कुमार जी ने किया जो न्याय के साथ विकास के मामले में एक मजबूती प्रदान की बिहार को, तीसरी न्याय की लड़ाई होगी जो आर्थिक न्याय की लड़ाई होगी जिसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करने का काम करेंगे । सामाजिक न्याय के मामले में लालू प्रसाद जी, देखिए, बहुत लोग बहुत सी बातें बोलते हैं लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह विधान सभा सौ साल का इतिहास लिखता है और इतिहास है यहां पर, आप देखिए कि लालू प्रसाद जी के आने के पहले इस सदन में किस समाज के कितने लोग प्रतिनिधि हुआ करते थे । मैं

चुनौती के साथ कहता हूं कि आप निकलवाइये और दिखवाइये, आजादी से पहले दलित समाज के कितने सदस्य आया करते थे । आजादी के बाद भी, आजादी के बाद तो आरक्षण मिला तो दलित समाज के लोग आये लेकिन अति पिछड़े समाज, ओ0बी0सी0 समाज के कितने लोग आजादी के बाद 40 वर्षों में इस सदन में आ सकें, पांच से सात प्रतिशत लोग आ सकें । लालू प्रसाद जी के आने के बाद क्रांतिकारी बदलाव हुआ और एक साइलेन्ट रिवोल्यूशन काम किया और आज प्रतिनिधित्व देख लीजिए । आज प्रतिनिधित्व जो आप देख रहे हैं अति पिछड़ों का, तामाम लोगों का, उन्होंने आरक्षण, जो कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण दिया था दस प्रतिशत आरक्षण अति पिछड़ों को उसको बढ़ाकर 18 प्रतिशत आरक्षण करने का काम किया, उस लड़ाई को नीतीश कुमार जी ने आगे ले जाने का काम किया और पूरे बिहार में नल-जल, हर पंचायत में विद्यालय बनाने का काम, सड़कें बनाने का काम और तमाम तरह के काम किये हैं । उस लड़ाई में अंतिम...

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति-शांति ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : लड़ाई थी आर्थिक न्याय दिलाना । आर्थिक न्याय दिलाने का लक्ष्य क्या है ? उपाध्यक्ष महोदय, देश की संपत्ति चंद एक-दो उद्योगपतियों के हाथों में दस-दस, बीस-बीस लाख करोड़ रुपये दे दिये जाते हैं और हमारे गरीब-गुरबा पांच किलो अनाज में खुश होते हैं, ऐसी स्थिति पैदा की जा रही है। इसलिए तेजस्वी यादव जी का जो आर्थिक न्याय का संकल्प है, वह जो पैसा दो-चार उद्योगपतियों को दिया जाता है, वह पैसा गरीब-गुरबा, शोषित, वंचित समाज के बीच, स्मॉल इंडस्ट्रीज होने चाहिए, माइक्रो इंडस्ट्रीज होने चाहिए । जो असमानता है, उस आर्थिक असमानता को दूर करने का और सामाजिक न्याय के साथ विकास करने का संकल्प है । हम पूरे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि हमारे उप मुख्यमंत्री...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब कंक्लूड कीजिए ।

श्री अख्तरूल इस्लाम शाहीन : तेजस्वी यादव नीतीश जी के नेतृत्व में बेहतर ढंग से काम करने का काम करेंगे । बहुत-बहुत धन्यवाद । आपका आभार प्रकट करता हूं ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री अखतरूल ईमान साहब । आपका समय एक मिनट है ।

श्री अखतरूल ईमान : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं इस वक्त सिर्फ सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि सरकार दावे कर रही है कि छः घंटे में कहीं से भी राजधानी पहुंच सकते हैं, मेरा दावा यह है कि चार घंटे में हम जिला मुख्यालय

नहीं पहुंच पाते हैं । उसका बड़ा कारण यह है कि हमारे यहां सड़कों की कमी है । महोदय, बिहार में एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 15 हजार 700 किलोमीटर पी0डब्ल्यू0डी0 की सड़कें हैं । उस ऐतबार से सर, प्रत्येक विधान सभा में कम-से-कम 60 किलोमीटर, 70 किलोमीटर सड़कें हैं लेकिन मेरे यहां मात्र 31 किलोमीटर है और वहां पर जो पुल है पिछले दिनों डैमेज हो गया है भोकरी के पास हमारे क्षेत्र में, जो पलसा रोड है वह तीन सालों से टूटा पड़ा है । महसिल ब्रिज बन रहा है, पुल निगम से उसका काम रूका हुआ है । कोचाधामन प्रखंड में महोदय, तीन साल से ब्रिज का काम रूका हुआ है । मैं उसकी तरफ ध्यान दिलाना चाहता हूं । मैं जानता हूं कि आर0डब्ल्यू0डी इस वक्त उतना काम नहीं कर पाता क्वॉलिटी का जितना आर0सी0बी0 करता है । मैं माननीय उप मुख्यमंत्री साहब से बिनती करता हूं कि सीमांचल के पिछड़ेपन में बड़ी-बड़ी लंबी दूरी में पुलों का नहीं बनना है । वहां पर महानंदा में, कनकई में, परमान में 40-40 किलोमीटर पुल नहीं है । महाशय, जिसकी वजह से बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं । इसलिए मैं मांग करता हूं कि अभयपुर शिलाघाट में, कुट्टी घाट में बेरभरी में, निचितपुर में पुल का निर्माण हो और तैयबपुर में 113 साल पुराना, जो उस वक्त मीटर गेज की लेन लाईन थी उसी को कंवर्ट किया गया है, वन वे रोड है सर..

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : सर, एक मिनट, थोड़ी सी करम फरमाई कीजिए । डोक नदी में, खरखरी में पुल का निर्माण हो जाय सर । एक बात और मैं कहूंगा सर कि वार्ड सचिवों को नियमित कर दिया जाय और पंचायत प्रतिनिधियों को जो मानदेय दिया जाता है वह सम्मानजनक हो । एन0एच0-327 (ई) का काम हमारे यहां चल रहा है और वहां माराडंगा में अंडर पास नहीं दिया जा रहा है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । अगर सरकार पिछड़ेपन का निदान चाहती है, इंसाफ के साथ दावा है, मैं चाहता हूं कि यह दावा सत्य हो तो सीमांचल की इन समस्याओं का सामाधान किये बगैर सीमांचल में जो गरीबी है, जो पलायन है वह नहीं थम सकता है । महोदय,

उपाध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य, अब समाप्त कीजिए ।

श्री अखतरूल ईमान : मैं समझता हूं कि सरकार इस पर अपना ध्यान देकर कुछ-न-कुछ उस इलाके के उत्थान के लिए काम करेगी । बहुत-बहुत धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य श्री प्रणव कुमार । आपका समय पांच मिनट है ।

श्री प्रणव कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं । साथ ही साथ मैं अपने नेता प्रतिपक्ष और सचेतक महोदय के प्रति भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं ।

..क्रमश:.

.

टर्न-24/हेमन्त/20.03.2022

श्री प्रणव कुमार(क्रमशः) : मैं मुद्गल ऋषि की तपोभूमि और दानवीर कर्ण की भूमि मुंगेर का प्रतिनिधित्व करता हूं । मैं मुंगेर की महान जनता का धन्यवाद व्यक्त करता हूं । महोदय, सदन के आज के बदले हालात पर कुछ कहना चाहता हूं -

''न नजर बदली, न नजारे बदले, न सोच बदली,
लेकिन सदन के गलियारे बदल गये,
न कश्तियां बदली, न नाविक बदला ,
लेकिन हम लोगों की दिशाएं बदल गयीं ।''

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विपक्ष द्वारा लाये गये कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । आज पथ निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विभाग एवं कला संस्कृति एवं युवा विभाग में वाद-विवाद चल रहा है । मैं सबसे पहले आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने मुंगेर के लोगों की चिर-परिचित मांग थी कि गंगा नदी पर रेल से सड़क पुल की योजना, जो उनके कार्यकाल में मुंगेर के लोगों को तोहफा दिया गया है और खगड़िया से मुंगेर 333 बी, जो राष्ट्रीय राजमार्ग है और गंगा नदी पर जो सड़के बनी हैं, वह सड़कें

(व्यवधान)

असत्य तो आप लोगों से बोलना सीखे कोई...

उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, समय कम है, आप अपने क्षेत्र की बात कर लीजिए ।

श्री प्रणव कुमार : माननीय पथ निर्माण मंत्री से मैं कहना चाहूंगा कि उस रोड में एक भी लिंक पथ नहीं बनाया गया है जिससे शहर के लोगों को आने-जाने में बहुत ही कठिनाई महसूस होती है । साथ-ही-साथ जो मुंगेर से मिर्जाचौकी तक फोरलेन बनने जा रही है, मुंगेर के क्षेत्रों में सदर प्रखण्ड और जमालपुर प्रखण्ड के कुछ क्षेत्र हैं, जहां भूमि अधिग्रहण किया गया है सरकार के द्वारा और स्थानीय प्रशासन के द्वारा, वहां के किसानों पर लाठियां बरसाने का काम कर रहे हैं और उन्हें वर्षों पुरानी दर से जमीन अधिग्रहण का दिया जा रहा है और रजिस्ट्री ऑफिस की एम0वी0आर0 शीट पर जो रेट है, उस रेट के अनुसार नहीं दिया जा रहा है और हमेशा सरकार उस पर दबाव

बनाना चाहती है । माननीय उप मुख्यमंत्री-सह-पथ निर्माण मंत्री, मैं कहना चाहूंगा कि आप उस पर ध्यान दें ।

उपाध्यक्ष : ठीक है, अब समाप्त कीजिए ।

श्री प्रणव कुमार : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं...

उपाध्यक्ष : समय का अभाव है । सरकार का उत्तर होगा ।

श्री प्रणव कुमार : महोदय, एक मिनट । मैं सरकार से एक और आग्रह करना चाहता हूं कि कला संस्कृति विभाग की तरफ से कबड्डी, खेल प्रतियोगिता और कुश्ती यह ग्रामीणों का खेल है । बिहार खेल में फिसड्डी है । इसलिए मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि मुंगेर में वर्षों से....

उपाध्यक्ष : ठीक है । माननीय सदस्य श्री धिरेन्द्र प्रताप सिंह, अपनी बात तीन मिनट में खत्म कीजिए ।

श्री धिरेन्द्र प्रताप सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी को, उप मुख्यमंत्री जी को, मुख्य सचेतक जी को, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया । धन्यवाद देना चाहूंगा अपने क्षेत्र की जनता को, जिन्होंने अपनी आवाज बनाकर मुझे यहां पर बोलने का अवसर दिया । चूंकि समय सिर्फ तीन मिनट का दिया गया है और बोलना बहुत ज्यादा था ।

उपाध्यक्ष : समय आपका दस मिनट था । सरकार का उत्तर होगा, इसलिए समय कम कर दिया गया है ।

श्री धिरेन्द्र प्रताप सिंह : सबसे पहले तो हम यह कहना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री का जो सपना था कि बिहार के किसी कोने से बिहार की राजधानी में पांच घंटे में पहुंचना । पथ निर्माण को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी के इस सपने को पूरा किया, तो आज विपक्ष वाले हों या हम, कभी विपक्ष वाले हम लोगों के साथ भी बैठा करते थे । तो पटना से बाहर जिन लोगों का विधान सभा क्षेत्र था, 200-300 किलोमीटर, तो कहते थे कि कमर में दर्द हो गया है । लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अब विपक्ष वाले भी आराम से पांच घंटे में बिहार के किसी कोने से पटना आ जाते हैं ।

(व्यवधान)

अरे भई, थोड़ा सुन तो लीजिए । जहां तक आप लोग विकास की बात कह रहे थे, तो हम आप लोगों को वाल्मीकिनगर में आमत्रंण देना चाहेंगे खुले दिल से, आप भी माननीय मंत्री थे, तो मुझे लगता है कि आप जरूर पांच घंटे में पहुंचे होंगे वाल्मीकिनगर में । आप लोगों को मैं वाल्मीकिनगर में आने का न्यौता देना चाहूंगा ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : शांति, शांति ।

श्री धिरेन्द्र प्रताप सिंह : वहां पर आप आकर देखिये कि बिहार प्रदेश का, जो उन्होंने विकास के पथ पर चलते हुए एक मरीन ड्राइव का निर्माण किया है, मुझे लगता है कि मुंबई का मरीन ड्राइव, बिहार के उस मरीन ड्राइव के आगे फेल है । तो आग्रह करेंगे कि आप लोग जरूर वहां पर आयें । माननीय पथ निर्माण मंत्री जी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि बगहा शहर जो है, काफी जाम रहता है, तो जाम से मुक्ति कराने के लिए वहां बाईपास का निर्माण करवाया जाय । पश्चिम चम्पारण जिला के बेतिया मनुवा पुल से रतौल तक सड़क का कार्य काफी धीमी गति से चल रहा है इसके कार्य में प्रगति लायी जाय । बगहा में दो आर0ओ0बी0 निर्माणाधीन हैं । आग्रह है कि बगहा सेमरा पथ पर भी चीनी मिल के समीप एक रेलवे ऑवर ब्रिज की अति आवश्यकता है, क्योंकि वहां हमेशा जाम की समस्या रहती है, तो आग्रह है कि वहां पर आर0ओ0बी0 का निर्माण करवाया जाय और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि माननीय मंत्री जी का और पथ निर्माण के सचिव जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि जो मेरा विधान सभा क्षेत्र है, वह दो राज्यों से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश और बिहार । उसमें 104 से लेकर 110 किलोमीटर का जो पथ है, एन0एच0-227 । सात किलोमीटर का जो पथ है, वन विभाग से एन0ओ0सी0 नहीं मिलने के कारण काफी जर्जर स्थिति में है । वन विभाग की आपत्ति के समाधान के लिए भारत सरकार अन्य प्रांतों में वनों से होकर गुजरने वाले मार्गों पर एलिवेटेड रोड बनाती है, जो राहगीरों एवं पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है । इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आप मध्य प्रदेश में देख सकते हैं...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त कीजिए ।

श्री धिरेन्द्र प्रताप सिंह : सर, एक मिनट । 16 किलोमीटर टेन्स टाईगर रिजर्व में है एलिवेटेड रोड और राजस्थान में 23 किलोमीटर का प्रस्तावित है । तो मैं आग्रह करना चाहूंगा आप लोगों से कि मेरे विधान सभा में भी मात्र तीन किलोमीटर लगेगा, तीन किलोमीटर का एलिवेटेड रोड बनाया जाय । इस एलिवेटेड रोड बना देने की वजह से, बगहा में जो दो आर0ओ0बी0 बन रहा है उसकी जो उपयोगिता है, वह बढ़ेगी और आस्था का केंद्र, जो मदनपुरा का माई स्थान है, मुस्लिमों का मदार चौक का मेला है एवं रामायण से जुड़े हुए वाल्मीकि आश्रम है, पर यातायात में सुगमता होगी. ..

उपाध्यक्ष : ठीक है । समाप्त किया जाय ।

श्री धिरेन्द्र प्रताप सिंह : सर, थोड़ा और । और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रीय सीमा, जो भारत नेपाल इंडो बॉर्डर है । अगर यह एलिवेटेड रोड बनता है, तो मुझे लगता

है कि भारत नेपाल सीमा का जो रोड चल रहा है, वह उसके बगल से होकर ही गुजरता है, तो काफी सुविधा होगी ।

उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग । सरकार का उत्तर होना है, इसलिए पांच मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे माननीय मंत्री जी ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय,....

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष : इनका गिलोटिन में है ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया । आज मैं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की मांग संख्या-44 के वित्तीय बजट पर बोलने के लिए यहां पर खड़ा हूं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि सभी को मालूम है कि बिहार की जो जनसंख्या है, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति के 1 करोड़ 65 लाख 67 हजार 325 लोग हैं और अनुसूचित जनजाति के 13 लाख 36 हजार 573 लोग हैं । मैं उनकी अपेक्षा और आकांक्षाओं का यह बजट आपके सामने रखने के लिए यहां पर उपस्थित हूं ।

(क्रमशः)

टर्न-25/धिरेन्द्र/20.03.2023

...क्रमशः...

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : महोदय, मैं सर्वप्रथम बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करते हुए, जिन्होंने हम सब को यह अधिकार दिया, सम्मान दिया कि आज हम सब के बीच में यहाँ पर बोल सकें । मैं उनको याद करते हुए याद दिलाना चाहता हूँ सदन को कि जो अनुसूचित जाति शब्द आया, अनुसूचित जन-जाति शब्द, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, 1935 में यह शब्द आया और भारत के संविधान में इसको 1950 में लागू किया गया । हमारे संविधान की आर्टिकल्स, अगर हम 341 की बात करें, 342 की बात करें, 29(1) की बात करें, 15(4) की बात करें, 16 की बात करें, उन सब आर्टिकलों में एक प्रावधान दिया गया है कि जो भारत के या बिहार के गरीब वर्ग हैं, जिसको हम अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति कहते हैं, उनको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और कल्चरल तौर पर, उनको सांस्कृतिक तौर पर, उनका कैसे हम उत्थान करें, इसके लिए हमलोगों को सोचना है । मैं माननीय नीतीश कुमार जी को जो हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री हैं, मैं उनको धन्यावद देना चाहता हूँ कि उनकी संवेदनशीलता कितनी है, उनके प्रति वे कितने

जागरूक हैं और कितने सोचते हैं कि 01 अप्रील, 2007 को उनके लिए एक अलग विभाग का गठन किया गया, जिसका नाम अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति विभाग है और वह शुरूआत 40 करोड़ 48 लाख रुपये से किया गया था, आज हम 18 अरब 55 लाख हैं जो 4000 प्रतिशत ज्यादा है । समय कम है, मैं सॉर्ट में बता देना चाहता हूँ कि हम सामाजिक तौर पर उनके लिए क्या कर रहे हैं, आर्थिक तौर पर क्या कर रहे हैं, सांस्कृतिक तौर पर क्या कर रहे हैं, जैसा कि हमारे माननीय सदस्य श्री मनोज मंजिल ने जो बात उठायी थी कि आज भी 49.8 परसेंट ऐसे लोग हैं जो हायर एजुकेशन नहीं कर पाते हैं जो एस०सी० के लोग हैं और 31 दशमलव कुछ परसेंट हैं जो एस०टी० के लोग हैं जो हायर एजुकेशन पूरा नहीं करना चाहते हैं । हम समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला था, उसके लिए, समतामूलक समाज के लिए जब उन बच्चों को, उनके परिवार के जो अंग हैं उनको पढ़ाने का काम करेंगे तभी जाकर हम समतामूलक, जिसको समान शिक्षा प्रणाली की बात हमारे माननीय सदस्य ने बोला था । आज हमारे पास माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जो सरकार चल रही है और उनके कारण हमलोग अभी 87 विद्यालय हमारे इस प्रदेश में चल रहे हैं और अभी 13 विद्यालय बन कर तैयार हो गए हैं और जो बिहार सरकार का संकल्प है उसके अनुसार ऐसे प्रखंड जहाँ 50 हजार से ज्यादा की आबादी है और ऐसे प्रखंड जहाँ 30 हजार से ज्यादा की आबादी है वहाँ पर एक विद्यालय खोलेंगे और 30 हजार में एक छात्रावास का निर्माण करेंगे तो आने वाले समय में हम 40 ऐसे स्कूलों का निर्माण करने जा रहे हैं और 136 छात्रावास का निर्माण करने जा रहे हैं और हमारी जो संख्या होगी वह 720 आसन वाले हमारे स्कूल होंगे, करीब एक लाख स्टूडेंट को हम आवासित होकर पढ़ाने का काम करेंगे...

उपाध्यक्ष : ठीक है, अब समाप्त कीजिये ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : उसको भोजन देने का काम करेंगे, उनको कपड़े देने का काम करेंगे, उनको किताब देने का काम करेंगे और उनके लिए सही तरह से खेल-कूद की जो सारी सामग्री, उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे । हमारी सरकार इस तरह से काम कर रही है । महोदय...

उपाध्यक्ष : अब समाप्त किया जाय । समय का अभाव है ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : महोदय, हमलोग करीब 38 लाख लोगों को छात्रवृत्ति देते हैं जो क्लास-1 से लेकर पोस्टमैट्रिक तक है और बिहार सरकार ने माननीय नीतीश कुमार जी की अगुवाई में काम किया । भारत सरकार ने 2.5 लाख आय सीमा रखी थी लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 लाख कर उनलोगों को भी हम देने का काम

कर रहे हैं जो पूरी तरह से राज्यांश से दिया जाता है और हमलोग उनके प्रति सोचते हैं, हम एक हजार रुपये उनको डी॰बी॰टी॰ करते हैं, हमारे जो बच्चे 10वीं में उत्तीर्ण होते हैं उनको हम 10 हजार देते हैं, जो सैकेंड डिवीजन होते हैं उनको हम 8 हजार देते हैं, जो इंटर में होते हैं उनको 15 हजार और 10 हजार रुपये देते हैं और हम ऐसे 2 लाख 80 हजार लोगों को पैसा देने का काम कर रहे हैं जो बिहार सरकार अपने बजट से देने का काम कर रही है और 305 करोड़ रुपये इसमें खर्च आता है ।

(इस अवसर पर माननीय अध्यक्ष महोदय ने आसन ग्रहण किया)

महोदय, हम विशेष रूप से महादलितों के लिए, उनके उत्थान के लिए हमारे पास विकास-मित्र हैं महोदय, विकास-मित्र आज बिहार में 9,554 की संख्या में हैं और उनके...

अध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, अब संक्षिप्त करें इसलिए कि अब सरकार का उत्तर होना है ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : महोदय, संक्षिप्त ही कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग शांति बनाये रखें ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : महोदय, दो मिनट ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपलोग शांति बनाये रखें, वे बोल रहे हैं, आपलोग बैठिये । साढ़े चार बजे से सरकार का भी उत्तर होगा । ठीक है, बैठिये ।

श्री संतोष कुमार सुमन, मंत्री : महोदय, हमारे पास 5,554 विकास-मित्र हैं और मैं सदन को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ कि हमलोग विकास रजिस्टर वर्जन-2 का काम कर रहे हैं, जिसमें सात निश्चय, जल-जीवन-हरियाली और दहेज प्रथा, ये सारी चीजों का संकलन करते हैं और हमारे पास 36 लाख 87 हजार 637 विकास रजिस्टर हैं जो महादलित समुदाय के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति समुदाय के जितने भी परिवार हैं उनका डाटा संकलन कर हमलोग उनके पक्ष में काम करने का काम कर रहे हैं । हमलोग जो उनके ऊपर अत्याचार होते हैं उसके लिए भी काम कर रहे हैं और आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि 6,671 ऐसे केस हैं, हमलोग 90 परसेंट लोगों को मुआवजा देते हैं, जितने भी केस रजिस्टर होते हैं हमलोग तुरंत उनको पैसा देने का काम करते हैं तो हमारा विभाग हर तरीके से सामाजिक स्तर पर हो, शैक्षणिक स्तर पर हो, चाहे किसी भी तरह से उनका उत्थान करने के लिए, समाज की मुख्यधारा में लोने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं इसलिए, महोदय, मैं आपके....

अध्यक्ष : माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग ।

(व्यवधान)

आपलोग सुनिये, बैठिये, आराम से सुनिये । अब सरकार का उत्तर होगा ।

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय...

अध्यक्ष : सरकार को मैंने, विभागीय मंत्री खड़े हो गए हैं ।

(व्यवधान)

क्या ? कहिये न ।

श्री विजय कुमार सिन्हा, नेता विरोधी दल : अध्यक्ष महोदय, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हमलोग सुनें, उसके पहले माननीय उप मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का मामला देशभर में चल रहा है ई॰डी॰ और सी॰बी॰आई॰ का, और उसमें आरोपित हैं तो ये बता दें कि क्या मसला है ?

(व्यवधान)

अध्यक्ष : अब सरकार का उत्तर होगा । माननीय नेता प्रतिपक्ष, आप बैठिये, आप स्थान ग्रहण कीजिये । माननीय मंत्री...

(व्यवधान)

देखिये, इसी कारण से आपको समय नहीं दिया जाता है । अब सरकार का उत्तर हो रहा है । माननीय सदस्यगण, आपलोग अपने स्थान पर बैठ जायें । सरकार का उत्तर।

सरकार का उत्तर

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, पथ निर्माण विभाग के बजट पर वाद-विवाद में... (व्यवधान)

अध्यक्ष : अब आपलोग शांत रहिये ।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : जिन-जिन सदस्यों ने वाद-विवाद में शिरकत हुए हैं, उन सभी के प्रति हम आभार प्रकट करते हैं ।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : आपके कहने से हम सफाई दिलवायें । जाइये, जाइये, सफाई दिलवाने चले हैं । यह आसन है, आपके दवाब से आसन नहीं चलेगा । सरकार का उत्तर हो रहा है और आप इंटरफेयर कर रहे हैं । सरकार का उत्तर । माननीय मंत्री...

(व्यवधान)

कुछ नहीं, जाइये आपलोग, आपलोगों को तो जाना ही था । माननीय मंत्री जी ।

(इस अवसर विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन का बहिर्गमन किया गया)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : अध्यक्ष महोदय, छोटे लाल राय जी, कृष्ण कुमार मंटू जी, मीना कुमारी जी, भीम कुमार सिंह जी, संजय कुमार सिंह जी, अख्तरूल इस्लाम शाहीन जी, शकील अहमद खाँ जी, मनोज मंजिल जी, डॉ॰ अनिल कुमार जी, रिंकु सिंह जी, अजय कुमार जी, राम रतन सिंह जी, श्रेयसी सिंह जी, अखतरूल ईमान जी, प्रणव कुमार जी, इन सदस्यों ने वाद-विवाद में भाग लिया । इन सब के सुझावों को, इन सब की बातों को हमारे पथ निर्माण विभाग के अधिकारियों ने नोट किया है और हमलोगों ने संज्ञान में भी लिया है । पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मौका दिया और साथ-ही-साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देता हूँ कि एक अवसर जो है मुझको दिया है, एक भारी जिम्मेवारी दी है जिसको पूरी ईमानदारी के तहत इस जवाबदेही को हम पूरा करने में लगे हैं । अब महोदय, नेता प्रतिपक्ष तो चले गए, उनसे हमें सवाल पूछना था, लगता है किसी ने पहले ही उनको हिंट कर दिया । महोदय, इस सदन में सभी लोगों के सामने उन्होंने बोला था कि तमिलनाडु की घटना अगर गलत साबित हो गई तो मैं माफी माँगूंगा । उनके कहने पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान में लेते हुए वहाँ टीम भी भेजी और बात स्पष्ट रूप से तमिलनाडु की पुलिस हो, बिहार की पुलिस हो, उन्होंने साफ तौर पर बोला कि जो घटना हुई थी, यह एक फेक वीडियो था, एक प्रोपगेंडा था दो राज्यों को लड़ाने की...

...क्रमशः...

टर्न-26/संगीता/20.03.2023

(क्रमशः)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : ये लोग तो भारत माता की जय बोलते हैं लेकिन तमिलनाडु इसी भारत का अंग है लेकिन कितनी मन में घृणा है, जहर है, नफरत है इन लोगों को बिना जांच-पड़ताल किए हुए, बिना क्वेरी किए हुए बिना वेरिफाई किए हुए आकर के हंगामा करना, अभी यहीं के रिपोर्टर बेचारे लिख करके बाहर जा रहे थे तो हंगामा करने लगे अरे बाहर का लोग कैसे आ गया, ये अभी साबित हुआ है महोदय मतलब बिना हाथ-गोर पांव के जो मन में आता है ये लोग बोलते हैं चाहे पहले शहीद वाला पिता के अपमान की बात कही गई, वह भी झूठा साबित हुआ, तमिलनाडु वाला महोदय जो बात था वह भी झूठा साबित हुआ तो महोदय, इनका केवल एक ही काम है केवल झूठ बोलना और हमको आजतक समझ में नहीं आया असत्य और झूठ में क्या अंतर है ? असत्य लोगों में, समाज में जहर किस तरह का बोया जाय उसी काम में ये लोग लगे रहते हैं महोदय तो ज्यादा कुछ

नहीं कहेंगे । माइक वाली जो घटना हुई थी, वे कह रहे थे कि खोलकर छूते ही गिर गया था और सबलोगों ने वीडियो देखा कैसे ताबड़तोड़ घुमाई चल रहा था, खिंचाई चल रहा था उसके बचाव में ये आ गये महोदय मतलब अब नेता प्रतिपक्ष जैसे भी हों, नेता प्रतिपक्ष हैं संवैधानिक पद है तो कम से कम अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करना चाहिए । अब हमको और नीतीश जी को पता नहीं था कि हम जब एक होंगे तो इनके तोते जो हैं पिंजरे से बाहर निकलेंगे तो ये तो हमको पता ही था महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे अभिभावक हैं उनको भी पता था कि तोते जो हैं निकलेंगे पिंजरे में से, अब ये लोग कह रहे हैं कि हमको जो है माफी मांगना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इस्तीफा मांग रहे थे, ई0डी0-सी0बी0आई0 की जांच की बात कर रहे थे, उस पर हम आते लेकिन ये लोग तो चले गए लेकिन आज पथ निर्माण विभाग पर वाद-विवाद है इसपर भी हम आयेंगे बतायेंगे लेकिन आज जो हमलोगों का प्रयास है महोदय, पथ निर्माण विभाग का कि अच्छी कनेक्टिविटी राज्य को दें, अच्छी कनेक्टिविटी के तहत पुल का निर्माण होता है, अच्छी सड़कों का निर्माण होता है और मेन्टेनेंस को भी हमलोग जो हैं खासतौर पर ध्यान दें ताकि जो चीजें हमने बनायी हैं उसको भी हमलोग मेन्टेन कर सकें और हमारी और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमलोगों की सरकार की कोशिश है कि विकास के पथ पर हमलोग आगे बढ़ें इसी तरीके से निर्माण करें । ''पक्की सड़क, अच्छी सड़क और भी पक्की सड़क तरक्की की सड़क बनाने वालों के लिए रूकने-थकने की गुंजाइश कहां है'' तो इस दिशा में और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में ''Bihar is one of the leading State'' मतलब इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में बिहार जो है लीडिंग स्टेट है, बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स पथ निर्माण विभाग ने किए हैं चाहे बी0एस0आर0डी0सी0 हो, पुल निर्माण निगम हो या विभाग के लोग हों, बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं महोदय इसके लिए हम विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ, कर्मियों के साथ-साथ सबसे बड़ी भूमिका जिनकी रही है अभियन्ताओं, उन सभी अभियन्ताओं को सदन में आज खड़े होकर के धन्यवाद देना चाहते हैं, बधाई देना चाहते हैं कि बिहार जब आगे बढ़ा है तो उनकी भी बड़ी भूमिका रही है और माननीय मुख्यमंत्री जी खुद इंजीनियर हैं, एक-एक चीज जो है चीजों को समझते हैं, कई इनके प्रोजेक्ट्स हैं जो कम्प्लीट किए गए हैं, इन्हीं की सोच का असर है महोदय जो काम हुआ है । मुख्यमंत्री जी का पहले विचार था 6 घंटे में आ जायं, फिर 5 घंटे में आ जायं वह विभाग ने जो है हासिल किया है और हमलोगों की कोशिश है कि और भी रास्ते को और सुगम बनाया जाय और सुरक्षित, सेफ्टी को देखते हुए सेफ्टी भी बहुत जरूरी है महोदय आए दिन एक्सीडेंट होता है

अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है । रोड में मेन्टेनेंस के लिए भी हमलोग ओ0पी0आर0एम0सी0 के थ्रू करते हैं लेकिन एक नई टेक्नोलॉजी है, प्रत्यय अमृत जी बैठे हैं उनको भी धन्यवाद देते हैं कि ये काम हुआ, रियल टाईम मॉनिटरिंग मतलब कम्प्लेन जो है तुरंत इंजीनियर जो है वह करता है, मैन्डेटरी उसकी मॉनिटरिंग होती है और तुरंत इमीडिएट उसका जो है हल होता है इसको देखते हुए कई राज्य के लोग और खुद केंद्र सरकार के लोग सीखकर के गए हैं महोदय तो यह बड़ी उपलब्धि है, हरेक चीज जो है कायदे से किया जा रहा है लेकिन आपको हम बता दें ज्यादा कुछ नहीं इस विभाग की बहुत सारी उपलब्धियां रही हैं, समय कम है क्योंकि मूलतः सबलोग जानते हैं और सब लोग मन पर दिल पर हाथ रखकर अगर मानें तो मानेंगे कि भाई हां रोड के मामले में, बिहार जो है पुल के मामले में बेहतरीन काम किया और काम चल रहे हैं प्रोजेक्ट कर रहे हैं । चाहे कोई किसी दल का हो, किसी विचार का हो माननीय नीतीश कुमार जी ने जो किया है वह सब चीज जो है मानते हैं लोग लेकिन कुछ जो मेन प्रोजेक्ट्स वगैरह है जैसे आपका जे0पी0 गंगा परियोजना के दीघा से पी0एम0सी0एच0 पथांश का लोकार्पण हुआ, अटल पथ फेज-2 का हुआ, महात्मा गांधी सेतु का लोकार्पण हुआ जिससे उत्तर बिहार एवं दक्षिण बिहार का आवागमन जो है, संपर्कता सुगम से हुआ है महोदय तो काफी जो है काम अच्छा हुआ है । इसके लिए हम कहना चाहेंगे कि "अच्छी सड़कें आधुनिक युग की वह जरूरत है, जिस पर देश-प्रदेश के सपनें सरपट भागते हैं" तो महोदय, इसी सिलसिले में अगर देखिएगा तो चाहे एम0डी0आर0 हो, स्टेट हाईवे हो, एन0एच0 हो, वामपंथ-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जो है हमलोग काम कर रहे हैं, आर0ओ0बी0 का निर्माण हो, केंद्र सड़क अवसंरचना निधि जो सी0आर0एफ0 फंड जो कहते हैं उसके तहत भी काम होता है । सात निश्चय पार्ट-2 का सुलभ संपर्कता, बाईपास, ऐलिवेटेड रोड ये बने, नाबार्ड संपोषित जो है वह भी कार्य उसके तहत होता है और महोदय प्रमुख नदियों पर पुल का निर्माण अगर बनाना हो तो कई ऐसी प्रमुख नदियां हैं चाहे कोसी में, सीमांचल में जो बनी हैं । नई नियुक्तियां भी क्योंकि मैनपॉवर रहेगा तो उसके लिए विभाग ने निकाला है कई जगह रिक्रूटमेंट हुआ है और कई जगह जो है आगे भेजा गया है कि ज्यादा से ज्यादा इंजीनियर हम अपनी जरूरत को पूरा कर सकें, उस दिशा में भी काम किया जा रहा है तो महोदय बहुत सारे ऐसे काम हैं जो पथ निर्माण विभाग में हुए हैं उसका कुछ हमारे सदस्य जो हैं वे कह रहे थे, उन सबका जो क्वेरी था, अब श्रेयसी बात को रख रही थी हमारे साथ ही स्कूल में पढ़ी है जैसा वह बता रही थी, अच्छी डांसर भी है अच्छी स्पोर्ट्समैन भी है वह कह रही थी कि

हम अब तक नितीन गडकरी जी से नहीं मिले हैं हम गंभीर नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि अभी तो बिहार आए थे नितीन गडकरी जी जो हम गए थे तो अपनी मांग को भी हमने रखा था, उद्घाटन जो कैमूर के इलाके में हुआ था, उनको पता ही नहीं है और हमने जो चिट्ठी भी लिखी है नितीन गडकरी जी को भाई जो उनके एन0एच0ए0आई0 के जो प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं वे धीरे चल रहे हैं उसमें तेजी लायें उसमें महिषकुट, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया पथ जो एन0एच0-107 है, एन0एच0-77 जो हाजीपुर-मुजफ्फरपुर पथ है इसमें भी काम धीरे चल रहा है, राष्ट्रीय उच्च पथ जो एन0एच0-19 है हाजीपुर-छपरा पथ की क्या स्थिति है सबलोग जानते हैं, पटना-गया-डोभी जो एन0एच0-83 है उसको लेकर हमने चिट्ठी लिखा और भी निर्माणाधीन जो बाईपास में प्रस्तावित सभी 5 आर0ओ0बी0 के निर्माण कार्य की गति अत्यंत ही स्लो है बहुत ही धीमी है, उसको लेकर हमने लिखा, वीरपुर-उदाकिशुनगंज एन0एच0-106 को 2-लेन के अनुरूप जो है निर्माण का कार्य किया जा रहा है उसमें भी जो प्रगति है जो होनी चाहिए वह नहीं है तो ऐसी-ऐसी जितनी चीजें हैं और जहां भू-अर्जन की कार्रवाई तो चल ही रही है तो ऐसे-ऐसे पथों को लेकर के हमने नितीन गडकरी जी को चिट्ठी लिखा है लेकिन उनको तय करना है ये जितने पथ हैं आपलोग सबलोग जान रहे हैं बिहार के लोग हैं कि कितना दिन से चल रहा है लेकिन अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है तो उनको तो पता नहीं स्पोर्ट्स को लेकर पूछे थे हम, धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी यहां बैठे हैं कि महागठबंधन की सरकार आते ही स्पोर्ट्स पॉलिसी बनायी है 'मेडल लाओ और नौकरी पाओ', इससे बढ़िया स्पोर्ट्स पॉलिसी नहीं है चाहे जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की बात कर रही थी राजगीर में, वह बन ही रहा है मोइन-उल-हक स्टेडियम भी बन रहा है हरेक चीजें जो हैं आ रही हैं पटरी पर और चीजें जो हैं और सुधारा जा रहा है लेकिन जो भी खेलकूद में हुआ वह तो बिहार सरकार ने ही किया...

(क्रमशः)

टर्न-27/सुरज/20.03.2023

(क्रमशः)

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : एक चीज बता दें जो मोदी जी ने किया हो 8 साल में, 9 साल में, केन्द्र की सरकार ने खेल-कूद को लेकर के । उनको तो कुछ भी कहना है, कहती रहें । असल में वह गलत जगह बैठी हुई हैं बेचारी, हमको तो अच्छा लगता है जब कोई युवा बोलते हैं, कोई डिसीजन मेकिंग में आता है, पॉलिसी मेकिंग में आता है तो हमें बड़ी खुशी होती है और बड़े अच्छे से भी

अपनी बात को रख रहीं थीं । लेकिन ऐसी जगह पहुंच गयी हैं जहां ज्ञान नहीं दिया जाता है, जहां केवल झूठ-फरेब की राजनीति होती है, नकारात्मक चीजें होती है, उस खेमे में बैठी हुई हैं खैर ये तो उनकी मर्जी लेकिन धक्का तो सबको लगेगा ही। ये लोग क्या-क्या कर रहे हैं, अपने सहयोगियों के साथ क्या-क्या किये, अपने लोगों के साथ क्या-क्या कर रहे हैं किसको नहीं पता है । तो इसलिये महोदय ये जो नाबार्ड की बात कर रहीं थीं 18 सौ 50 करोड़ की 41 स्कीम है, जो केबिनेट 31 मार्च से पहले हो जायेगा डी0पी0आर0 ऑफ इच प्रोजेक्ट 41 जो है डी0पी0आर0, टाइम लगता है वह टाइम होते ही नेचुरल प्रोसेस है इट विल टेक टाइम वह समय पर हो जायेगा और 12 स्कीम जो है जिसमें अप्रोच रोड का इशू था उसको हमलोगों ने देखते हुये लैंड एक्यूजीशन को रिजोल्व करते हुये सारा कर लिये हैं और 4 जो स्कीम है वह पेंडिंग है, वह भी 15 अप्रील तक पूर्ण कर लिये जायेंगे । तो ये सारी चीजें हैं और बिना पहुंच पथ के वह बता रही थी कि पहुंच पथ नहीं है । वैसे चार हैं जहां पहुंच पथ नहीं हैं अरवल जिला में भगवतीपुर के बीच पुल का जो है, सुगम पथ को लेकर के जो पुल के निर्माण के लिये भू-अर्जन चल रहा है, जून, 2023 तक हो जायेगा । बेतिया जिला में ससीस्वा बाजार से सिघरना मार्च, 2023 तक कर लिया जायेगा । बेतिया जिला में धनकुटवा में त्रिभुवन नदी पर पुल का निर्माण है उसका भी 2023 तक लक्ष्य पूर्ण कर लिया जायेगा और कटिहार जिला में गोगरा लालगंज पथ जो पुल है उसकी भी भू-अर्जन की प्रक्रिया चल रही है नवम्बर, 2023 तक इसको भी पूर्ण कराने का लक्ष्य है महोदय तो ये सारी चीजें चल रही हैं । संजय सरावगी जी आएं वे बता रहे थे दरभंगा के बारे में तो उनको तो खुश होना चाहिये कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उनकी समाधान यात्रा में काफी चीजों का समाधान हुआ है तो काफी काम जो है इस यात्रा के बाद हुआ है । अब ये वी0आई0पी0 रोड के चौड़ीकरण का कह रहे थे तो उसका महोदय डी0पी0आर0 बन रहा है और 4 सड़क की जहां तक बात कर रहे थे वह स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष उसको रखा गया है अगर वह पास हो जायेगा तो निविदा अप्रील तक निकाला जायेगा और साथ ही साथ जो फ्लाईओवर की बात कह रहे थे इसको गंभीरता से हमलोग विचार कर रहे हैं और जरूरत पड़ी तो बनायेंगे भी महोदय । तो ये सारा काम है हमलोग कर रहे हैं लेकिन आप देखियेगा अभी सीमांचल को लेकर के अखतरूल ईमान जी भी बात कर रहे थे, महानंदा नदी पर दो सौ करोड़ का पुल जो है निर्माण कराने का, हमलोगों के पास प्रस्ताव है इसलिये हमलोग करवा देंगे और भी गोह विधान सभा में हसपुरा का जो भीम जी बता रहे थे कई सड़के हैं । हमारे अधिकारियों ने नोट किया है वे सारी चीजें देख

लेंगे । वैसे बाईपास जो है हसपुरा में कार्ययोजना 2023-24 में है । हाजीपुर से वैशाली पथ की वाइडिंग की बात कर रहे थे उनके सदस्य वह भी 10 मीटर तक हमलोग वाइडिंग करेंगे । कटिहार में शकील अहमद जी का कहना था कि जो सिंगल लेन है उसको डबल लेन के लिये हमलोग एक्जामिन कर रहे हैं तो सारी चीजों का काम हमलोग कर हैं महोदय । छोटे लाल जी का भी था उसको भी हमलोग एक्जामिन करवा रहे हैं जो कपरफोड़ा से दरिहारा रोड है उसके वाइडिंग का प्रस्ताव भी है 2023-24 में तो ये सारी चीज जो है । अभी बाबूबरही से मीना जी बता रहीं थीं तेनुआही से खुटौना 16 किलोमीटर जो है वह भी प्रस्तावित है । तो ये सारे काम को महोदय हमलोग कर रहे हैं और नीतीश जी के नेतृत्व में सारे काम को हमलोगों की कोशिश है कि कोई प्रोजेक्ट अगर हमलोग उठाते हैं तो सही समय पर हमलोग जो है उसको पूरा करते हैं, जो टारगेट है, उसको समय पर पकड़ते हैं तो ये कार्रवाई की जा रही है । जरा दिक्कत होती है भू-अर्जन को लेकर तो उसके लिये अलग से हमलोगों ने अधिकारी जो हैं, विशेषज्ञ जो हैं भू-अर्जन को लेकर के अलग से सेल बनाया हुआ है ताकि तेजी आ सके । तो महोदय, इन लोगों को तो कोई काम है नहीं, सुनना तो है नहीं, काम से तो कोई मतलब रहता नहीं है । दिनभर इन लोगों का काम है नीतीश जी को गाली देना, हमको गाली देना और रेडबुल पी-पीकर गाली दें और एनर्जी ड्रिंक पी लें । इनके गाली देने से तो कुछ होने वाला है नहीं महोदय । तो इसलिये हमलोग बार-बार कहते हैं कि बी0जे0पी के पास न कोई चाल है, न कोई चरित्र है, न कोई चेहरा है और न कोई नेतृत्व है, ये असलियत है महोदय । केवल लोगों में असत्य भ्रम फैलाना, समाज को तोड़ना, नफरत की राजनीति करना तो इनके लिये एक शायरी हम पढ़ देते हैं:

''लहजे में बदजुबानी,
चेहरे पर नकाब लिये फिरते हैं,
वो जिनके खुद के बहीखाते बिगड़े हैं,
वह मेरा हिसाब लिये फिरते हैं ।''

तो महोदय ये बोल रहे हैं ई0डी0, सी0बी0आई0, इनकम टैक्स भाई जांच कोई नया है । 2017 में इनके एक नेता हैं अफवाह मियां दिन भर पी0सी0 करना, दिन भर गरियाना । पी0सी0 करते हैं पिछली बार 2017 में पी0सी0 किये कि मिट्टी घोटाला हो गया, मिट्टी घोटाला हो गया । फिर वही मिट्टी घोटाला बाद में गठबंधन टूट गया, भ्रम फैलाया गया, अफवाह फैलाया गया, कन्फ्यूजन पैदा किया । वही बड़बोले नेता फिर संबंधित विभाग के मंत्री बने, मिट्टी घोटाले पर ही मिट्टी डाल दिये । जिन्हें उनकी पार्टी ने ही राजनीतिक रूप से दफन कर दिया

वो अपनी प्रासंगिकता खोजने के लिये उसी मिट्टी तले दबे हुये, हाथ-पांव निकाल अपने आकाओं का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं । सबलोगों ने देखा था क्या बकवास बातें महोदय डेली, हम तो पुछते हैं कि नया क्या बोल रहे हैं । जो आप बोल रहे हैं वो दो बार सी0बी0आई0 जांच करके बंद कर दिया, ई0डी0 जो है जांच करके बंद कर दिया । एक-एक की बात बोलते जाते हैं लेकिन अपने अशियाना के बारे में नहीं बताते हैं । अशियाना जो है उनका उसके बारे में भी उनको जिक्र करना चाहिये लेकिन कोई नहीं, अब जांच होगी तो हम तो जायेंगे । अब किस प्रकार से रेड पड़ा, नहीं पड़ा, क्यों हो रहा है असली डर महोदय 2024 का है । ये जान रहे हैं, ये कहीं टिकने वाले नहीं हैं, असली डर महोदय 2024 का है और इतने घबराहट में क्या-क्या नहीं कर रहे हैं, हालांकि करते रहें । 6 साल से क्या कर रहे थे, क्या हुआ एक हो गये तो फिर से इनका तोता पिंजड़ा से बाहर आ गया । कोई काम तो किये नहीं, कोई एविडेंस हो तो लाओ न भाई । बोला गया कि मेरे यहां से कितना छः सौ करोड़, खजाना मिला । हम बोलें उनको सीजर लिस्ट तो दिखा दो ई0डी0 वाले, पंचनामा होता है दिखा दो पता चल जायेगा । तो ये सब तो दिखाना नहीं है इन पर बात नहीं करना है तकनीकी । इनको खाली है कि हमलोगों के काम को जो नीतीश जी के नेतृत्व में महागठबंधन काम कर रही है जनता के प्रति, बिहार के प्रति और ये जनता की मांग थी कि भाई महागठबंधन की सरकार बने और जरूरत थी, उसको देखते हुये बनी है । जनता के लिये काम करे तो केवल चरित्र हनन करना और मेन जो काम कर रहा है हमलोग 20 लाख नौकरी की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि देना शुरू कर दिये तो उसके बाद ये लोग जो हैं लगे पड़े हैं कि हमलोग काम न करें, डायवर्ट करें, दूसरे काम में लगे, उलझे रहें । इनको भी पता है कि कुछ नहीं है फिर भी । एक और शायरी हम कहना चाहेंगे । अब हम तो शुरू से ही देखते आ रहे हैं इतनी कम उम्र में सारा अनुभव हो गया । हर जगह का चाहे नेता विरोधी दल का हो, उप मुख्यमंत्री का हो या और भी तरह के सी0बी0आई0, ई0डी0, केस, मुकदमा, किस तरह का झुठ प्रचार । हर तरह से हम लड़ें, इनका मुकाबला किये तो हम इनको कहना चाहते हैं:

''वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं,
मैं अपने उम्र से कई साल बड़ा हूं ।''

तो इनके गीदड़ भभकी से हमलोग डरने वाले हैं क्या । पूर्णिया में तो हमलोग कह ही न रहे थे । अब विजय माल्या कौन है इनको नहीं याद आयेगा, मेहुल चौकसी कौन है इनको याद नहीं आयेगा, नीरव मोदी कौन है, ललित मोदी कौन है और फलां गुजराती भाई लोग कौन हैं याद नहीं न आयेगा । अभी जो 80

हजार करोड़ का घोटाला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बैठा दी इनका तोता निकल ही नहीं रहा है ।

(क्रमशः)

टर्न-28/राहुल/20.03.2023

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री (क्रमशः) : अब सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान लेकर कमेटी बैठा दी तो इनका तोता क्यों नहीं निकलता है महोदय । निकालना न चाहिए लेकिन वह घोटाला नहीं होगा । मेरी बहनों के ससुराल में जाकर के उनकी ननद का, उनके ससुराल के ससुराल वालों का गहना निलवा लेना फोटो खींच लेना । अब समझिये 25 जगह रेड पड़ी हर घर में घर खर्च के लिए अगर एक-दो लाख रुपया भी होता है तो 50 लाख तो ऐसे ही हो जाता है इसका क्या मतलब है तो इसलिए अब कान का, मंगलसूत्र निकलवाकर फोटो खींच लिये । महोदय, मेरे यहां आधे घंटे में ई0डी0 का काम खत्म हो गया था लेकिन ई0डी0 बैठी रही हम बोले अब काम खत्म हो गया पंचनामा बनाईये और जाइये तो बोले नहीं ऊपर से फोन आयेगा तब जायेंगे मनीष सिसोदिया जी के यहां 14 घंटे बैठे आप लोगों के यहां 15 घंटे बैठने का ऑर्डर है तो रात के एक-दो बजे वे लोग गये । मेरी बीवी गर्भवती है और इतना रूमर फैल गया कई तो बताते-बताते कि हमको बेटी हुई है, अच्छा है बेटी ही हो हम तो चाहेंगे कि पहले बेटी ही हो लक्ष्मी आये घर में लेकिन इतना रूमर फैला, मेरी बीवी गर्भवती है उसको इस टाईम पर बी0पी0 हाई होता है अब उसमें एक जगह 15-15 घंटे बैठाना खैर ये अलग बात है फिर बाद में हम लोगों ने उसको जबरन हॉस्पिटल भेजा और हेल्थ इशूज पर तो कार्रवाई रोक कर देखा जाता है लेकिन आप देखिये बहनों को ले आया गया है, मेरी बीवी को ले आया गया है इतनी निम्नस्तर की लड़ाई हो गयी है । महोदय, आडवाणी जी, अटल जी जब थे तो ऐसा माहौल नहीं था भले ही विचार में हम लोग अलग थे लेकिन यह तो अलग ही माहौल है ये तो पॉलिटिकल विंडिक्टिव से भी ज्यादा जो है एकदम पर्सनल हो गये ये लोग । कोई नया कुछ नहीं एक ही केस जो है तीन-चार बार जांच होकर के बंद कर दिया गया, जिसका पार्लियामेंट में भी जवाब दिया गया कि कुछ नहीं है । डी0ए0 केस हुआ हमारे पूरे परिवार पर जब डी0ए0 केस हम लोग सुप्रीम कोर्ट से जीत गये तब भी लगे पड़े हैं ये लोग लेकिन इन लोगों का सातिरपना चलने वाला नहीं है । जब लालू जी नहीं डरे तो लालू जी का बेटा भी डरने वाला नहीं है और हमारे पुरखे, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हमारे नेता के संघर्ष, साझी विरासत और वैचारिकी का खून मेरी रगों में दौड़ रहा है तो न डरने

का, न झुकने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता । महोदय, हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और जो है लड़ाई लड़कर जीतेंगे और ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं तो कहूंगा :

मैं हूं उसका, वो है मेरा,
बात है ठौर-ठिकाने की,
हमें क्या सदमा पहुंचेगा,
जब जनता हमारी यार बनी है । अध्यक्ष महोदय, जनता सब देख रही है और जनता हम लोगों के साथ है । इन लोगों के पास न कोई नेता है, न कोई विचार है, यह तो आप जान ही रहे हैं कि किस प्रकार का विचार है । ये लोग तो गांधी जी की पुण्यतिथि में जश्न मनाने वाले लोग हैं, ऐसे लोग जो बापू को भद्दी-भद्दी गालियां देते हैं । क्या नहीं करते हैं, असली निशाना तो वहां है खैर आर0एस0एस0 का जो एजेंडा है हम माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि सही समय पर इन्होंने जो निर्णय लिया, पूरा देश इनको देख रहा है बधाई दे रहा है कि सही निर्णय आपने लिया, सही समय पर निर्णय लिया और हम लोगों की कोशिश है कि सब लोग मिलजुलकर लड़ें, न हमको मुख्यमंत्री बनना है, न इनको प्रधानमंत्री बनना है । जहां हैं वहां खुश हैं । इनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं हमें खुशी है तो इसलिए काम करने से मतलब है । जनता को दिक्कतें जो आ रही हैं, समस्याएं जो आ रही हैं उनका समाधान करने से हम लोगों को मतलब है अपनी इच्छा क्या है । अब हमसे ज्यादा भाग्यशाली कौन होगा मेरे माता-पिता दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं, हम उप मुख्यमंत्री रहे, विपक्ष के नेता रहे और क्या चाहिए हमें लेकिन जो इन्होंने मौका दिया हमको, हमको इनके डिसिजन पर भी खरा उतरना है कि जो इन्होंने निर्णय लिया वह सही लिया, इनके लिए हम लड़ रहे हैं । कोई इधर-उधर से बातचीत करता है वह गलत बात न किया करे, तरह-तरह की बातें होती हैं, कोई कुछ भी करेगा जब हम इनके साथ खड़े हैं तो मजबूती के साथ खड़े हैं कोई डगमगा नहीं सकता । इन लोगों का सपना देखते रहिये अब टूटेगा महागठबंधन । सब जान न गये इन लोगों को, लकुवा मारा हुआ है अभी भी वह काटता है तो जलन होती है क्या कहते हैं उसको, वैसा हाल हो गया, बिसबिसाता है एकदम बिसबिसाये हुए लोग हैं तुरंत कूद-फांद कर रहे हैं कोई मतलब नहीं । बताओ सदन में बोले नेता विरोधी दल कि हम माफी मांगेंगे अगर तमिलनाडु वाली घटना गलत होगी, सारी जांच रिपोर्ट आ गयी कहां खड़े होकर के माफी मांगे, कोई शर्म नहीं है, उल्टा चोर कोतवाल को डाट रहा है । महोदय, यह स्थिति बनी हुई है तो क्या कहना इन लोगों का इनको यदुरप्पा, हेमंत बिसवा, नारायण राणे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय आदि इन लोगों को नहीं नजर आता है । इनके पास तो

वॉशिंग मशीन है न तुरंत आइये अपना दाग मिटाइये, एकदम चकाचक । यही काम में लगे हुए हैं तो खैर ये जहां जांच करनी चाहिए अडानी साहब की वहां हिम्मत नहीं है । बताइये पॉर्लियामेंट में लाईन काट दी गयी, इतनी मिनट तक साइलेंट रहे सब विपक्ष की आवाज को वहां भी दबाने की कोशिश की जा रही है । क्या हो रहा है तो आप देखियेगा महोदय कि हम गरीबों को आगे बढ़ायें तो भ्रष्टाचार, वो अमीरों को भगायें तो शिष्टाचार । यही फर्क है हम लोग गरीब को आगे बढ़ाने में लगे हैं तो भ्रष्टाचार हो जाता है वे लोग विजय माल्या जी, नीरव जी, चौकसी भाई और भी पता नहीं कौन-कौन कितना लोन लेकर भागे अमीरों को भगा दिये तो शिष्टाचार हो जाता है । वाह भाई । इस तरह का काम ये लोग करते हैं, नकारात्मक राजनीति करते हैं हम लोग विकास के साधक हैं वे लोग बाधक हैं, वे लोग कोई काम नहीं होने देना चाहते हैं लेकिन उन लोगों के कहने से क्या होगा हम लोग तो स्पेशल पैकेज के लिए लगातार मांग कर ही रहे हैं लेकिन देना नहीं देना तो केन्द्र सरकार के हाथों में है उनको निर्णय लेना है । महोदय, ज्यादा कुछ है नहीं फिर कल हमको स्वास्थ्य विभाग पर बोलना ही है तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे हम पुनः विभाग के सभी अधिकारी, पदाधिकारी, कर्मी, जितने हमारे अभियंता हैं, इंजीनियर्स हैं उनको धन्यवाद देते हैं और उनसे यही उम्मीद करते हैं कि ईमानदारी से...

अध्यक्ष : माननीय उपमुख्यमंत्री जी आप अपने वक्तव्य को प्रोसीडिंग का हिस्सा बनवा दीजिये।

श्री तेजस्वी प्रसाद यादव, उप मुख्यमंत्री : हम दिलवा देते हैं । महोदय, ज्यादा कुछ नहीं अंत में माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और आप सभी सदस्यों को हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोग हम लोगों का बल हैं, असली ताकत आप लोग हैं, आप लोग मजबूत रहते हैं, हौसला बढ़ाते हैं, हर एक परिस्थिति में आप लोग खड़े रहते हैं तो लड़ने का साहस और बढ़ता है । शकील साहब, वाह आप शायरी जो किये, हम भले ही छोटे हैं लेकिन आपने जो हौसला अफजायी किया उसके लिए आपको भी धन्यवाद देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि ईमानदारी से अपने काम को हम लोग करेंगे जनता के प्रति, बिहार को आगे बढ़ायेंगे और ज्यादा कुछ न कहते हुए आपकी अनुमति से अब मैं वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुमान मांग संख्या-41 के अधीन पथ निर्माण विभाग का 59,18,86,67,000 /- (उनसठ अरब अठ्ठारह करोड़ छियासी लाख सड़सठ हजार) रुपये की अनुदान मांग स्वीकृति हेतु सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा

हूं और सब लोगों से अनुरोध है कि सब सर्वसम्मति से इसको पारित करने का काम करें और माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव वापस लें ।

(माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग के भाषण का अंश- परिशिष्ट द्रष्टव्य)

अध्यक्ष : क्या माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं?

(माननीय सदस्य अनुपस्थित)

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''इस शीर्षक की मांग 10/- रुपये से घटाई जाय ।''

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ ।

अब मैं मूल प्रस्ताव को लेता हूं ।

अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि

''पथ निर्माण विभाग के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2024 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा, उसकी पूर्ति के लिए 59,18,86,67,000 /- (उनसठ अरब अठ्ठारह करोड़ छियासी लाख सड़सठ हजार) रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाय ।''

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मांग स्वीकृत हुई ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज दिनांक-20 मार्च, 2023 के लिये स्वीकृत निवेदनों की कुल संख्या-53 है, अगर सदन की सहमति हो तो इन्हें संबंधित विभाग को भेज दिया जाय ।

(सदन की सहमति हुई)

अब सभा की बैठक मंगलवार, दिनांक-21 मार्च, 2023 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक के लिये स्थगित की जाती है ।

XXX - आसन के आदेशानुसार इस अंश को विलोपित किया गया ।

---

1. वृहद जिला पथ – Major Districts Roads (MDR)

महोदय, पथ निर्माण विभाग के अधीन वर्तमान में कुल 15637 कि0मी0 वृहद जिला पथ है, जिसमें से 5531 कि0मी0 सिंगल लेन है, जिसे कम से कम इन्टरमीडिएट लेन में उन्नयन किया जाना है। इसमें से लगभग 2000 कि0मी0 पर कार्य किया जा रहा है। वर्ष 2023-24 में **272.00 कि0मी0** पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण की योजना नाबार्ड के तहत प्रस्तावित है। शेष पथों का भी चरणबद्ध तरीके से राज्य योजना से चौड़ीकरण किये जाने की योजना है।

2. राज्य उच्च पथ (State Highway)

2.1 महोदय, राज्य सरकार सभी राज्य उच्च पथों को 2-लेन मानक संरचना में उन्नयन हेतु दृढ़संकल्पित है। इस लक्ष्य के तहत वर्तमान में 3638 कि0मी0 राज्य उच्च पथों में से लगभग 2890 कि0मी0 का 2-लेन में उन्नयन किया जा चुका है तथा लगभग 325 कि0मी0 उन्नयन हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जिसका क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में प्रक्रियाधीन है।

2.2 एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से 1595 कि0मी0 राज्य उच्च पथों का 2-लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है तथा 202 कि0मी0 का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

2.3 ADB के वित्त पोषण से BSHP-III (Phase-2) के अन्तर्गत 6 राज्य उच्च पथों (i) मानसी-सिमरी बख्तियारपुर पथ (SH-95), (ii) कटिहार-बलरामपुर पथ (SH-98), (iii) वायसी-बहादुरगंज-दीघलबैंक पथ (SH-99), (iv) बेतिया-नरकटियागंज पथ (SH-105), (v) अम्बा-देव-मदनपुर पथ (SH-101) एवं (vi) मंझवे-गोविन्दपुर पथ (SH- 103) कुल लम्बाई 266.55 कि०मी० का ₹2680 35 करोड़ की लागत से 2 लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन हेतु स्वीकृत परियोजनाओं में से राज्य उच्च पथ सं०-99, 103 एवं

105 का कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। शेष राज्य उच्च पथों यथा SH- 95ए 98 एवं 101 की निविदा प्रक्रियाधीन है।

2.4 महोदय, BSHP-IV के अन्तर्गत ADB के वित्त पोषण से कुल ₹5153.11 करोड की अनुमानित लागत से 09 पथों (कुल लम्बाई-462.07 कि0मी0) एवं एक उच्चस्तरीय पुल के निर्माण कार्य हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के आर्थिक कार्य मंत्रालय द्वारा अनुशंसित कर ADB को भेजा गया है। ए0डी0बी0 के स्तर पर वित्त सम्पोषण हेतु इन योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। योजनाएँ है:-

- नवादा एवं गया जिलान्तर्गत बनगंगा-जेठियन-गहलौत-भिन्डस ;(NH-82) पथ (लम्बाई-41.6 कि0मी0, लागत-₹407.46 करोड़)
- बांका एवं भागलपुर जिलान्तर्गत धोरैया-इंगलिस मोड़-असरगंज पथ (लम्बाई-58 कि0मी0, लागत-₹595.78 करोड़),
- सुपौल एवं अररिया जिलान्तर्गत गणपतगंज-परवाहा ;(SH-92) पथ (लम्बाई-53 कि0मी0, लागत-₹644.04 करोड़),
- मधुबनी जिलान्तर्गत मधुबनी राजनगर-बाबूबरही-खुटौना पथ (लम्बाई-41.1 कि0मी0, लागत-₹511.07 करोड़),

- सीतामढी एवं मधुबनी जिलान्तर्गत सीतामढ़ी-पुपरी-बेनीपट्टी ;(SH-52) पथ (लम्बाई-51.35 कि0मी0, लागत-₹517.05 करोड़),
- सारण एवं सिवान जिलान्तर्गत छपरा-मांझी-दरौली-गुठनी पथ (लम्बाई-71.6 कि0मी0, लागत-₹684.22 करोड़),
- भोजपुर जिलान्तर्गत आरा-एकौना-खैरा-सहार पथ (लम्बाई-32.2 कि0मी0, लागत-₹322.35 करोड़),
- बक्सर जिलान्तर्गत ब्रहमपुर-कोरानसराय-इटाढ़ी-सरंजा-जालीपुर पथ (इटाढ़ी-बक्सर सम्पर्क मार्ग एवं उजियारपुर इंदौर सम्पर्क मार्ग सहित) (लम्बाई-80 कि0मी0, लागत-₹792.59 करोड़),
- मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत हथौड़ी-औराई पथ में एक उच्च स्तरीय पुल का पहुँच पथ सहित निर्माण कार्य (लागत-₹228.99 करोड़)
- दरभंगा एवं सीतामढ़ी जिलान्तर्गत अतरबेल-जाले-घोघराचट्टी (SH-97) पथ (लम्बाई-31.70 कि0मी0, लागत-₹449.56 करोड़)।

3. राष्ट्रीय उच्च पथ – (National Highway)

महोदय, बिहार राज्य के अन्तर्गत वर्तमान में कुल 5977 कि0मी0 राष्ट्रीय उच्च पथ है, जिसमें 3122 कि0मी0 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) एवं 2855 कि0मी0 MORTH के अधीन है।

3.1 भारतमाला परियोजना फेज-1 के अन्तर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण परियोजनाएँ सम्मिलित हैः-

(i) आमस - दरभंगा,

(ii) पटना - सासाराम,

(iii) पटना - अरेराज - बेतिया,

(iv) मुजफ्फरपुर - बेगुसराय,

(v) किशनगंज -बहादुरगंज एवं

(vi) चकिया- बैरगनिया

उपरोक्त वर्णित योजनाओं में किसी भी योजना का कार्य अभी प्रारंभ नहीं हो सका है। कुछ योजनाएँ भू-अर्जन की प्रक्रिया में तथा कुछ योजनाएँ निविदा की प्रक्रिया में है। आमस-दरभंगा का कार्य आवंटित हो चुका है।

3.2 भारतमाला परियोजना फेज-2 अन्तर्गत गोरखपुर - सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, रक्सौल - पटना - हल्दिया एक्सप्रेसवे का पटना तक विस्तारीकरण एवं पटना - पूर्णियाँ एक्सप्रेसवे पर मात्र सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त हुई है। वाराणसी - कोलकाता एक्सप्रेसवे के निर्माण हेतु निविदा प्रक्रियाधीन है।

3.3 राष्ट्रीय उच्च पथों के 4-लेनिंग के तहत पटना-गया-डोभी पथ, आरा-मोहनियाँ पथ, रजौली-बख्तियारपुर पथ, नरेनपुर-पूर्णियाँ पथ, मुंगेर-मिर्जा चौकी पथ, गलगलिया-अररिया पथ आदि का कार्य किया जा रहा है।

3.4 महोदय, राष्ट्रीय राजमार्ग के परियोजनाओं के क्रियान्वयन में राज्य सरकार द्वारा पूर्ण सहयोग किया जा रहा है। इसी क्रम में राष्ट्रीय उच्च पथ के मेगा परियोजनाओं में भू-अर्जन की समस्याओं का राज्य सरकार के विभिन्न स्तरो पर अनुश्रवण कर निदान किया जा रहा है। विशेष व्यवस्था के तहत इस हेतु एक भू-अर्जन कोषांग कार्यरत है, जिसमें मुख्य भू-अर्जन विशेषज्ञ एवं दो भू-अर्जन विशेषज्ञ के पदों का सृजन कराकर भू-अर्जन कार्य में तेजी लाई जा रही है। इतने सहयोग के बावजूद राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-19 (हाजीपुर - छपरा), राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-83 (पटना - गया - डोभी), राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-106 (बीरपुर - बिहपुर), राष्ट्रीय उच्च पथ संख्या-107 (महेशखुंट - सहरसा - मधेपुरा-

पूर्णियाँ), मुजफ्फरपुर रा0उ0प0-77 आदि के कार्य में प्रगति अपेक्षा के अनुरूप नहीं है। इस हेतु राज्य सरकार के द्वारा संबंधित बैठकों में भी भारत सरकार के पदाधिकारियों का ध्यान आकृष्ट कराया जाता है तथा भारत सरकार से लगातार पत्राचार भी किया जा रहा है।

उल्लेखनीय है कि उपरोक्त योजनाओं की धीमी गति के कारण इसकी लगातार समीक्षा माननीय उच्च न्यायालय, पटना के द्वारा भी की जा रही है।

4. वामपंथ उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना (RCPLWEA):

4.1 राज्य के अति वामपंथ उग्रवाद प्रभावित जिलों में सुगम आवागमन एवं विधि-व्यवस्था के दृष्टिकोण से ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 60(केन्द्रांश):40(राज्यांश) कॉस्ट शेयरिंग के आधार पर RCPLWEA Phase-I के तहत् राज्य के पाँच जिले औरंगाबाद, गया, बांका, जमुई एवं मुजफ्फरपुर में 64 अदद् पथ पैकेजों (कुल लम्बाई 1038 कि0मी0) एवं 39 पुल पैकेजों के निर्माण की स्वीकृति कुल ₹1228 83 करोड़ की लागत पर दी गई है। <u>इस परियोजना के तहत 988 कि0मी0 पथों एवं 31 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।</u>

RCPLWEA Phase-II के तहत् वर्ष 2019-20 में 50 अद्द पथ पैकेजों (कुल लम्बाई-589.66 कि0मी0) एवं 27 अदद् पुल पैकेजों के ₹1034.06 करोड़ की स्वीकृति उपरान्त 470 कि0मी0 पथों एवं 16 पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

<u>RCPLWEA Phase-III के तहत वर्ष 2021-22 एवं वर्ष 2022-23 में 39 अद्द पथ पैकेजों (कुल लम्बाई-353.18 कि0मी0) एवं 14 अदद् पुल पैकेजों की स्वीकृति कुल ₹508.04 करोड़ की लागत पर दी गई है। निविदा निस्तारण हो चुका है तथा 4 पैकेजों (गया-03 एवं जमुई-01) को छोड़कर अन्य सभी पैकेजों में कार्य प्रगति पर है।</u>

भारत नेपाल सीमा सड़क परियोजनाः

4.2 भारत-नेपाल सीमा परियोजना अन्तर्गत बिहार राज्य में कुल 552.29 कि.मी. में निर्माण कार्य किया जा रहा है। यह परियोजना सीमावर्त्ती सात जिलों यथा पश्चिमी चम्पारण, पूर्वी चम्पारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया तथा किशनगंज से गुजरता है जो पश्चिमी चम्पारण के मदनपुर से आरंभ होकर किशनगंज जिला के गलगलिया में समाप्त होता है।

इस पथ के निर्माण से सीमा पार शस्त्र एवं अन्य नशीले पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण के साथ-साथ सीमावर्त्ती इलाकों में सुगम यातायात की सुविधा प्रदान होगी जिससे इस क्षेत्र के आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा।

इस परियोजना में निर्माण कार्य का वित्तीय वहन गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा तथा भू-अर्जन, Utility Shifting एवं फॉरेस्ट क्लीयरेंस में आने वाले व्यय सहित <u>इस मार्गरेखण पर</u>

कुल 121 उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण राज्य सरकार के निधि से किया जा रहा है।

वर्तमान में 226.17 कि॰मी॰ पथ एवं 119 उच्चस्तरीय पुलों का निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। परियोजना के शेष कार्य को दिसम्बर 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

5. आर0ओ0बी0 – (R.O.B.)

5.1 महोदय, निर्बाध एवं सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने हेतु 15 ROB का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसमें से 11 ROB बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा एवं 4 ROB बिहार स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में भी कुल 13 ROB के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है एवं 3 ROB की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है।

5.2 इस वित्तीय वर्ष में स्वीकृत ROB में-

MOU के अन्तर्गत

- पूर्वी चम्पारण के मोतिहारी शहर में समपार संख्या-158 (जीवधारा - बापूधाम), समपार संख्या -160 (बापूधाम-मोतिहारी यार्ड) पर एवं समपार संख्या - 178 (सुगौली - मंझौलिया)
- पष्चिमी चम्पारण जिला में समपार संख्या-188 (मंझौलिया-बेतिया) पर,

- दरभंगा जिला में समपार संख्या- 21 (लहेरिया सराय - दरभंगा), समपार संख्या-2 Spl (दरभंगा - मोहम्मदपुर), समपार संख्या- 1 - 28 (दरभंगा - मोहम्मदपुर एवं दरभंगा - ककड़घट्टी),
- मधेपुरा जिला में समपार संख्या-90 (मधेपुरा यार्ड)
- सारण जिला में समपार संख्या-7 (छपरा कचहरी - मढ़ौरा)
- समपार संख्या - 9 Spl (बरौनी-तेघड़ा) पर ROB का निर्माण कार्य सम्मिलित है।

राज्य योजना अन्तर्गत स्वीकृत

- भागलपुर में मिर्जानहाट ब्रिज नं0-152 के स्थान परए
- पटना जिला में बख्तियारपुर इंजीनियरिंग कॉलेज के नजदीक,
- नालंदा जिला में हरनौत रेल फैक्ट्री के निकट समपार संख्या-10/C पर

6. केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि – (CRIF)

6.1 महोदय, केन्द्रीय सड़क अवसंरचना निधि (CRIF) के तहत राज्य में कुल 12 योजनाओं की स्वीकृति ₹1097.51 करोड़ की लागत से प्रदान की गई है, जो कार्यान्वित हैः-

- पटना जिलान्तर्गत मीठापुर-खगौल मेन रोड संख्या-1 से गोरया मठ, मीठापुर बी एरिया रोड (₹35.13 करोड़)
- पटना जिलान्तर्गत छितनावा (एन.एच. 30) उसरी-दानापुर-षिवाला बाईपास (₹137.62 करोड़)
- बक्सर जिलान्तर्गत इटाढ़ी-धनसोई पथ (₹38.31 करोड़)
- मधुबनी जिलान्तर्गत निधि चौक से रेलवे स्टेशन महावीर मंदिर चौक तक (₹31 18 करोड़) -
- गया जिलान्तर्गत एन0एच0-83 के अवशेष पथांश (₹149.81 करोड़)
- जहानाबाद जिलान्तर्गत एन.एच. 83 के अवशेष पथांश जहानाबाद बाईपास के प्रारंभ से अन्त तक पथ (₹99.84 करोड़)
- सिवान जिलान्तर्गत मैरवा-दरौली पथ (₹61 16 करोड़)

- मुजफ्फरपुर जिलान्तर्गत बुढ़ी गंडक नदी पर अखाड़ा घाट पुल के नजदीक उच्चस्तरीय पुल (₹69.58 करोड़) का निर्माण कार्य
- सारण जिलान्तर्गत रिविलगंज विशुनपुरा बाईपास पथ (₹228.53 करोड़)
- सारण जिला अन्तर्गत अमनौर बाजार बाईपास पथ (₹69.23 करोड़)
- गरखा बाईपास पथ (₹91 87 करोड़)
- परसा बाजार बाईपास पथ (₹85.24 करोड़)

• बिहार-झारखण्ड की सीमा पर रोहतास जिलान्तर्गत पण्डुका के पास सोन नदी पर ₹210 13 करोड़ की लागत से 1500 मीटर लम्बे उच्च स्तरीय आर0सी0सी0 पुल का निर्माण कार्य प्रगति में है।

7. सात निश्चय पार्ट-2 : सुलभ सम्पर्कता (Bypass / Elevated Road)

7.1 माननीय मुख्यमंत्री बिहार की समाधान यात्रा के संदर्भ में विभिन्न जिलों में आयोजित बैठकों के आलोक में यातायात को बेहतर व्यवस्थित ढंग से संचालन हेतु कई बाईपास के निर्माण की योजना प्रस्तावित है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं स्वीकृत भी हो चुकी है। इस योजना के क्रियान्वयन से राज्य के सभी शहरों एवं सघन बसावटों से होकर गुजरने वाले मार्गों में जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी तथा आवागमन सुगम होगा।

7.2 सात निश्चय पार्ट-2: वर्ष 2021-22 में सुलभ सम्पर्कता के तहत कुल स्वीकृत 8 बाईपास (₹143.16 करोड़) की योजनाएँ कार्यान्वित कराई जा रही है तथा वर्ष 2022-23 में स्वीकृत 11 बाईपास (₹313.74 करोड़) की योजनाओं की निविदा प्रक्रियाधीन है।

7.3 वर्ष 2023-24 में (6 बाईपास) दरभंगा जिलान्तर्गत बहेड़ी बाईपास, भोजपुर जिलान्तर्गत चँदवा से धनुपरा बाईपास, खगड़िया जिलान्तर्गत नगर सुरक्षा बांध बाईपास, गया जिलान्तर्गत गुरूआ बाईपास, किशनगंज जिलान्तर्गत बहादुरगंज बाईपास, सारण जिलान्तर्गत मशरख बाईपास प्रस्तावित है।

8. नाबार्ड सम्पोषित – (NABARD)

8.1 महोदय, राज्य के चहुँमुखी विकास को ध्यान में रखते हुए सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को तीव्र एवं सुगम बनाने के निमित पथ निर्माण विभाग द्वारा नाबार्ड ऋण अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में कुल 20 पथों (लम्बाई 259 43 कि0मी0 एवं लागत ₹718 69 करोड़) के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण तथा कुल 18 अदद् पुल/पुलिया (लागत ₹103 42 करोड़) के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई, जिसका क्रियान्वयन विभिन्न चरणों में है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में नाबार्ड ऋण के तहत लगभग ₹1850 करोड़ से अधिक की कुल 41 (25 पथ योजना एवं 16 पुल योजना) योजनाओं की स्वीकृति प्रक्रियाधीन है। इसके अन्तर्गत कुल 272.62 कि0मी0 वृहद जिला पथों के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण का कार्य प्रस्तावित है। इसके निर्माण के फलस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा तथा सरकार की अन्य सुविधाओं का लाभ ग्रामीणों तक सुगमता से पहुँचाया जा सकेगा। इनमें प्रमुख योजनाएँ हैंः:-

- नालन्दा जिलान्तर्गत नूरसराय - राजगीर ग्रीनफिल्ड पथ (₹862 करोड़),

- पटना जिलान्तर्गत लोदीपुर से पैनाल भाया गोपालपुर पथ (₹50 करोड़),
- मनेर से हल्दी छपरा भाया हाथी टोला पथ (₹40 करोड़),
- दरभंगा जिलान्तर्गत करेह नदी पर हायाघाट के पास बने पुल से इनमाईत ढाला तक पुल का निर्माण (₹80 करोड़),
- भोजपुर जिलान्तर्गत आरा-छपरा के बीच वीर कुंवर सिंह सेतु के पहुँच पथ का निर्माण कार्य (₹90 करोड़)
- रोहतास जिलान्तर्गत अकबरपुर - अधौरा पथ (₹118 करोड़)
- सीवान जिलान्तर्गत आन्दर - तीयर पथ में गंडक नहर के उपर सीवान-सिसवन पथ तक का कार्य (₹90 करोड़)
- लखीसराय जिलान्तर्गत पचना रोड - लखीसराय - शेखपुरा पथ (₹65 करोड़)
- सुपौल जिलान्तर्गत बी0एस0एस0 कॉलेज परसरमा से चैनसिंहपट्टी पथ
- समस्तीपुर जिलान्तर्गत सरायरंजन से ककड़घट्टी पथ (₹35 करोड़)
- सीतामढ़ी जिलान्तर्गत पुपरी से चोरौत पथ का निर्माण कार्य (₹70 करोड़) आदि सम्मिलित है।

9. केन्द्र सरकार द्वारा महत्वपूर्ण पुल परियोजनाएँ-

- गंगा नदी पर बक्सर में 2-लेन अतिरिक्त पुल (निर्माणाधीन)
- शेरपुर - दिघवारा के बीच गंगा नदी पर 6-लेन पुल (निविदा की प्रक्रिया में)
- जे0पी0 सेतु के समानान्तर 6-लेन पुल (स्वीकृति की प्रक्रिया में)
- महात्मा गाँधी सेतु के समानान्तर 4-लेन पुल (निर्माणाधीन)
- औटा-सिमरिया के बीच गंगा नदी पर राजेन्द्र सेतु के समानान्तर 6-लेन पुल (निर्माणाधीन)
- विक्रमशीला सेतु के समानान्तर गंगा नदी पर 4-लेन पुल (कार्य आवंटित)
- मनिहारी - साहेबगंज के बीच गंगा नदी पर 4-लेन पुल (निर्माणाधीन)
- कोशी नदी पर एन0एच0-106 फुलौत घाट पर 4-लेन पुल (निर्माणाधीन)
- कोशी नदी पर भेजा-बकौर के बीच 2-लेन पुल (निर्माणाधीन)
- गंडक नदी पर डुमरियाघाट स्थित 2-लेन पुल (निर्माणाधीन)

➢ हाजीपुर - छपरा के बीच सोनपुर घाट स्थित 2-लेन पुल (निर्माणाधीन)

9.1 केन्द्र सरकार की अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाएँः:

➢ पटना रिंग रोड के मार्गरेखन पर गंगा नदी पर शेरपुर-दिघवारा के बीच 6-लेन सेतु निर्माण

➢ दानापुर - बिहटा एलिवेटेड पथ का निर्माण

➢ बख्तियारपुर - मोकामा तक 4-लेन उन्नयन कार्य।

➢ औटा - सिमरिया में गंगा नदी पर राजेन्द्र सेतु के समानान्तर 6-लेन पुल का निर्माण।

➢ भेजा - बकौर के बीच कोशी नदी पर पुल का निर्माण।

➢ मेहरौना - सीवान पथ (राम जानकी मार्ग) का निर्माण।

10. प्रमुख नदियों पर पुलों का निर्माण

10.1 महोदय, राज्य अन्तर्गत पूरब से पश्चिम एवं उत्तर से दक्षिण निर्बाध एवं सुगम आवागमन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार द्वारा राज्य की प्रमुख नदियों पर पुलों का नेटवर्क तैयार किया गया है।

- गंगा नदी पर राज्य सरकार द्वारा आरा -छपरा को जोड़ने वाली वीर कुँवर सिंह 4-लेन सेतु का निर्माण कर आवागमन के लिए चालू है। 21 00 कि0मी0 के च्फब् पहुँच पथ की योजना तैयार की गई है जिससे सुगम यातायात सुनिश्चित हो सके।
- गंगा नदी पर राज्य सरकार द्वारा तीन नये पुलों का निर्माण कार्य प्रगति में है -कच्ची दरगाह - बिदुपुर के बीच 6-लेन पुल, सुल्तानगंज-अगुवानी घाट 4-लेन पुल, बख्तियारपुर-ताजपुर में 4-लेन पुल।
- कोशी नदी पर राज्य सरकार द्वारा विजयघाट, बलुआहा घाट एवं गण्डौल-बिरौल के बीच निर्मित पुलों पर आवागमन चालू है।

- मानसी - हरदी चौघड़ा पथ (एस0एच0-95) में कोशी नदी पर उच्च स्तरीय पुल का निर्माण स्वीकृत है। निविदा की कार्रवाई की जा रही है।
- गंडक नदी पर धनहा-रतवल पुल, गोपालगंज-बेतिया के बीच विशनपुर पुल, सत्तरघाट पुल, बंगराघाट पुल का निर्माण कार्य किया गया है एवं इन पुलों से आवागमन चालू है। सत्तरघाट पुल में अतिरिक्त वाटर-वे प्रदान करने के लिए लगभग 984 मीटर लम्बाई में नये उच्च स्तरीय पुल का निर्माण किया जा रहा है।

धनहा-रतवल पुल के रतवल साईड पहुँच पथ का मजबूतीकरण कार्य किया जाना प्रस्तावित है।

- सोन नदी पर अरवल-सहार तथा दाउदनगर-नासरीगंज के बीच राज्य सरकार द्वारा निर्मित 4-लेन पुल पर आवागमन चालू है। सोन नदी पर पण्डुकाघाट में नये पुल का निर्माण कार्य किया जा रहा है।
- इसके अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न नदियों पर अनेकों पुल का निर्माण कराकर राज्य में निर्बाध आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है।

11. अन्य महत्वपूर्ण आधारभूत ढाँचे का विकास – (Infrastructural Development)

11.1 जे0पी0 गंगा पथ

- पटना शहर में सुगम यातायात के दृष्टिगत शहर के पष्चिमी भाग (दीघा) से पूर्वी भाग (दीदारगंज) को सुलभ सम्पर्कता प्रदान करने हेतु महत्वाकांक्षी जे0पी0 गंगा पथ परियोजना की शुरूआत की गई है। कुल ₹3831.00 करोड़ की लागत से 20 500 कि0मी0 की इस परियोजना का कार्य प्रगति पर है। इस परियोजना हेतु ₹2441.00 करोड़ का वित्त पोषण हुडको से तथा शेष ₹1390.00 करोड़ का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। परियोजना क्रियान्वयन के क्रम में गंगा नदी के बहाव की प्रवृति पटना शहर की तरफ की संभावना को दृष्टिगत आई0आई0टी0 रूड़की के विषेषज्ञ दल द्वारा अध्ययन कराया गया एवं प्राप्त सुझाव के अनुरूप गायघाट से दीदारगंज तक पथ तटबंध संरचना के बदले एलिवेटेड संरचना निर्माण करने का निर्णय लिया गया।

- दीघा से पी0एम0सी0एच0 पथांष (7.400 कि0मी0) का लोकार्पण दिनांक 24.06.2022 को किया गया है। द्वितीय चरण अर्थात् पी.एम.सी.एच. से गायघाट (4.700 कि0मी0) जून 2023

तक एवं गायघाट से पटना घाट (4.500 कि0मी0) तक सितम्बर 2023 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

- दीघा से दीदारगंज तक (20.500 कि0मी0) दिसम्बर 2023 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित है। इस परियोजना को पटना के यातायात व्यवस्था को सुगम करने के साथ-साथ मनोरंजन स्थल के तौर पर विकसित करने का प्रस्ताव है। जे0पी0 गंगा पथ के दीघा से ए0एन0 सिन्हा संस्थान तक के पथांश में रिभर फ्रंट डेवलपमेंट एवं सौंदर्यीकरण की योजना पर विभाग कार्य कर रहा है।

- आगामी चरण में इस पथ को दीघा से पश्चिम शेरपुर तक एवं पूरब में दीदारगंज से बख्तियारपुर तक विस्तारित करने की योजना है। इस हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है।

11.2 कच्ची दरगाह से बिदुपुर के बीच 6-लेन न्यू गंगा पुल

- एशियन डेवलपमेंट बैंक के वित्त पोषण से राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 30 स्थित कच्ची दरगाह से राष्ट्रीय उच्च पथ सं0 103 स्थित बिदुपुर के बीच 6-लेन ग्रीनफिल्ड पुल परियोजना (₹4988.40 करोड़) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पुल की लम्बाई 9.76 कि0मी0 एवं पहुँच पथ की लम्बाई 10.00 कि0मी0 है। अभी तक लगभग 60 प्रतिशत से अधिक का कार्य किया जा चुका है।

सबलपुर से राघोपुर तक (4.50 कि0मी0) का कार्य दिसंबर, 2023 तक पूर्ण कर राजधानी पटना से राघोपुर की सम्पर्कता सुनिश्चित हो जायेगी। इस परियोजना के क्रियान्वयन के दौरान उत्पन्न जटिलताओं का निराकरण कर लिया गया है। सभी कार्य को दिसंबर, 2024 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है।

- इस पुल के निर्माण से उत्तर बिहार से दक्षिण बिहार की अतिरिक्त संपर्कता हो जायेगी। यह परियोजना पटना रिंग रोड का भी हिस्सा है तथा पटना-बख्तियारपुर 4-लेन पथ के जंक्शन पर निर्बाध परिचालन हेतु Trumpet संरचना का भी निर्माण किया जा रहा है।

- राघोपुर दियारा क्षेत्र का आर्थिक एवं व्यवसायिक विकास के मद्देनजर दियारा क्षेत्र में पथ नेटवर्क सहित राघोपुर रिंग रोड सह सुरक्षा बांध (60.69 कि0मी0) निर्माण की योजना है। इसके निर्माण पर लगभग ₹1600.00 करोड़ रुपये की लागत संभावित है।

11.2 बख्तियारपुर-ताजपुर के बीच गंगा नदी पर पहुँच पथ के साथ पुल परियोजना-

राज्य में जन निजी भागीदारी के अन्तर्गत राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-31 के प्रस्तावित बाईपास में करजान गाँव से राष्ट्रीय उच्च पथ सं०-28 में ताजपुर को जोड़ने वाली गंगा नदी पर कुल ₹1602.74

करोड़ रूपये की लागत पर 5.550 कि०मी० लम्बाई का 4-लेन पुल एवं 45.393 कि०मी० 4-लेन पहुँच पथ की योजना स्वीकृत है। विगत तीन वर्षों से रियायतग्राही (Concessionaire) की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण कार्य बाधित था। बिहार में पहली बार OTFI (One Time Fund Infusion) पद्धति का उपयोग कर जन-निजी-भागीदारी के इस परियोजना का पुनरूद्धार किया गया है। इसके तहत परियोजना के शेष कार्य को पूर्ण करने हेतु ₹935.775 करोड़ का OTFI राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस परियोजना में कार्य समाप्ति के पश्चात् Toll से प्राप्त आय के बँटवारा हेतु Water Fall Mechanism का इस्तेमाल किया जाएगा जिसके तहत First Charge on Toll का अधिकार Lender Bank को, इसके बाद राज्य सरकार एवं अन्त में Concessionaire का रहेगा। पूरक / त्रिपक्षीय एकरारनामा की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है एवं कार्य को 30 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य है।

11.4 मीठापुर से रामगोविन्द सिंह महुली हॉल्ट तक पथ का निर्माण-

राज्य योजना मद अन्तर्गत मीठापुर से रामगोविन्द सिंह महुली हॉल्ट तक 8.86 कि0मी0 लंबे 4-लेन एलीभेटेड पथ का निर्माण कार्य ₹1030.586 करोड़ रू0 की लागत से प्रगति पर है। इस पथ के बन जाने से पटना के दक्षिण भाग से राजधानी आने-जाने में

ट्रैफिक सिग्नल मुक्त संपर्कता स्थापित होगी। द्वितीय चरण में मीठापुर से सिपारा तक NH-30 के ऊपर 4-लेन का निर्माण प्रस्तावित है।

11.5 कारगिल चौक से साईन्स कॉलेज तक डबल डेकर एलिवेटेड कोरिडोरः

पटना शहर अन्तर्गत गाँधी मैदान के कारगिल चौक से साईन्स कॉलेज, पटना तक अशोक राजपथ में सुगम यातायात हेतु डबल डेकर एलिवेटेड कोरिडोर का निर्माण कार्य प्रगति में है, जिसकी लम्बाई 2.20 कि0मी0 एवं लागत ₹422.00 करोड़ है। पी0एम0सी0एच0 से इस कोरिडोर की सम्पर्कता हेतु डबल डेकर के दोनों स्तर से रैम्प का प्रावधान किया गया है। इस कार्य को दिसम्बर, 2024 तक पूर्ण किये जाने का लक्ष्य है।

11.6 लोहिया पथ चक्रः

पटना शहर अन्तर्गत पटना उच्च न्यायालय से पटेल भवन तक नेहरू पथ में विभिन्न जंक्शन पर यातायात का निर्बाध परिचालन सुनिश्चित करने हेतु लोहिया पथ चक्र की स्वीकृति कुल ₹391.48 करोड़ की लागत से की गई है। प्रथम चरण में ललित भवन के पास निर्मित संरचना पर नवम्बर 2021 से यातायात चालू है। द्वितीय चरण में हड़ताली चौक स्थित संरचना का निर्माण कार्य प्रगति में है जिसे जून 2023 तक पूर्ण करने का

लक्ष्य है। इसके निर्माण के फलस्वरूप बोरिंग कैनाल रोड, दारोगा राय पथ, अटल पथ एवं नेहरू पथ जंक्शन पर सिग्नल रहित यातायात का परिचालन सुनिश्चित होगा।

12.<u>नई तकनीक का अभिनव प्रयोग–</u>

<u>(Latest Technology)</u>

13.1 महोदय, पथ निर्माण विभाग अच्छी सड़कों के निर्माण के साथ-साथ उसके उत्कृष्ट संधारण हेतु नये-नये तकनीक का उपयोग कर रहा है। इसी क्रम में विभाग द्वारा **OPRMC प्रथम चरण** (वर्ष 2013-18) के सफल क्रियान्वयन के पश्चात् OPRMC द्वितीय चरण (वर्ष 2019-25) में **13064 कि0मी0** पथों का 7 वर्षों के लिए संधारण किया जा रहा है।

- विभागीय पथों के उत्कृष्ट संधारण के लिए साक्ष्य आधारित विस्तृत एवं सटीक अनुश्रवण हेतु एक नई एवं बेहतर व्यवस्था पथ संधारण ऐपतथा मुख्यालय स्थित कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर (Control and Command Centre) की स्थापना की गई है जिसमें मोबाईल ऐप के माध्यम से पथ की खराबियों का वास्तविक काल (real time) अनुश्रवण के साथ-साथ क्षेत्रीय अभियंताओं द्वारा निर्धारित निरीक्षण चक्र सुनिश्चित कराया जा रहा है। सभी पथों में पाये जा रहे कमियों का आँकड़ा संकलित किया जाता है ताकि बार-बार खराब होने वाले पथों को OPRMC से विलोपित कर विस्तृत तकनीकी जाँच के आधार पर

मजबूतीकरण की कारवाई की जा सके। इस नूतन व्यवस्था से पथों के रख-रखाव में काफी सुधार आया है। इसी क्रम में विभाग द्वारा 28 अक्टूबर 2022 को पॉटलेस दिवस के रूप में घोषित करते हुए सभी पथांशों को छठ से पूर्व पॉटलेस करने का लक्ष्य प्राप्त किया गया।

- इस अभिनव तकनीक के अध्ययन हेतु कोलकाता स्थित आस्ट्रेलियन वाणिज्यिक दूतावास के सदस्यगण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष एवं अन्य राज्यों यथा उड़ीसा एवं उत्तर प्रदेश के वरीय अभियंताओं के दल द्वारा कन्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेन्टर का भ्रमण किया गया।

- पटना शहर के अन्तर्गत विभिन्न फ्लाईओवर, महत्वपूर्ण पुलों एवं मुख्य मार्गों पर सजावटी रोशनी एवं प्रकाश की व्यवस्था की गयी है।

13. नई नियुक्तियाँ –(Recruitment)

13.1 महोदय, पथ निर्माण विभाग के कार्य संस्कृति में बदलाव एवं विगत वर्षों से हासिल किये गये उपलब्धियों में विभागीय अभियंताओं का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। विगत एक वर्ष में 248 सहायक अभियंताओं की नियुक्ति बिहार लोक सेवा आयोग के अनुशंसा के आधार पर एवं 33 कनीय अभियंताओं की नियुक्ति बिहार तकनीकी सेवा आयोग के अनुशंसा पर की गई है।

31 सहायक अभियंता (असैनिक) की नियुक्ति हेतु बिहार लोक सेवा आयोग को अनुशंसा भेजी गई है। विभागीय अनुशंसा के आलोक में 463 कनीय अभियंता(असैनिक), 62 कनीय अभियंता (यांत्रिक) एवं 10 कनीय अभियंता (विद्युत) की नियुक्ति हेतु बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा कार्रवाई की जा रही है।

14. सड़क सुरक्षा – (Road Safety)

14.1 पथ निर्माण विभाग द्वारा सड़कों पर दुर्घटनाओं के रोकथाम के लिये पथों का सड़क सुरक्षा अंकेक्षण (Road Safety Audit) का कार्य लगातार किया जा रहा है तथा सड़कों का संरचनात्मक सुधार एवं सड़क सुरक्षा उपायों को क्रियान्वित किया जा रहा है। इसके तहत राज्य सरकार द्वारा अबतक कुल 159 ब्लैक स्पॉट पर संरचनात्मक सुधार कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त सभी पथों में सड़क सुरक्षा अंकेक्षण के सभी सुझावों यथा- जंक्शन उन्नयन, दुर्घटना प्रबल स्थानों पर यातायात शांत करने के उपाय, रोड साईनेज, रोड मार्किंग, जेब्रा क्रॉसिंग, गति सीमा संकेतक चिन्ह एवं रम्बल स्ट्रीप आदि का प्रावधान किया जा रहा है ताकि दुर्घटनाओं एवं उससे होने वाली क्षति को न्यूनतम किया जा सके। वाहनों के तीव्र गति को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग के द्वारा मोबाईल स्पीड रडार गन की व्यवस्था जे0पी0 गंगा पथ में की गयी है।

15. प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध – (Training, Testing & Research)

15.1 प्रशिक्षण, परीक्षण एवं शोध संस्थान का मूल उद्देश्य पथ निर्माण विभाग अन्तर्गत चल रही योजनाओं में उच्च गुणवत्ता स्थापित करना एवं अभियंताओं को आधुनिकताम तकनीकी का प्रशिक्षण प्राप्त करवाना है। राज्य प्रशिक्षण नीति के तहत कनीय अभियंताओं से मुख्य अभियंता स्तर तक के पदाधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण यथा- Induction Course, Orientation Course एवं Refresher Course का आयोजन वाल्मी पटना में किया जाता है। साथ ही देश के प्रतिष्ठित प्रशिक्षण संस्थानों यथा- CRRI-New Delhi, ASCI- हैदराबाद IAHE-Noida, NICMAR-Pune एवं IIT जैसे संस्थानों में लगातार कई वर्षों से विभाग के अभियंताओं को प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है एवं Webinar के माध्यम से भी अभियंताओं का ज्ञान संवर्द्धन कराया जा रहा है। विगत वर्ष अप्रैल 2022 से दिसम्बर 2022 तक देश के ख्याति प्राप्त संस्थानों/संस्थानों के विशेषज्ञों द्वारा 18 Online/Offline प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत मुख्य अभियंता

से कनीय अभियंता स्तर के कुल 613 अभियंताओं को प्रशिक्षण कराया गया। इसके अतिरिक्त अभियंत्रण एवं पोलिटेक्निक संस्थानों में अध्ययनरत कुल 380 छात्र/छात्राओं को Internship/ Inplant Training/Industrial Training/Vocational Training के तहत पथ निर्माण विभाग के विभिन्न प्रमंडलों, BRPNNL, BSRDCL एवं परीक्षण एवं शोध संस्थान से प्रशिक्षण कराया गया।

15.2 माह अप्रैल 2022 से माह दिसम्बर 2022 तक परीक्षण एवं शोध संस्थान, पटना के द्वारा उड़नदस्ता प्रमंडलों एवं अन्य से प्राप्त नमूनों में कुल 115 बिटूमिनस एवं 66 नन बिटूमिनस नमूनों के जाँच को संपादित किया गया। इस संस्था के द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के निरूपण आदि हेतु आवश्यक जाँच भी संपादित किए जाते हैं।

इनके द्वारा BIS/IRC/MORT&H द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप जाँच कार्य सम्पन्न किया जाता है। विभाग के अधीन निर्माणाधीन कार्यों की गुणवत्ता जाँच हेतु त्रि-स्तरीय व्यवस्था स्थापित है, जिसमें प्रथम स्तर पर संबंधित प्रमंडल की गुण नियंत्रण ईकाई, द्वितीय स्तर पर क्षेत्रीय गुण नियंत्रण ईकाई के रूप में अंचल स्तरीय उड़नदस्ता दल और तृतीय स्तर पर मुख्यालय स्थित चार उड़नदस्ता प्रमंडल कार्यरत है। मुख्यालय स्तर पर प्राप्त शिकायतों/परिवादों के आलोक में एवं निदेशानुसार

कार्यरत योजनाओं में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु प्रत्येक उड़नदस्ता प्रमंडलों द्वारा पथों का औचक निरीक्षण एवं जाँच सुनिश्चित की जाती है। इनके द्वारा मंत्रिमंडल निगरानी विभाग, तकनीकी परीक्षक कोषांग के निदेशों के आलोक में जाँच कार्य सम्पन्न किया जाता है।

उड़नदस्ता जाँच दल से प्राप्त जाँचफल की समीक्षा हेतु विभाग में दो समिति यथा मुख्यालय स्तर पर मुख्य अभियंता (अनुश्रवण) की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय उड़नदस्ता जाँच मूल्यांकन समिति एवं दूसरी मुख्य अभियंता (संबंधित) की अध्यक्षता में त्रिसदस्यीय क्षेत्रीय उड़नदस्ता जाँच मूल्यांकन समिति गठित है। इसके अतिरिक्त मुख्यालय स्तर पर तकनीकी पहलूओं की समीक्षा हेतु अभियंता प्रमुख की अध्यक्षता में सात सदस्यीय तकनीकी समिति भी गठित है।

विभाग में पारदर्शिता हेतु इन जाँच प्रतिवेदनों को जन-साधारण के अवलोकन के प्रयोजन से सार्वजनिक डोमेन में प्रदर्शित किया जा रहा है।

15.3 विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप सड़कों एवं पुलों के निर्माण में नवीनतम तकनीक से अवगत कराने के उद्देश्य से बिहार सड़क शोध संस्थान की स्थापना प्रक्रियाधीन है।

पथ निरूपण, निर्माण, संधारण, सड़क सुरक्षा, नई तकनीक का उपयोग, अभियंताओं को विश्वस्तरीय मानक प्रशिक्षण, waste material का निर्माण कार्यों में उपयोग, तमबलबसपदह तकनीक इत्यादि क्षेत्र में इस संस्थान द्वारा अग्रणी भूमिका निभायी जायेगी।